लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खंड 39, 1965/1886 (शक)

Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalguna 12 to 25, 1886 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886–87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं]

[Vol. XXXIX contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 14—सोमवार 8 मार्च, 1965/1 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
302	विमान दुर्घटनायें	1189—91
303	भारत और पाकिस्तान के गृह-मंत्रियों का सम्मेलन	1191—95
304	भारत-लंका करार	1195—96
305	मिग विमान परियोजना	1196—1202
306	पाकिस्तानी सेना का जमाव	1202—05
307	देश में रोजगार की स्थिति	1206—08
308	प्रधान मंत्री के साथ उद्योगपतियों की भेंट	1208—10
309	द्वितीय अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन	1210—12

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
310	सार्वजनिक रेडियो सैट	1212
311	मजगांव नौ-स्थानों का आधुनिकीकरण	1213
312	संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना	1214
313	विदेशों में प्रचार	1215
314	नेहरू स्मारक निधि के लिए मनीआर्डर कमीशन	1215—16
315	भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रमुख	1216
316	अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह दिल्ली	1216—17
317	चीन द्वारा हिमालय संघ की रचना	1217
318	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	1217—18
319	नेफा में औद्योगिक विकास की सम्भावना	1218
320	उपभोक्ता मूल्य देशनांक	1218—19
321	युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	1219
322	चीनी हथियारों का पाकिस्तान ले जाया जाना	1219—20
323	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के निकट चीन की नौकायें	1220
324	पाकिस्तान में हाल में हुए चुनाव	1221

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 14—*Monday, March* 8, 1965/*Phalguna* 17, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
302.	Air Crashes	1189—91
303.	Indo-Pakistan Home Minister's Conference	1191—95
304.	Indo-Ceylon Agreement	1195—96
305.	M. I. G. Project	1196—1202
306.	Concentration of Pak. Forces	1202—05
307.	Employment situation in the Country	1206—08
308.	Industrialists meeting with Prime Minister	1208—10
309.	Second Afro-Asian Conference	1210—12

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
310.	Community Listening Sets	1212
311.	Modernisation of Mazagaon Docks	1213
312.	Pak. Firing on U.N. Observers	1214
313.	External Publicity	1215
314.	M.O. Commission for Nehru Memorial Fund	1215-16
315.	Heads of Indian Diplomatic Missions	1216
316.	International Film Festival, Delhi.	1216-17
317.	Creation of Himalayan Federation by China	1217
318.	Rehabilitation of Ex-Service men	1217-18
319.	Industrial Potential in NEFA	1218
320.	Chinese boats near Andaman and Nicobar	1218-19
321.	Violations of Cease-fire Line	1219
322.	Movement of Chinese arms to Pakistan	1219-20
323.	Chinese boats near Andaman and Nicobar Islands	1220
324.	Recent Elections in Pakistan	1221

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
325	राजनयिक पदों पर नियुक्तियां	1221–22
326	जम्मू और काश्मीर पर संवैधानिक उपबन्धों का लागू किया जाना	1222
327	इन्डोनेशिया मलयेशिया विवाद . . .	1223
328	विदेशों में भारतीय मिशन	1223–24
329	अल्पकालीन सेवा के लिए भर्ती	1224
330	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जान ।	1224
331	बर्मा से भारतीयों की वापसी . .	1225
अतारांकित प्रश्न संख्या		
735	लंदन में भारतीय दूतावास के कर्मचारी .	1225–26
736	रेडियो व्यय को तार व्यय के साथ मिलाना	1226–27
737	लोक नर्तकों के लिये पुरस्कार . .	1227
738	स्वतंत्रता दिवस पर व्यय .	1227
739	बिना लाइसेंस के रेडियो . . .	1227–28
740	भारत-अरब सम्बन्धों पर गोष्ठी . . .	1229
741	नौसेना के जहाज का दुर्घटनाग्रस्त होना . . .	1229
742	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में गबन . . .	1230
743	उदवभरक प्रणाली	1230
744	अन्तर्देशीय पत्र और विदेशों के लिये हवाई डाक पत्र . .	1230–31
745	नई दिल्ली में नया हवाई अड्डा . . .	1231
746	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश	1231
747	प्रबन्ध में मजदूरों का प्रतिनिधित्व . . .	1231–32
748	हिन्द महासागर में परमाणु अस्त्रों से लैस जहाज .	1232
749	आर्मी रिज़र्विस्ट्स की पेंशन . . .	1232
750	भारतीय उच्चायोग, पाकिस्तान में द्वितीय सचिव .	1233
751	अरब फिल्म समारोह . . .	1233
752	कलकत्ता में इन्दोनेशिया का वाणिज्य दूतावास .	1234
753	काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक . .	1234
754	ग्रामीण रोजगार दफ्तर	1235
755	दिल्ली में टेलीफोन	1235
756	सेवा-नियुक्त सैनिकों के लिये नौकरियां . . .	1235–36

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
325.	Appointments to Diplomatic Posts	1221–22
326.	Extension of Constitutional Provisions to Jammu and Kashmir	1222
327.	Indonesia-Malayasia dispute	1223
328.	Indian Missions Abroad	1223–24
329.	Short Service Recruitments	1224
330.	Firing by Pak. Troops	1224
331.	Repatriation of Indians from Burma	1225
Unstarred Question Nos.		
735.	Employees in Indian High Commission, London	1225–26
736.	Amalgamation of Radio Expenses with Telegraph Expenses	1226–27
737.	Prizes for Folk Dances	1227
738.	Expenditure on Independence Day	1227
739.	Pirate Radios	1227–28
740.	Seminar on Indo-Arab Relations	1229
741.	Naval Aircraft Crash	1229
742.	Misappropriation in Delhi Telephone District.	1230
743.	Stevedore System	1230
744.	Inland Letters and Foreign Aerogrames	1230–31
745.	New Aerodrome in New Delhi.	1231
746.	Earned Leave to Industrial Employees in Defence Establishments	1231
747.	Workers participating in Managements	1231–32
748.	Nuclear Armed Ships in Indian Ocean	1232
749.	Pensions of Army Reservists	1232
750.	Second Secretary of Indian High Commission, Pakistan	1233
751.	Arab Film Festival	1233
752.	Indonesian Consulate in Calcutta	1234
753.	U. N. Observers in Kashmir	1234
754.	Rural Employment Bureaus	1235
755.	Telephones in Delhi	1235
756.	Employment for Retired Soldiers	1235

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
757	सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार	1236
758	स्वर्गीय पं० नेहरू के जीवन सम्बन्धी प्रदर्शनी	1236–37
759	बोनस विधेयक	1237–38
760	मछेरों के शवों को निकालने के लिये श्री लंका सरकार की प्रार्थना	1238
761	लोक-सभा की बैठकें	1238–39
762	भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा का विलय	1239
763	गश्त लगाने वाली अमरीकी परमाणु पनडुब्बियां	1240
764	परमाणु हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी शिखर सम्मेलन	1241
765	संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मसला	1241–42
766	दिल्ली में चलते-फिरते टेलीविज़न एकक	1242
767	विचारधारा डिवीजन	1242
768	सभा-पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज़ों का हिन्दी अनुवाद	1243
769	राष्ट्र रक्षा कोष	1243
770	सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा	1244
771	रेडियो-फोटो सेवा	1244
772	अमरीकी सैनिक सहायता मिशन	1244–45
773	परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये शिखर सम्मेलन	1245
774	मद्रास में अवाड़ी स्थित कपड़ा बनाने का कारखाना	1245–46
775	मजगांव डाक	1246
776	पंजाब में रोजगार की स्थिति	1246–47
777	जवानों तथा अधिकारियों के यात्रा भत्ते	1247
778	विश्व परमाणु निशस्त्रीकरण सम्मेलन	1247–48
779	टेलीफोन के बिल	1248
780	राणा प्रताप सागर अणु संयंत्र	1248–49
781	"स्टेट्समैन" की सम्पादकीय टिप्पणियां	1249
783	अमरीका में प्रचार	1249–50
784	लेखा प्रक्रिया	1250
785	राजस्थान में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था	1250–51
786	आयुध कारखाने	1251
787	फिल्म समारोह से जर्मनी की फिल्म को वापिस लेना	1252
788	चिकित्सकों के लिए पारपत्र	1252
789	पंजिम का तार घर	1252–53
790	प्रधान मंत्री का संवैधानिक अधिकार	1253
791	अमरीकी उद्योगपतियों का दौरा	1253

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
757.	Border Publicity	1236
758.	Exhibition Covering Pandit Nehru's Life	1236–37
759.	Bonus Bill	1237–38
760.	Ceylon Government's request for picking up bodies of fishermen	1238
761.	Sitting of Lok Sabha	1238–39
762.	Amalgamation of I.A.S. and I.F.S.	1239
763.	U. S. Nuclear Submarines on Patrol Duty	1240
764.	Summit Conference on banning nuclear weapons	1241
765.	Tibet Issue in U. N. O.	1241–42
766.	Mobile T. V. Units in Delhi	1242
767.	Ideology Division	1242
768.	Hindi Versions of Documents Laid on the Table	1243
769.	National Defence Fund	1243
770.	Military Training Centre Kotah	1244
771.	Radio-Photo Service	1244
772.	U. S. Military Aid Mission	1244–45
773.	Summit Conference on banning nuclear weapons	1245
774.	Clothing Factory, Avadi, Madras	1245–46
775.	Mazagaon Docks	1246
776.	Employment Position in Punjab	1246–47
777.	T. A. Scales of Jawans and Officers	1247
778.	World Conference on Nuclear Disarmament	1247–48
779.	Telephone Bills	1248
780.	Rana Pratap Sagar Atomic Plant	1248–49
782.	Installation of Telephones in Nepal	1249
783.	Publicity in U.S.A.	1249–50
784.	Accounting Procedure	1250
785.	Automatic Telephone in Rajasthan	1250–51
786.	Ordnance Factories	1251
787.	Withdrawal of German Film from Film Festival	1252
788.	Passports for Doctors	1252
789.	Telegraph Office, Panjim	1252–53
790.	Prime Minister's Constitutional Right	1253
791.	Visit of U.S. Industrialists	1253

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
792	हावड़ा स्टेशन पर मारपीट	1254
793	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में प्रचार	1254
794	ईसाई और हिन्दू नागा	1255
795	चीन जाने की अनुमति	1255
796	पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण	1255–56
797	सर्वे आफ इंडिया	1256
798	कोयला खान प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें	1256
799	खानों में मजदूर संघ के अधिकार	1257
800	यूगोस्लेविया से टेलीफोन सैट	1257–58
801	श्रम डिपो, गोरखपुर	1258
802	संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के विश्व संघ का सम्मेलन	1258–59
803	औद्योगिक विवाद अधिनियम के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के निर्णय	1259
804	चीनी उद्योग में लाभांश	1259–60
805	क्योन्झर में लौह अयस्क की खानें	1260
806	चीनी उद्योग के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड	1260–61
807	कागज उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	1261
808	आवश्यकताओं के आधार पर मजूरी	1261
809	गुजरात में अणु शक्ति केन्द्र	1262
810	रायगड़ा और जयोर के बीच सीधा टेलीफोन सम्बन्ध	1262
811	भुवनेश्वर में डाक और तार विभाग के क्वार्टर	1262
812	उड़ीसा में ग्राम क्षेत्रों में रेडियो सेट	1263
813	आकाशवाणी के सम्बलपुर केन्द्र के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी	1263
814	उड़ीसा में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	1263–65
815	पंचायत समितियों के कार्यालयों में टेलीफोन	1265
816	दिल्ली मेल मोटर सर्विस	1265–66
817	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के लिए लाइट मशीन गनें	1266
818	राज्यों के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन	1266
819	नई दिल्ली के दुकान कर्मचारी	1267
820	वाराणसी तथा गोरखपुर के बीच बेतार सेवा	1267
821	संसदीय शिष्टमंडल का नागालैंड का दौरा	1267–68
822	योजना का प्रचार	1268
823	दिल्ली में बेकार लोग	1269
824	बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम	1269

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
792.	Fracas at Howrah Station.	1254
793.	Publicity in S.E. Asian Countries.	1254
794.	Christian and Hindu Nagas.	1255
795.	Persons allowed to go to China.	1255
796.	Exodus from East Pakistan	1255–56
797.	Survey of India.	1256
798.	Complaint against Collieries Managements	1256
799.	Trade Union Rights in Mines.	1257
800.	Television sets from Yugoslavia	1257–58
801.	Labour Depot, Gorakhpur.	1258
802.	Conference of World Federation of U. N. Associations	1258–59
803.	Decision of High Courts on Industrial Disputes Act	1259
804.	Bonus in Sugar Industry.	1259–60
805.	Iron Ore Mines, Keonjhar	1260
806.	Second Wage Board for Sugar Industry.	1260–61
807.	Wage Board for Paper Industry.	1261
808.	Need Based Wages.	1261
809.	Nuclear Station in Gujarat	1262
810.	Direct Telephone Circuit between Rayagada and Jaypore	1262
811.	P. & T. Quarters in Bhubaneswar	1262
812.	Radio Sets for Rural Areas of Orissa.	1263
813.	S. C. and S. T. Employees in Sambalpur Station of A.I.R.	1263
814.	National Sample Surveys in Orissa.	1263—65
815.	Telephones in Panchayat Samiti Offices	1265
816.	Delhi Mail Motor Service	1265–66
817.	Light Machine Guns for N.C.C.	1266
818.	Conference of State Ministers for information	1266
819.	New Delhi Shop Employees	1267
820.	Wireless between Varanasi and Gorakhpur	1267
821.	Visit of Parliamentary Delegation to Nagaland	1267–68
822.	Plan Publicity	1268
823.	Unemployed Persons in Delhi.	1269
824.	Beating of Retreat Programme	1269

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
825	ब्रिटिश नौसेना अध्यक्ष का आगमन	1270
826	कानपुर के निकट डाकघर पर डाका	1270
827	नागाओं के लिए पाकिस्तानी हथियार	1271
828	कैंटीन स्टोर्स विभाग .	1271–72
829	कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट	1272
830	कैन्टीन स्टोर्स विभाग .	1273
831	नया प्रसारण कार्यक्रम चालू करना	1273
832	रेडियो लाइसेंस . . .	1274
833	स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू के जीवन पर फिल्म	1274
834	राष्ट्रमण्डलीय समुद्री केबल	1274
835	तारापुर अणु शक्ति केन्द्र .	1275
836	कलकत्ता में स्टेडियम के लिये भूमि	1275

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सरदार प्रताप सिंह कैरों तथा अन्य तीन व्यक्तियों की हत्या .	1275–85
श्री बाल्मीकी . .	1275
श्री हाथी	1275–85

सभा पटल पर रखे गये पत्र 1285

समिति के लिये निर्वाचन	1286
राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति . .	1286
केरल आयव्ययक, 1965–66 . .	1286
रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . .	1286–1305
श्री नेसामनी . .	1286–87
श्री अ० सि० सहगल .	1287–88
श्री दीनेन भट्टाचार्य . .	1288–90
श्री शिव नारायण . .	1290–91
श्री बसवन्त . .	1291–92
श्री मि० सू० मूर्ति . .	1292–94
श्री मधु लिमये . . .	1294–95
श्री गौड़	1295–96
श्री लाटन चौधरी	1296
श्रीमती जमुना देवी	1296–97
श्री मौर्य	1297–98
श्री वासप्पा . . .	1298–99
श्रीमती शकुन्तला देवी . .	1299

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
825.	Visit of British Naval Chief	1270
826.	Hold up in Post Office near Kanpur.	1270
827.	Pakistani arms for Nagas.	1271
828.	Canteen Stores Department	1271-72
829.	Canteen Stores Department	1272
830.	Canteen Stores Department	1273
831.	Introduction of new broadcasting programme	1273
832.	Radio Licences	1274
833.	Film on late Shri Nehru	1274
834.	Commonwealth Submarine Cable.	1274
835.	Tarapore Atomic Power Station.	1275
836.	Land for Stadium at Calcutta.	1275
	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	Murder of Sardar Pratap Singh Kairon and three others	1275—78
	Shri Balmiki	1275
	Shri Hathi	1275—85
	Papers laid on the Table	1285
	Election to Committee.	1286
	Central Advisory Committee for N.C.C.	1286
	Kerala Budget, 1965-66	1286
	Statement presented	1286
	Railway Budget—General Discussion	1286-1305
	Shri Nesamony	1286-87
	Shri A. S. Saigal	1287-88
	Shri Dinen Bhattacharya	1288—90
	Shri Sheo Narain	1290-91
	Shri Baswant	1291-92
	Shri M. S. Murti	1292—94
	Shri Madhu Limaye	1294-95
	Shri Gowdh	1295-96
	Shri Lahtan Chaudhry	1296
	Shrimati Jamunadevi	1296-97
	Shri Maurya	1297-98
	Shri Basappa	1298-99
	Shrimati Shakuntala Devi	1299

विषय	पृष्ठ
श्री शिकरे	1299
श्री सुबोध हंसदा	1299–1301
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	1301
श्री प्र० चं० बरुआ	1302–03
श्री मुहम्मद इलियास	1303–05

Subject	PAGES
Shri Shinkre	1299
Shri Subodh Hansda	1299—1301
Shri Jagdev Singh Siddhanti	1301
Shri P. C. Borooah	1302—03
Shri Mohammad Elias	1303—05

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 8 मार्च, 1965/17 फाल्गुन, 1886 (शक)

Monday, March 8, 1965 /Phalguna 17, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विमान दुर्घटनायें

*302. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 14 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारतीय वायु सेना की विमान दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए मंत्रिमंडल के भूतपूर्व सचिव की अध्यता में नियुक्त की गई समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

समिति की सिफारिशों का वायु सेना अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, और आवश्यक कार्यवाही, उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाएगी । समिति के अध्यक्ष ने सुझाव दिया था, कि हर वर्ष वायु सेनाध्यक्ष वर्ष के दौरान में होने वाली विमान दुर्घटनाओं का पुनरीक्षण करे, और सरकार को अपनी रिपोर्ट दे। इसे सरकार ने मान लिया था, और आवश्यक निदेशन जारी कर दिए गए थे । वायु सेनाध्यक्ष की पहली रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, और उसका निरीक्षण हो चुका है । इससे पता चला है कि 1964 में दुर्घटनाओं की समग्र पुनरावृत्ति में वृद्धि नहीं हुई । सरकार ने रिपोर्ट की निम्न बातों पर कार्यवाही शुरू कर दी है :—

(1) सिफारिश संख्या 14 जिसमें दूसरे मुल्कों में चुने सेविवर्ग को मौसम सम्बन्धी विधि में उच्च प्रशिक्षण के लिए भेजने का सुझाव दिया है । इस उद्देश्य के लिए 4 अफसर भेजे जा रहे हैं ।

(2) समिति ने सर्वे आफ इंडिया की नक्शामाला में संशोधन का सुझाव दिया है। वायु सेना के लिए आवश्यक नक्शों की तैयारी के लिए, एक विशिष्ट सर्वे यूनिट की स्वीकृति दी गई है । इस उद्देश्य के लिए नक्शों की आवश्यकताएं दर्शाने वाली एक सूची तैयार कर ली गई है, और उचित समय के अन्दर उन्हें वायु सेना के लिए प्राप्त करने की एक योजना भी बना ली गई है । इन नक्शों की तैयारी के लिए कार्य अब तक आरम्भ हो चुका है ।

(3) समिति ने जहाज को उतारने के लिए विभिन्न सहायक मशीनें लगाने का सुझाव दिया है । इन सहायकों को प्राप्त करने के लिए तथा उन्हें लगाने के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं कर दी हैं ।

Shri D. N. Tiwary : This statement indicates that the recommendations of the Committee are being examined by Air Force authorities and necessary action will be taken on receipt of their report. One recommendation was that enquiry should be conducted in regard to these aircraft accidents every year and instructions to that effect have been issued. I want to know the causes of accidents which took place during 1964 or there was only one cause for these accidents, if so, what was that ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): We have not received the details of enquiries in regard to the accidents which took place during 1964.

First report shows that the over all accidents rate during 1964 has not gone up. The big accidents have been shown in the report categorywise. The causes of accidents during 1964 have been indicated by the Committee.

Shri D. N. Tiwary : Statement shows that on the suggestion made by the Committee, we have started to revise the maps. I want to know the time, when these new maps will be ready and will be handed over to Air Force authorities ?

Shri Y. B. Chavan : It is difficult to indicate time and date for this.

श्री रा० गि० दुबे : सरकार द्वारा अधिकारियों को ऋतु विज्ञान का उच्च प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने तथा सर्वेक्षण नक्शों को आधुनिकतम बनाने के लिए की गई कार्यवाहियों की मैं प्रशंसा करता हूं । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि आज जब हमें चीन और पाकिस्तान का सामना करना पड़ रहा है, तो वायु सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन नक्शों में संशोधन करने में विलम्ब क्यों हुआ है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में इस पर पहले ही कार्यवाही हो रही थी परन्तु जब दुर्घटनाओं के प्रश्न पर विचार हुआ तो इस समस्या का राष्ट्रीय महत्व देखते हुए विचार करना पड़ा। आपात काल में इस सम्बन्ध में केवल सामरिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया । परन्तु इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश को लेकर विचार किया जाना है ।

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में दिया गया है कि सहायक मशीनें मंगाने की तथा उनको लगाने की व्यवस्था कर दी गई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन दुर्घटनाओं के कारण हमारे बहुत अच्छे विमान चालकों की मृत्यु हो जाती है मैं यह जानना चाहती हूं कि विवरण में इतनी लापरवाही से क्यों बताया गया है कि सहायक मशीनों को मंगाने की व्यवस्था कर ली गई है ? यह कहा जाना चाहिये कि सभी सहायक मशीनें तुरन्त दी जायेंगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन मूल्यवान व्यक्तियों के प्रति लापरवाही दिखाने की बात नहीं है। यह हमारे लिये बहुत कीमती हैं। परन्तु जब हम कहते हैं कि हम कुछ मंगा रहे हैं तो 'कुछ' शब्द इस्तेमाल करना ही पड़ता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है, जो विशेषतः खर्च आदि के बारे में तथा मृतकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता के बारे में और अन्य बातों के बारे में है ? यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय की इस वर्ष की मांगों में इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था कर ली गयी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : साधारणतः व्यवस्था होती है। वायु सेना के सामान्य बजट में इसके लिए व्यवस्था होती है। आशा है उसमें व्यवस्था है।

श्री हरि विष्णु कामत : ऐसी आशा है। क्या आपको मालूम नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस बात पर वायु सेना के हैडक्वार्टर की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि वह इसमें बढ़ोतरी या परिवर्तन का सुझाव देते हैं, तो हो सकता है हम अनुपूरक मांगें पेश करें।

श्री इकबाल सिंह : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई तुलना की है कि हमारे देश में ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे विकसित देशों की अपेक्षा विमान दुर्घटनायें कम होती हैं अथवा अधिक ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट में बताया गया है, और कुछ तुलनात्मक आंकड़ें भी उसमें दिये गये हैं। परन्तु मेरे विचार से यह वास्तविक तुलना नहीं है क्योंकि वहां पर चलने वाले विमानों और वहां की जलवायु में हमारे विमान तथा जलवायु में बहुत अन्तर है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में बताया गया है कि 1964 में दुर्घटनायें बढ़ी नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 1964 में दुर्घटनाओं की संख्या पिछले साल की दुर्घटनाओं से कम थी या अधिक ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह कम थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : "दुर्घटनाओं की दर" का अर्थ क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में इसका अर्थ पिछले दस सालों की औसत से है।

भारत और पाकिस्तान के गृह मन्त्रियों का सम्मेलन

+

*303. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामसेवक यादव :
श्री हेमराज :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रा० बरुआ :

श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों की अगली बैठक की तारीख और स्थान निश्चित करने के बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो ये बैठक कहां होगी और इसकी कार्य-सूची की संक्षिप्त रूप रेखा क्या होगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पिछली बैठक का प्रस्ताव पाकिस्तान में चुनाव होने के कारण रद्द हो गया था । पाकिस्तान ने बैठक में भाग न लेने के बारे में कुछ और नये कारण बताये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमें यह अनौपचारिक रूप से बताया गया है कि मार्च 1965 तक पाकिस्तानी अधिकारी इन विषयों पर बातचीत के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पायेंगे ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इसके आधार पर कि पाकिस्तान बैठक के लिये उत्सुक नहीं है तथा हाल में ही उसने सीमा पर आक्रमणात्मक गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इसमें कोई शरारत देखी है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं ।

Shri R. S. Pandey : Has the election of Shri Ayub Khan as President of Pakistan effected in any way the solution of problems which were to be discussed in the meeting between the Home Ministers of India and Pakistan.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता है । मैंने बताया कि वह मार्च से पहले सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या राष्ट्रपति अय्यूब खां के पुन: चुने जाने के कारण उस पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव और हाल की शेख अब्दुल्ला की विदेश यात्रा के समय पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष सहायता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पाकिस्तान सरकार से कहेगी कि वह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है कि जिस पर विचार किया जाना चाहिये ।

Shri Yashpal Singh : In view of Pakistan's claims over Kutch area and Mr. Bhutto's statement that there is no likelihood of any settlement of Kashmir question, why do the Government not drop the idea of Indo-Pak Home Ministers' conference in March or April ? There were so many meetings of Shri Swaran Singh with Pakistan Ministers, but all those meetings bore no fruit. Why are we persisting on this conference ?

Mr. Speaker : This should also be considered.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के विवरण से स्पष्ट है कि अभी कोई तारीख नियत नहीं की गई । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्मेलन से पहले कुछ शर्तें लगायेगी जैसे पाकिस्तान आक्रमण द्वारा हथियाये गये क्षेत्र को पहले खाली करे और उसके पश्चात् गृह-कार्य मंत्री सम्मेलन हो ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इस समय गृह-कार्य मंत्रियों की बैठक का प्रश्न नहीं है । यदि बैठक हुई तो अन्य विषयों पर भी विचार हो सकता है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान जनरल अय्यूब खां के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत-पाकिस्तान गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन से कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकलेंगे । यदि हां, तो पाकिस्तान के नेता का शरारत भरा वक्तव्य . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हेम बरुआ : मैं इसे वापिस लेता हूं, यद्यपि यह गलत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कहता कि ऐसा कहना गलत है । परन्तु एक अन्य देश के बारे में जिसे हम मित्र देश कह सकते हैं, नहीं कहना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वे वास्तव में हमारे मित्र हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमें राज्याध्यक्ष के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न करने वाले सदस्य के विचारों तथा दृष्टिकोण पर बहुत निर्भर करता है । मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हमारा मित्र नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : 'शरारत भरा' एक बहुत हल्का शब्द है ।

अध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी के विचारों तथा दृष्टिकोणों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान जनरल अय्यूब खां के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत-पाकिस्तान गृह-कार्य मंत्रियों के आगामी सम्मेलन से कोई

लाभ नहीं होगा तथा यदि हां, तो क्या इससे हमारी सरकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? और यदि नहीं, तो इस सम्मेलन के बारे में हमारी सरकार को इतनी आशा क्यों है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें कोई विशेष आशा नहीं है । बात यह है कि सम्मेलन एक पक्षीय नहीं हो सकता ।

श्री हेम बरुआ : जनरल अय्यूब खां के वक्तव्य के बारे .....

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां । यदि वह गृह-कार्य मंत्री सम्मेलन करने पर राजी नहीं होंगे तो सम्मेलन नहीं होगा ।

श्री बसुमतारी : जब तक भारत-पाकिस्तान गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन की तारीख निश्चित नहीं होती तब तक क्या भारत सरकार ने आसाम सरकार से कहा है कि वह आसाम से पाकिस्तानियों को न निकाले ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरे विचार में ऐसा नहीं है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार का ध्यान शेख़ अब्दुल्ला द्वारा लन्दन में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री की बैठक का सुझाव दिया है तथा काहिरा में दिये गये वक्तव्य की ओर भी दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि काश्मीर के लोगों की सलाह नहीं ली गई है तथा यदि हां, तो क्या शेख़ अब्दुल्ला के पारपत्र में भाषण स्वतन्त्रता .....

अध्यक्ष महोदय : यह बात बिल्कुल अलग है । हम गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : During the last 17 years Pakistan is in occupation of our land in Kashmir, West Bengal and Kutch. As this problem could not be solved by protest notes, whether Government will take some firm steps to take back this land ?

Mr. Speaker : That is a separate question.

श्री कपूर सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्रियों की बैठक में काश्मीर का प्रश्न कार्य-सूची में है ? यदि उत्तर 'हां' में है, तो क्या इस बैठक के सफल होने की कोई आशा है और यदि उत्तर 'नहीं' में है, तो क्या इस बैठक के सफल होने की कोई आशा है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी इसकी कोई आशा नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : जब कभी भी बैठक होगी, क्या इसको कार्य-सूची में रखने की कोई आशा है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जब गृह-कार्य मंत्रियों की बैठक होगी, तो वे उन्हीं विषयों पर बात करेंगे जिन पर पहले बात कर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भी एक विषय होगा ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : गृह-कार्य मंत्रियों का प्रस्तावित सम्मेलन पाकिस्तान के इस सुझाव पर स्थगित किया गया था कि वहां पर चुनाव हैं। क्या सरकार को कोई संकेत भी मिला है कि क्या पाकिस्तान इस सम्मेलन को चाहता है या नहीं?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस का पहले उत्तर दिया जा चुका है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस प्रकार के जो सम्मेलन पहले हो चुके हैं उनका भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य-सूची में नहीं है । श्री विभूति मिश्र ।

Shri Bibhuti Mishra : Pakistan's very creation was based on hatred and disputes. Does the Government hope for a settlement with that country?

Mr. Speaker : Next question.

Shri Bibhuti Mishra: Mr. Speaker my question has not been answered.

Mr. Speaker : This question is enough. Its answer is in itself.

Shri Bibhuti Mishra : We are being kept in the dark by refusing answer to this auqestion.

Mr. Speaker : The hon. member is aware that some questions have their answers in themselves. There is no need to give their answers. That is why I have not asked Government to answer that question.

भारत-लंका करार

\+

*304. { **श्री रामनाथन् चेट्टियार :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–लंका अधिकारी दल की भारत–लंका करार के अन्तर्गत जो कि भारत–लंका के प्रधान मंत्रियों के बीच 1964 में हुआ था; भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा उनकी सम्पत्तियां को भारत लाने के बारे में हो रही वार्ता का क्या परिणाम रहा है; और

(ख) लंका सरकार ने भारतीय राष्ट्रजनों को अंतिम बार भारत आते समय नकदी, जेवर तथा अन्य चल सम्पत्ति साथ लाने की क्या रियायतें देना स्वीकार किया है?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) श्रीलंका और भारत के अधिकारियों के बीच जो बातचीत हुई, उसमें श्रीलंका से अंतिम रूप में भारत आते समय भारतीय राष्ट्रिकों की परिसंपत्ति लौटाने की बात इस शक्ल में नहीं उठी ।

(ख) विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अधीन रहकर, श्रीलंका सरकार इस पर सहमत हो गई है कि अक्तूबर, 1964 के भारत–श्रीलंका क़रार के अंतर्गत प्रत्यावर्तित होने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को श्रीलंका से अंतिम रूप में वापस आते समय अपनी सभी परिसंपत्ति ले जाने की अनुमति दी जाय । श्रीलंका सरकार भारतीय राष्ट्रिकों को आजकल 75,000 रुपए की अधिकतम सीमा तक अपनी परिसंपत्ति वापस लाने की अनुमति देती है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार का ध्यान वित्त मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने कहा था कि पहली अगस्त, 1964 से लंका से भेजे गये धन के बारे में विलम्बकाल दिया जायेगा और क्या इस से करार की शर्तों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

श्री दिनेश सिंह : आशा है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अभी इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या उन्होंने 1.50 लाख रुपये से घटा कर 75,000 रुपये लाने की सीमा भारतीय राष्ट्रजनों के लिए ही निश्चित की है ?

श्री दिनेश सिंह : ऐसा केवल भारतीय राष्ट्रजनों के बारे में ही नहीं किया गया । परन्तु कई देश हैं जिन को उन्होंने एक ग्रुप में रखा है और उन सभी देशों के राष्ट्रजनों के लिए 75,000 रुपये अपने देश वापस ले जाने की इजाज़त दी है ।

श्रीमती सावित्री निगम : मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमंत्री ने कहा कि बातचीत के दौरान इस प्रश्न पर चर्चा नहीं की गई । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर हज़ारों ऐसे भारतीय हैं जिनकी वहां काफी सम्पत्ति है, तो बातचीत के दौरान ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर क्यों चर्चा नहीं कीं गई ?

श्री दिनेश सिंह : जिन बातों के लिये चर्चा की गई थी, उनको सभी सदस्य जानते हैं । यह करार तो बाद में हुआ था । चूंकि लोग इतना ही धन ला रहे हैं, इसलिये इस मामले पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Do Government think that the repatriation of property worth Rs. 75,000/- allowed by the Government of Ceylon is enough ; and if not whether the Government have given any suggestion to Ceylon Government to raise this limit ?

Shri Dinesh Singh : The Government of India are of the view that the Indians should take out watever they have and accordingly we have requested the Government of Ceylon.

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार ने उस सम्पत्ति की कुल मालियत का पता लगाया है जो लंका में अब भारतीयों के पास है ?

श्री निनेश सिंह : जी, नहीं ।

मिग विमान परियोजना

+

श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विवश्नाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

*305 श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सोवियत संघ की सहायता से मिग विमान कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उत्पादन कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) असैनिक निर्माणों तथा प्रशिक्षण कार्य-क्रमों की प्रगति सन्तोषजनक है । प्लांट, मशीनरी, जिग, हथियार तथा विमानों के अवयव रूस से प्राप्त करने सम्बन्धी काम हाथ में लिए गये हैं ।

(ख) मिग फैक्टरियों में विमान निर्माण करने की योजना चार विभिन्न प्रावस्थाओं में की गई है, अर्थात् बड़ा एकत्रीकरण, छोटे एकत्रीकरण, छोटे छोटे अवयवों से और कच्चे माल से । आशा की जाती है कि प्रथम प्रावस्था अगले वर्ष आरम्भ हो जाएगी, और चार वर्षों में विमान अपने अन्तिम प्रावस्था से गुजर कर फैक्टरी से बाहर आने लगेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या विशेषज्ञों के रूसी दल ने, जो यहां था, अपनी अन्तिम सलाह दे दी है और क्या उन्होंने हमें यह सारी तकनीकी जानकारी दे दी है कि इसको बिना और विलम्ब के कैसे बनाया जा सकता है ?

श्री अ० म० थामस : निस्सन्देह वे हमें सभी तकनीकी जानकारी देंगे । सोवियत रूस की यात्रा के पश्चात्, प्रतिरक्षा मंत्री ने सभा यह बताया था कि सोवियत संघ उत्पादन करने तथा इस बारे में तकनीकी सलाह देने के मामले में अधिक कार्य करेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि मिग विमान 21 सोवियत संघ और अन्य देशों में पुराना माना जाता है, यदि हां, तो क्या हम मिग विमान 21 अथवा मिग विमान 24 का, जो सोवियत संघ ने चीन को दिये हैं, निर्माण करने के लिये करखाना लगाने में अब भी दिलचस्पी ले रहे हैं ?

श्री अ० म० थामस : यह पुराने नहीं हुए हैं, और जिस का हम निर्माण करने जा रहे हैं वह मिग विमान 21 का परिष्कृत रूप है ।

Shri Yashpal Singh: May I know the number of MIGs which have been received from Russia according to the schedule and the number thereof which are yet to be recived?

श्री अ० म० थामस : मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले हम भारत में विमान, उनके पुर्जों को जोड़कर बनायेंगे और ऐसा हम आगामी वर्ष के आरम्भ से करना शुरू कर देंगे। विमान बनाने के अन्य क्रमों के बारे में भी हमने कार्यक्रम बनाया है . .

अध्यक्ष महोदय : वह कार्यक्रम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। वह उन विमानों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं जो उन्होंने हमें दे दिये हैं ।

श्री अ० म० थामस : हम ने संयंत्रों, मशीनों, जिगों और अन्य चीज़ों की एक सूची दी है । वे इस की जांच कर रहे हैं और आशा है कि हमें ये चीज़ें समय पर मिल जायेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या उन में से कोई विमान प्राप्त हो चुका है ।

श्री अ० म० थामस : विमानों की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है । उत्पादन का कार्यक्रम आरम्भ होगा . . .

अध्यक्ष महोदय : वह उत्पादन कार्यक्रम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, परन्तु विमान मिलने के बारे में पूछ रहे हैं हालांकि यह प्रश्न संगत नहीं है ।

श्री अ० म० थामस : श्रीमन्, इस का सम्बन्ध तीन स्क्वैड्रनों को सुसज्जित करने से है जिस का अभी प्रतिरक्षा मंत्री ने उल्लेख किया है । आशा है कि वे यथासमय प्राप्त हो जायेंगे ।

Shri Vishwa Nath Pandey: The hon. Minister just said that the production of MIGs would start only after four years, may I know as to how the requirements of these four years would be met?

श्री अ० म० थामस : प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दिये गये विवरण में इसको स्पष्ट कर दिया गया है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने देश में विमान बनाने के लिए अपेक्षित कच्चे माल, इस्पात आदि को प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्यन किये हैं और मशीनें अथवा कच्चा माल खरीदने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

श्री अ० म० थामस : यह बताना लोक हित में नहीं होगा कि इसमें कितनी विदेशी मुद्रा होगी और हमें स्वयं कितना धन उपलब्ध करना होगा ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या इस कारखाने के स्थापना स्थान के बारे में कोई अस्थायी निर्णय किया गया है ?

श्री अ० म० थामस : इंजिन कारखाना उड़ीसा में कोरापुट में, ढांचों का कारखाना महाराष्ट्र में नासिक में और इलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री हैदराबाद में होगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या हम ने रूसी सहयोगियों से ऐसा कोई प्रबन्ध किया है कि वे आगामी दो अथवा तीन वर्षों में मिग विमानों के बनाने के बारे में जो भी प्रोद्योगिकीय विकास और सुधार लायें जायेंगे, उनकी जानकारी हमें वे अपने आप ही देंगे जिस से हम अपने मिग विमानों में वह सुधार कर सकें ?

श्री अ० म० थामस : मैं ने पहले ही बता दिया है कि यह विमान जिसका हम निर्माण करने जा रहे हैं, मिग विमान 21 का परिष्कृत रूप है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : माननीय मंत्री ने कहा कि कारखाना तीन विभिन्न स्थानों पर लगाया जा रहा है । क्या मैं जान सकती हूं कि आयोजन तथा निर्माण के लिये ज़िम्मेदार कौन है और समन्वय एजेंसी कौन सी है ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में इस का निर्णय तो बहुत पहले किया गया था । सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय किया था कि तकनीकी तथा सुरक्षा सम्बन्धी कारणों की दृष्टि से ये कारखाने तीन स्थानों पर होने चाहियें ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इन कारखानों के आयोजन तथा इन के कार्य का समन्वय करने के लिये कौन ज़िम्मेदार है ?

श्री अ० म० थामस : यह हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जायेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : आपातकाल की दृष्टि से क्या मिग विमानों के उत्पादन में होने वाली देरी से हमारी प्रतिरक्षा सबन्धी तैयारी पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री अ० म० थामस : उस के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि गत 15 अक्तूबर से, जिस दिन क्रे लिन में राजनैतिक उथल पुथल हुई थी, इस विशिष्ट परियोजना के बारे में सोवियत सहायता धीमी गति से मिल रही है जैसा कि 12 मिग विमानों के न मिलने से स्पष्ट है क्योंकि ठेके के अनुसार वह हमें जनवरी तक मिल जाने थे और अभी नहीं आये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह सच नहीं है । 12 मिग विमान जिनको रूसियों ने देने का वचन दिया था, देश में पहले ही आ चुके हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : कितने आ चुके हैं ? चार आये हैं और दो गिर कर टूट गये हैं ? कितने और अभी आने हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : उत्तर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यही कि कार्यक्रम के अनुसार आ रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : Will only MIGs would be produced in the factories which are being set up under the MIG Project or whether any such Department would also be opened which could examine as to whether further development and improvements are possible in the manufacture of engines and frames of the aeroplanes ?

श्री अ० म० थामस : इन कारखानों में मुख्य तौर से मिग विमानों का ही निर्माण किया जायगा । शायद हैदराबाद के एरोनाटिक्स कारखाने में अन्य उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम भी किया जा सकेगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it would be possible for us to bring about certain improvement or changes in the project on the basis of the experience of the working of the MIG Aeroplanes which are being received under the agreement signed by the Defence Minister a few months back and whether Soviet technical assistance would be available to us for this purpose ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मेरे विचार से हम अपेक्षित तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकेंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि कोरापुट में कारखाने का निर्माण अनुसूची के अनुसार नहीं चल रहा है ? इस देरी के क्या कारण हैं ?

श्री अ० म० थामस : परियोजना की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है और उसको अन्तिम रूप अभी दिया जायेगा । हमने निर्माण की पहले क्रम के लिये 2.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है । बस्ती में प्रशिक्षण स्कूल और मकान बन गये हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : परन्तु अनुसूची क्या है ?

श्री हरि विष्णु कामत : कार्य अनुसूची के पीछे है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य को यह कहते सुना है कि कार्य अनुसूची के पीछे है ।

श्री अ० म० थामस : ये सभी कार्यक्रम---ढांचों का कारखाना, इंजिनों का कारखाना और एयरोनाटिक्स साथ साथ होने हैं । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य अनुसूची के पीछे है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । वरिष्ठ मंत्री तथा कनिष्ठ मंत्री द्वारा दिये गये विवरणों में विरोध है । वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि कार्य धीमी गति से नहीं हो रहा है जब कि कनिष्ठ मंत्री कहते हैं कि गति मन्द हो गई है किस पर विश्वास किया जाये और कौन सही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा पहले दिया गया उत्तर, सहायता की गति के बारे में था न कि इस बारे में । माननीय सदस्य को दोनों में भेद करना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु यह सब एक ही चीज है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या इस परियोजना में विमानचालकों जैसे कर्मचारी आदि को प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम अथवा योजना है ?

श्री अ० म० थामस : जी, हां ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस करार में सोवियत कारखानों में शिल्पिकों और इंजीनियरों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है और यदि हां, तो क्या अनुसूची के अनुसार उनकी प्रगति हो रही है ?

श्री अ० म० थामस : सोवियत विशेषज्ञ भारत में आयेंगे और वे हमारे कारखानों में हमारे लोगों को प्रशिक्षण देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपने लोगों को बाहर भेजने का भी कार्यक्रम है ?

श्री अ० म० थामस : अभी नहीं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The factories are being set up at three different places, may I know as to whether it is being done on political basis or economic basis ?

श्री अ० म० थामस : अपने देश की सुरक्षा के विचार से ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कभी ऐसा हो सकता है कि वामपक्षी साम्यवादियों के बुलावे पर हमारे देश पर आक्रमण हो और आपातकाल आये तथा हम मिग विमानों के निर्माण के लिये चार वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकें, तो क्या सुपरसोनिक विमान प्राप्त करने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका से कोई बातचीत की जा रही है ?

श्री अ० म० थामस : सभा में अनेक बार बताया जा चका है कि इस उत्पादन कार्यक्रम के अतिरिक्त अपनी वायु सेना को सशक्त बनाने के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध भी किये जा रहे हैं ।

Shri Bibhuti Mishra: By the time MIG aeroplanes would be produced after four years, it might become obsolete in the world; are Government taking this possibility into consideration that when they will be manufactured they would be up-to-date?

श्री अ० म० थामस : मैंने पहले ही बता दिया है कि इनका निर्माण चार क्रमों में होगा । पहला क्रम आगामी वर्ष के प्रारम्भ में आरम्भ होगा और देश में पुर्जों को जोड़ कर विमानों का निर्माण किया जायेगा । अन्तिम क्रम में कच्चे माल से विमान तैयार किये जायेंगे । ऐसा करने में चार वर्ष लगेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त इस परियोजना पर कितना खर्चा आयेगा ?

श्री अ० म० थामस : नासिक कारखाने की अनुमानित लागत लगभग 18 करोड़ रुपये है और विमान इंजिन कारखाने की अनुमनित लागत लगभग 35 करोड़ रुपये है ।

श्री रंगा : श्री विभूति मिश्र का प्रश्न यह था कि इन चार वर्षों में निर्माण, तकनीक और डिजाइन में बहुत फेर बदल हो जायेगी, क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जब भी वे

मिग विमानों का ऐसा डिज़ाइन तैयार करें जिसमें कोई परिवर्तन हो तो वह विमान आधुनिकतम हो ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया मैं नहीं जानता कि क्या वह हमारे प्रश्नों को समझ रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री अ० म० थामस: मैंने अभी बताया कि जिन विमानों का हम निर्माण करने जा रहे हैं वह मिग 21 का परिवर्तित रूप है। इसका अर्थ यह है कि उस विमान में अभी तक किये गये सुधारों को ध्यान में रखा जायेगा। इसके बाद के भी जो सुधार होंगे उन को भी ध्यान में रखा जायेगा।

Shri D. N. Tiwary : What would have been the difference in the cost of these MIG planes if they would have been manufactured at one place instead of at three different places ?

श्री अ० म० थामस : इन सभी बातों पर विचार किया गया था। मैंने पहले ही बताया है कि ऐसा सुरक्षा तथा अन्य सभी संगत कारणों से किया गया है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि यदि इनका उत्पादन तीन स्थानोंकी बजाय एक स्थान पर किया जाता तो इनकी लागत में क्या अन्तर होता ?

अध्यक्ष महोदय : जब हम समझते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें तीन स्थानों पर होना चाहिये तो हमें लागत में अन्तर पर ध्यान क्यों देना चाहिये।

CONCENTRATION OF PAK. FORCES

*306. **Shri Parkash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri D. C. Sharma :
Shri P. C. Borooah :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Maheshwar Naik :
Shri M. Rampure :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the conentration of armed forces of Pakistan on the Jammu and Kashmir border has increased ;

(b) whether it is also a fact that a similar situation is likely to develop on the Rajsthan and West Bengal borders ; and

(c) if so, the steps Government propose to take to meet the situation ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) समस्त युद्ध विराम रेखा तथा जम्मू काश्मीर की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ, पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सैनिकों के, क्रियाकलाप बिना रुके जारी है ; पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में उनके सैनिकों का कोई नया जमाव नहीं हुआ।

(ख) इन सीमाओं पर कोई असाधारण गति-विधि देखने में नहीं आई।

(ग) अपनी सीमाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, सभी आवश्यक एहतियाती उपाय किए गए हैं, और किए जा रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the activities of Pakistan on the Indian border, especially on the border of J.&K. have increased much after the treaty was signed between Pakistan and China and whether there is some hand of China also after these activities.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह सच है कि 1964 में इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। मैं नहीं कह सकता कि इसका उनसे सम्बन्ध है या नहीं। यह तो अनुमान का विषय है।

Shri Prakash Vir Shastri : Last time in reply to similar question, the Hon. Defence Minister said that he had no information about the degging of trenches or the construction of roadsor some like activities by Pakistan in the areas of Pakistan adjoining Rajasthan. I want to know whether now he got that information; If so, whether Pakistan activities have increased in Comparison on the Rajasthan border.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि वहां पर और अधिक जमाल हुआ है लेकिन वे बाज दफा अपने क्षेत्र में सक्रिय होने का प्रयत्न करते हैं और हमें सब कुछ पता है कि दूसरी ओर क्या होता रहता है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know the weakness in the policy of the Government of India due to which Pakistanis are encouraged and concentrate on our borders ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि यह हमारी नीति की दुर्बलता के कारण है यह तो उनका सामान्य रवैया और स्वभाव है कि वे इस प्रकार व्यवहार करते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : यह प्रश्न केवल जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल और गुजरात की सीमाओं पर सेनाओं के जमाव का प्रश्न ही नहीं है, जिसका मंत्री महोदय ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है लेकिन प्रश्न यह है कि बाज दफा ये पाकिस्तानी हमारी सीमाओं के भीतर 10, 15 और 20 मील तक घुस आते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इसके क्या कारण हैं और सरकार पाकिस्तानी सेना को अतिक्रमण करने से क्यों नहीं रोक पाती ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब कभी वे जम्मू तथा काश्मीर में कोई घटना पैदा करते हैं, हमने समय समय पर उनको भेजे गये कड़े विरोध पत्रों के बारे में जानकारी दी है। कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जहां सीमांकन नहीं किया गया है, वे अतिक्रमण करने का प्रयत्न करते हैं और ऐसे मामलों में पूर्वोपायी कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : काश्मीर और पूर्वी पाकिस्तान में, दो सीमाओं पर बार बार झगड़े हो रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वे इस प्रकार उत्तेजनात्मक कार्रवाई द्वारा भारत की शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संभवतः वे हमारी शक्ति का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हों। निश्चित ही उनको पता लग जाना चाहिए कि हम भी तैयार हैं।

श्री अब्दुल ग़नी गोनी : क्या सरकार ने सेनाओं को आदेश दिए हैं कि घुसपैठ करने वालों का निःस्वामिक भूमि में पीछा न किया जाए और क्या इससे पाकिस्तानी सेनाओं को प्रोत्साहन मिला है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इन मामलों में दिए गए निर्देशों के बारे में मैं विचार नहीं करना चाहता ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पिछले महीने प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वे राजस्थान सीमा का दौरा करेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि वहां का दौरा न करके क्या उन्होंनें राजस्थान सीमा की समस्या का अध्ययन किया है और यदि हां, तो लोगों के सीमा के भीतर 50, 60 मील तक आने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है । लेकिन इस विशेष सीमा पर इस समय पुलिस तैनात है, यहां पर सेना नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं । पिछले महीने सीमा से घुसने वाले व्यक्ति ने कुछ नृशंस कार्य किए थे । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आपने इस समस्या का अध्ययन किया है और आपने 50 मील भीतर तक घुसपैठ को रोकने और इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं जिनसे हमारे लोगों का मनोबल गिर रहा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : तकनीकी तौर से, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय अथवा पुलिस की है । अतः मैं यह नहीं बता सकता कि क्या सैनिक कार्यवाही की गई है । सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उस ओर से कोई सैनिक आक्रमण नहीं हो सकेगा । यह सावधानी हमने बरती है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी को कराची में दिए गए एक पाकिस्तानी मंत्री के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि "भारत द्वारा काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के बराबर उल्लंघन किए जाने से पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ सकता है ।" और यदि हां, तो पाकिस्तान की इस धमकी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता था कि वास्तव में वे अपनी ही कार्यवाहियों पर दोष प्रकट कर रहेहैं । वस्तव में वे एक दृश्य उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा हैं । यदि वे संकट उत्पन्न करना चाहेंगे, तो हमें, उसका कड़ा उत्तर देना होगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या सरकार को कच्छ में हाल में हुई घुसपैठ का पता है और क्या प्रतिरक्षा मंत्री कच्छ का दौरा करेंगे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विदेश मंत्री सभा को जो कुछ बता चुके हैं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कह सकता । इस समय सेना का सवाल नहीं है । इस समय मेरा वहां जाने का इरादा नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that the Government have decided to form a no man's land area of 4 miles on the Kashmir border and the persons living there would be given certificates. If so, how far it has been implemented ?

Shri Y. B. Chavan : We implement it but the difficulty is that others do not implement.

श्री पें० वेंकटासुब्या : क्या सीमा पर सेना के जमाव के अतिरिक्त, पाकिस्तान हमारे देश में घुसने और यहां विध्वंसक कार्यवाही करने के लिए तोड़फोड़ की योजना बना रहा है, क्या सरकार को इस बात का पता लगा है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं बता चका हूं कि हमें इन बातों का पता है और जब कभी हमें तोड़फोड़ के प्रयत्नों के बारे में पता चलता है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The highest officer of the East Pakistan Army is the brother of a Central Minister. He gets information from here and concentrates Pakistani Armed Forces on our borders into Pakistan areas.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । ऐसा कहना उचित नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : तो इस बात से इन्कार किया जाए ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सुझाव देना बड़ा अनुचित है । ऐसा हो सकता है कि किसी मंत्री का कोई सम्बन्धी वहां हो और नहीं भी हो सकता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे मैं मझे कोई जानकारी नहीं है ।

Mr. Speaker : It is not correct to say that they get information from here यह सुझाव बड़ा अनुचित है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The highest Officer of the Army there is the brother of a Central Minister or not ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे पता नहीं है । जहां तक मुझे पता है वहां की सेना में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Government enquire into this matter ?

Mr. Speaker : This you have asked now. He said that he had no information.

श्री शिकरे : क्या प्रतिरक्षा मंत्री सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह बहाना करके कि सरकार अभी तक इस बारे में निर्णय नहीं कर सकी है कि यह मामला गृह मंत्रालय के अधीन है या प्रतिरक्षा मंत्रालय के या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के, इस बारे में सभी संभव कार्रवाई की जाएगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उत्तरदायित्व का ऐसा कोई विभाजन नहीं है । यह तो सामूहिक उत्तरदायित्व है ।

श्री इकबाल सिंह : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि पाकिस्तान पाकिस्तान से लेकर पंजाब और राजस्थान तक सीमाओं पर सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को बसा रहा है और बहावलपुर राज्य से लेकर राजस्थान-पंजाब सीमा तक सड़कें बना रहा है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे लोग ऐसे कदम जरूर उठा रहे हैं । हमारी जानकारी यह है कि वे भूतपूर्व सैनिकों को बसाने और सड़कें बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

देश में रोजगार की स्थिति

+

*307. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में रोजगार की स्थिति के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख) सन् 1961 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 43,92,00,000 थी जिस में 18,85,00,000 व्यक्ति काम कर रहे थे । तीसरी योजना काल (सन् 1961—66) के दौरान देश की श्रम शक्ति में 1,70,00,000 व्यक्तियों की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है । ताजे आंकड़ों के अनुसार, तीसरी योजना काल में बढ़े रोजगार अवसरों का अनुमान 1,30,00,000 लाख होगा । योजना के विविध कार्यक्रमों को अच्छी तरह लागू करना, औद्योगिक क्षमता का पूरा पूरा उपयोग, तथा देहाती इलाकों का विकास आदि कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिन से अतिरिक्त रोजगार अवसर बढ़ेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दूसरी और तीसरी योजना-काल में बच रहे कितने व्यक्तियों को चौथी योजना-काल में रोजगार दिया जाएगा और क्या यह सच है कि चौथी योजना-काल में ये आंकड़े 35,000,000 तक पहुंच जाएंगे ?

श्री र० कि० मालवीय : तीसरी योजना से जो आंकड़े चौथी योजना में ले जाए जाएंगे, वे 12,000,000 हैं । चौथी योजना के आकड़ों पर विचार किया जा रहा है और चौथी योजना पेश किये जाने के समय उनको भी सभा में पेश किया जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है, चौथी योजना-काल में श्रम निर्माण कार्यक्रमों के लिए सरकार के क्या विशिष्ट प्रस्ताव हैं और क्या उन्हें बेरोजगारी बीमा की किसी योजना से सम्बद्ध किया जाएगा ?

श्री र० कि० मालवीय : विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं । लेकिन चौथी योजना में जितनी रोजगार क्षमता होगी और जो तीसरी योजना में है वह योजना के सामान्य विकास कार्यक्रम हैं जिन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है और तीसरी योजना में विशेष उपाय किए गए जैसे ग्रामीण कार्यक्रम, ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता समेत विशेष सुविधाएं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग, अर्थात् बेरोजगारी बीमा के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री र० कि० मालवीय : यह विचाराधीन है ।

श्री दी० चं० शर्मा : जब कि लोग बड़ी तेजी से गांवों को छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत के गांवों में रोजगार की स्थिति बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट उपाय किए हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : ग्राम-विकास कार्यक्रम तो चल रहा है जो सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है । यदि ब्योरा चाहिए, तो वे दे सकेंगे । इसके लिए माननीय सदस्य उस मंत्रालय से एक पृथक् प्रश्न पूछें ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विशिष्ट उपायों के बारे में जानकारी चाहता था और मंत्री महोदय विकास के बारे में बतला रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : इस समय उन के पास इसका उत्तर नहीं है। सम्बन्धित मंत्रालय से एक पृथक् प्रश्न पूछा जा सकता है ।

श्री दी चं० शर्मा : तो फिर वह यह कह सकते हैं कि "मेरे पास उत्तर नहीं है"।

श्री स०चं० सामन्त : क्या इस बात का कोई सर्वेक्षण किया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई बड़ी बड़ी परियोजनाओं में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ?

श्री र० कि० मालवीय : पहिली, दूसरी तथा तीसरी योजना में कुछ 28,000,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : एक योजना से दूसरी योजना में बेरोजगारी के आंकड़े रखे जाने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने बेरोजगारी बीमा लागू करने की किसी योजना पर विचार किया है ?

श्री र० कि० मालवीय : यह मामला विचाराधीन है ।

श्री बूटा सिंह : क्या बेरोजगारी के बारे में सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषत: कृषि क्षेत्र में, बेरोजगारी शामिल है ? यदि हां, तो यह कितनी है और बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्री र० कि० मालवीय : ग्रामीण जनता को केवल कृषि के विकास द्वारा ही रोजगार मिलेगा । वहां पर छोटे पैमाने के उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इन आंकड़ों में गांवों में बेरोजगारी के आंकड़े भी शामिल हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : जी, हां ।

श्री मुहम्मद इलियास : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार-व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : जैसा कि मैंने अभी बताया, गांवों में कृषि का विकास और छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना ।

प्रधान मन्त्री के साथ उद्योगपतियों की भेंट

\+

*308. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख उद्योगपति जनवरी, 1965 में देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए उन से मिले थे, और

(ख) यदि हां, तो उन के सुझाव तथा कठिनाइयां क्या हैं और उन के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मन्त्री के सभा-सचिव (श्री ललित सेन) : (क) और (ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण]

2 जनवरी, 1965 को कई एक उद्योगपति प्रधान मंत्री, गह-मंत्री, वित्त मंत्री, और उपाध्यक्ष, योजना आयोग के मिले । उन्होंने इस बात पर चिन्ता प्रकट की कि आर्थिक विकास की प्रगति इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिये । सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए । सरकार ने उन्हें बताया कि सरकारी उपक्रमों में काम को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से आगे ही कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस विवरण में केवल प्रक्रिया सम्बन्धी तरीकों का ही ज़िक्र किया गया है । इन मित्रों द्वारा क्या ठोस सुझाव व कठिनाइयां बताई गई थीं और प्रधान मंत्री उनको कहां तक संतुष्ठ कर सके ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : सामान्य बात चीत हुई थी और कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिये गये थे । न ही मैंने कोई विशिष्ट प्रक्रिया प्रकट की । तथापि, उन्होंने कहा कि विकास धीमा था और वे चाहते थे कि हम विकास में तेजी लाने के लिये कदम उठायें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्होंने कहा कि विकास धीमा था । क्या विकास की गति को तेज करने के लिये उन्होंने कोई सुझाव दिये थे, और क्या उन्होंने छिपे हुए धन और कर के ढांचे के बारे में बात की थी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उन्होंने कर ढांचे के बारे में बातचीत नहीं की, परन्तु उन्होंने कहा कि विशेष रूप से निगम आदि पर बहुत अधिक है । छिपे हुए धन के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को यह आश्वासन दिया है कि वह लोकतन्त्रात्मक समाजवाद को प्राप्त करने के अपने उस उद्देश्य के लिये काम करेंगे जो सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वे उसी प्रसंग तथा उसी पृष्ठभूमि में काम करेंगे ।

Shri Bibhuti Mishra : Did they told about surrendering black money and paying taxes ?

Shri Lal Bahadur Shastri : No Sir.

श्री अ० प्र० जैन : इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिये गये किन किन सुझावों को सरकार ने अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा कि मैं ने बताया उन्होंने कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिये थे और न ही हम ने किसी को स्वीकार किया है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : हमारे देश के आर्थिक विकास के संबंध में डा० हजारिया के प्रतिवेदन पर प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि 20 चोटी के उद्योगपतियों को ही अधिक लाभ पहुंचा है और छोटे उद्योगों का विकास नहीं हुआ है क्या प्रधान मंत्री ने छोटे उद्योगों के प्रतिनिधियों से मिलने पर इस बारे में विचार किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं कुछ समझ नहीं सका । यह एक बिलकुल दूसरा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह विचार के लिये है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : प्रधान मंत्री ने अभी बताया कि उद्योगपतियों ने कोई सुझाव नहीं दिया और न ही उन्होंने कोई अपना मत प्रकट किया । क्या प्रधान मंत्री भविष्य में ऐसी बैठकों में भाग न लेने का प्रयत्न करेंगे जिन में कोई निर्णय न किया जाये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह संभव नहीं है । मैं सामान्य विचार विमर्श के लिये लोगों और प्रतिनिधि मण्डलों से मिलता हूं ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : अखबारों में खबर थी कि सभी उद्योगपति पहले प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से मिले और फिर उन में से 2 प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से अलग अलग मिले थे । क्या उन्होंने पहली और दूसरी बैठक में भिन्न भिन्न सुझाव रखे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं । वे और बातों के लिये अलग से मिले थे ।

श्री बासप्पा : क्या प्रक्रियाओं को दोषरहित करने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं आर्थिक मंत्रालयों के सचिवों से मिला था और मैं ने उनसे पूछा है कि ऐसा क्या किया जाये जिससे विलम्ब न हो । उन्होंने पहले से ही कुछ कदम उठाये हैं और कुछ और भी करना पड़ेगा ।

द्वितीय अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

*309. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्रीमती रेणुका राय :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय अफ्रीकी-एशिया सम्मेलन अल्जीयर्स में मार्च, 1965 में शुरू होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों के भाग लेने की संभावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत रूस तथा मलेशिया के सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(घ) इस सम्मेलन में किन किन मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा की जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यह प्रस्ताव किया गया है कि यह सम्मेलन 29 जून, 1965 से अल्जीयर्स में आरंभ किया जाय और इसके पहले 24 जून को विदेश मंत्रियों की बैठक हो ।

(ख) आशा की जाती है कि 64 से ले कर 66 तक स्वाधीन राष्ट्रों को निमंत्रण भेजे जायेंगे । यह प्रत्येक देश पर निर्भर करता है कि वह इसमें भाग लेने, न लेने के विषय पर निर्णय खुद करे ।

(ग) अप्रैल 1964 में जकार्ता में जो तैयारी मीटिंग हुई थी, उसमें भारत ने यह प्रस्ताव किया था कि सोवियत संघ और मलयेशिया सम्मेलन में भाग लें । इन मामलों पर वह मीटिंग कोई निर्णय नहीं ले सकी और इसलिए इस मसले पर निर्णय होना बाकी है ।

(घ) ऐसा प्रत्यार्गा की जाती है कि तैयारी मीटिंग ने पिछले साल जकार्ता में जो कार्य-सूची बनाई थी, उस पर यह सम्मेलन विचार करेगा। यह कार्य सूची तैयारी मीटिंग की अंतिम विज्ञप्ति में है जो 17 अप्रैल 1964 को लोकसभा में रखी गई थी ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को यह जानकारी है कि क्या चीन को निमन्त्रण भेजा गया है अथवा नहीं ? क्या भारत सरकार ने कार्यावलि में कुछ बातों का सुझाव दिया था और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री दिनेश सिंह : लोक सभा के पिछले सत्र में कार्यावलि पर हम अलग से चर्चा कर चुके हैं । चीन सम्मेलन की तैयारी संबंधी समिति का सदस्य था और उसको निश्चय ही निमन्त्रित किया जायेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या परमाणु शस्त्रों रहित क्षेत्र बनाने को भी कार्यावलि में रखा गया है और इस विशिष्ट बात का किन किन देशों ने समर्थन किया था ।

श्री दिनेश सिंह : कार्यावलि सभा पटल पर रख दी गई है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस सम्मेलन को हर महीने स्थगित क्यों किया जा रहा है और इसकी क्या गारंटी है कि यह सम्मेलन जून में होगा ही ? देर के क्या कारण हैं और इस सम्मेलन को बुलाने में कौन देश बाधा डाल रहे हैं ।

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं मानता कि सम्मेलन को स्थगित किया जा रहा है । इसके मार्च में होने का प्रस्ताव था । प्रबन्ध पूरे नहीं हुए थे और अब यह शायद जून में होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय प्रधान मंत्री ने इस मामले पर व्यक्तिगत विचार किया है अथवा नहीं भारत सरकार इसके लिये कहां तक प्रयत्न करेगी कि रूस इस

सम्मेलन में भाग ले और यदि भारत द्वारा रखी गई उचित मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो क्या भारत सरकार इस सम्मेलन में भाग न लेने के लिये तैयार है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी नहीं ; अभी तक हम ने यह नीति नहीं अपनाई है । परन्तु हम देखेंगे कि अन्य देशों की क्या प्रतिक्रियायें होती हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारे विदेश उपमंत्री ने हाल ही में अनेक अफ्रीकी देशों का दौरा किया था । इस सम्मेलन में रूस और मलेशिया के भाग लेने के सम्बन्ध में क्या उन्होंने कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो उनके अनुमान क्या हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हां, इस मामले में मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी । चर्चा के निश्चित ब्योरे बताना मेरे लिये कठिन होगा, परन्तु मैं समझता हूं कि रूस और मलेशिया दोनों को सम्मेलन में बुलाने का समर्थन किया जा रहा है ; यद्यपि, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं मलेशिया और रूस दोनों के आधार समान नहीं हैं—दोनों के लिए समर्थन है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सार्वजनिक रेडियो सेट

*310. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपालसिंह :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना प्रचार सम्बन्धी अध्ययन दल ने सूचना दी है कि राज्यों/संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों को दिये गये सार्वजनिक रेडियो सेंटों में से लगभग 40 प्रतिशत सेट उपयोग नहीं किये गये ; और

(ख) यदि हां, तो इन सेटों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) पंचायती रेडियो सेटों की देख रेख और चालू रखने के जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । फिर भी, इस बात का पूरा विवरण एकत्रित किया जा रहा है कि राज्यों में इस काम के लिए क्या प्रबन्ध है ताकि इससे जो दोष दिखाई दें उनको दूर करने का उपाय किया जा सके ।

मजगांव नौ स्थानों का आधुनिकीकरण

†311. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेडा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० व० राघवन् :
श्री पोट्टकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1964 में प्रतिरक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन के विभिन्न समवायों के प्रतिनिधियों के साथ मजगांव नौ-स्थान के आधुनिकीकरण और युद्धपोत बनाने की नौ-सेना की योजनाओं की तकनीकी पहलुओं पर बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) मज़गाव डाक लिमिटेड, बम्बई में फ्रिगेट के निर्माण के लिए करार को अन्तिम रूप देने के लिए 17 से 22 दिसम्बर, 1964 तक विकर्ज आर्मस्ट्रांग (जलपोत निर्माताओं) लि० और यैरों एंड कम्पनी लि० से बातचीत की गई थी, यह दोनों फर्में यू० के० की हैं ।

(ख) 22–12–64 को निम्न तीन करारनामों पर हतास्क्षर हुए थे :—

(1) भारत में लिएण्डर किस्म के तीन एफ० एस० ए० 34 फ्रिगेटों का निर्माण करने के लिए तकनीकी सहायता देने के लिए ;

(2) पहले फ्रिगेट के लिए बिकर्ज यैरों निर्माण की मदों के प्रदाय के लिए ;

(3) यू० के० से समग्रत: खरीदी गई मदों के क्रय के लिए ।

संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

*312. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेडा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राधेलाल व्यास :
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि 28 दिसम्बर, 1964 को पुंछ क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों के एक दल पर पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्रों के सैनिक पर्यवेक्षक अपने साथ हथियार लेकर नहीं फिरते । नीली टोपी सहित उनकी वर्दी, तथा उन द्वारा साथ लिया झंड़ा उन्हें संयुक्त राष्ट्रों के पर्यवेक्षकों के तौर पर पहचानने के लिए काफी है । उनके लिए सशस्त्र सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और न ही प्राप्य ही की जाती है, क्योंकि उनका काम है, युद्धबन्दी व्यवस्थाओं का पालन निश्चित करना ।

उपरोक्त किस्म की गोलाबारी की हालत में, मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक, जिसे स्थिति की जानकारी होगी, पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मामला उठाने को तैयार है ।

विदेशों में प्रचार

*313. श्री कृ० च० पन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० च० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में प्रचार व्यवस्था के पुनर्गठन के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश प्रचार व्यवस्था तथा देश प्रचार व्यवस्था में समन्वय लाने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग). भारत में और विदेशों में, हमारी विदेश नीति के सम्बन्ध में प्रचार को प्रभावकारी बनाने के तरीकों को सुधारने के प्रश्न पर बराबर विचार होता रहता है । इस सम्बन्ध में, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच विचार विनिमय हुआ है । यह निर्णय किया गया है कि विदेश सचिव और सूचना तथा प्रसारण सचिव की समन्वयन समिति उन विभिन्न बातों पर विचार करे जो उठाई गई है और आम तौर पर हमारी विदेश नीति को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करे तथा आंतरिक और विदेश प्रचार के बीच सम्पर्क स्थापित करे।

नेहरू स्मारक निधि के लिये मनीआर्डर कमीशन

*314. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **संचार** मंत्री 21 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 600 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीआर्डर कमीशन की छूट देने से नेहरू स्मारक निधि के अंशदान में फाफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो लगभग कितनी अथवा किस अनुपात से वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या पहले अन्य निधियों के अंशदानों के लिए भी, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा निधि के अंशदान के लिये, ऐसी छूट दी गई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रमुख

*315. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी विदेश सेवा में राजनयिक मिशनों के प्रमुख के रूप में आजकल वृत्तिक राजनयिक और सरकारी कर्मचारी किस अनुपात में हैं ; और

(ख) क्या सरकार हमारे मिशनों के प्रमुखों के रूप में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) इस समय मिशन प्रमुखों के रूप में 37 ऐसे वृत्तिक राजनयिक हैं जो एक या एक से अधिक देशों में नियुक्त हैं ; 8 अन्य सेवाओं के हैं और 8 मिशन में प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति हैं।

(ख) मिशन प्रमुखों के पदों पर नियुक्तियां करना प्रधान मंत्री के अधिकार में है जो विदेश मंत्री की सलाह से यह काम करते हैं। सरकार साधारण जनता के लोगों को भी ऐसे पदों पर नियुक्त करती है कि जिसके लिए उनका अनुभव विशेष रूप से उपयुक्त समझा जाता हो, और उसका इस नीति पर चलते रहने का विचार है।

अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह, दिल्ली

*316. **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री उ० म० त्रिवेदी :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० देव :
श्री नरसिम्हा ड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह के दौरान संसत्सदस्यों को कुछ चलचित्रों के विशेष पूर्वदर्शन नहीं दिखाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) अन्य किन श्रेणियों के व्यक्तियों को ये चलचित्र देखने के लिए आमंत्रित किया गया था?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ग) निर्णायकों और परीक्षण समिति के सदस्यों के लिए पहले से या विशेष रूप से दिखाने के अलावा जो उनके काम के लिए आवश्यक था, केवल निम्नलिखित शो ही किए गए।

1. संसद् सदस्यों के लिए विज्ञान भवन में 11 शो।
2. अखबार वालों के लिये तीन फिल्में। इनको देखने के लिए केवल पत्र प्रतिनिधि ही निमंत्रित किये गये थे ।

(ख) प्रेस शो फिल्म विभाग के आडिटोरियम में किए गए जिसमें बैठने की जगह थोड़ी है, अतः और लोगों को निमंत्रण देना सम्भव नहीं था।

चीन द्वारा हिमालय संघ की रचना

*317. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल, भूटान तथा सिक्किम को मिला कर चीन के नेतृत्व में एक हिमालय संघ बनाने की चीन की योजना की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या चीन के साथ भूटान तथा सिक्किम की सीमा को चीन के नक्शों में सही रूप में दिखाया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) चीन के नेतृत्व में नेपाल, भूटान और सिक्किम को मिलाकर तथाकथित हिमालय संघ बनाने की चीन की किसी योजना के बारे में सरकार को मालूम नहीं ।

(ख) चीन सरकार ने अपने 26 दिसम्बर, 1959 के पत्र में कहा : "चीन और भूटान के मध्यवर्ती सीमा के बारे में दोनों पक्षों (भारत और चीन) के नक्शों में तथाकथित मैकमोहन रेखा के दक्षिणी क्षेत्र के चित्रण में ही कुछ अन्तर है । चीन और सिक्किम के बीच की सीमा बहुत पहले ही बाक़ायदा सीमांकित की जा चुकी है और न तो दोनों के नक्शों में ही कोई अन्तर न व्यवहार ही में ।" जहां तक भारतीय और चीनी नक्शों में भूटान-चीनी सीमा के चित्रण के अन्तर का प्रश्न है, यह अन्तर भारत की उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी और मैकमोहन रेखा के दक्षिण में लगने वाले भूटान के दक्षिण-पूर्वी भाग में है ।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

*318. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री गुलशन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक कामों पर लगाने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, क्या इसे कार्यान्वित करने का कार्य प्रतिरक्षा मंत्रालय करता है अथवा सेना मुख्यालय ; और

(ग) 1964 में नौसेना, सेना तथा वायु सेना के कितने कितने भूतपूर्व सनिकों को लगाया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सरकार ने असैनिक रोजगारों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कई उपाय किए हैं और अन्य उपाय विचाराधीन । इन उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या 3937/65]**

(ग) सरकार के पास सूचना के अनुसार नौसेना के 103, थलसेना के 8739 और वायु सेना के 43 भूतपूर्व सैनिकों को 1964 के दौरान रोज़गार दिया गया ।

नेफा में औद्योगिक विकास की सम्भावना

*319. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की परिषद् ने नेफा में औद्योगिक विकास की संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए कोई तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारण किया गया है ; और

(ग) छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना करने के लिए वहां पर स्थानीय रूप से कितनी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण का उद्देश्य यह है कि नेफा में आर्थिक और उद्योग सम्बन्धी संभावनाओं का पता लगाया जाय । सर्वेक्षण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और इस कारण किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचा गया है ।

उपभोक्ता मूल्य देशनांक

*320. **डा० उ० मिश्र** :
डा० रानेन सेन :
श्री दाजी :
श्री वारियर :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रों के श्रमिक वर्ग के विषय में उपभोक्ता मूल्य देशनांकों की श्रम ब्यूरो सीरीज तैयार किये जाने के बारे में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर विचार करने के लिए क्या सरकार का एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). दिल्ली केन्द्र के लिए, जो कि श्रम ब्यरो केन्द्रों में से एक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1944–100) की पुरानी सीरीज़ की जांच-पड़ताल करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति पहले ही स्थापित की गई है। दिल्ली विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों को जानने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि आया ब्यूरो के शेष 14 केन्द्रों की जांच-पड़ताल करने के लिए इसी प्रकार की विशेषज्ञ समिति/समितियों की स्थापना की जानी चाहिए।

युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन

*321. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि 23 फरवरी, 1965 को पाकिस्तानी सेनाओं ने जम्मू और काश्मीर राज्य के पूंछ के स्थान पर युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया ;

(ख) क्या पाकिस्तानी सेनाओं ने बहुत गोली चलाई ;

(ग) यदि हां, तो कितने भारतीय हताहत हुए ; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पुंछ में 23 फरवरी, 1965 को कोई ऐसी घटना नहीं घटी ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन की रोक-थाम के लिये आवश्यक एहतियाती उपाय किये गये हैं और जारी हैं ।

चीनी हथियारों का पाकिस्तान ले जाया जाना

*322. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मार्टर और दूसरे छोटे हथियार 12 और 26 अक्तूबर, 1964 को भारी संख्या में भारतीय रेलवे के हल्दीबाड़ी स्टेशन के रास्ते चीन से पूर्वी पाकिस्तान गए थे ;

(ख) यदि हां, तो यह सामान भेजने के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी था और किस एजेंसी ने सामान भेजा था ; और

(ग) क्या अपराधियों को पकड़ने और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के निकट चीन की नौकायें

323. श्री रामनाथन् चेट्टियार :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ल० ना० भंजदेव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अंदमान कांग्रेस समिति के प्रधान द्वारा नई दिल्ली में पिछली जनवरी में दिये गये इस प्रेस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चीन के सैनिक अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी कोणपर प्रायः अवैध प्रवेश करते रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने द्वीप समूह के तटीय क्षेत्र में गश्ती दस्तों को मजबूत बनाने के लिये आवश्यक उपाय किये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तथा (ख). जी हां।

पाकिस्तान में हाल में हुए चुनाव

*324. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत सरकार से शिकायत की है कि पाकिस्तान में हाल में हुए चुनावों में भारत का हाथ था ;

(ख) यदि हां, तो भारत पर मुख्य रूप से क्या आरोप लगाए गए थे ;

(ग) पाकिस्तान सरकार को क्या उत्तर दिया गया है ; और

(घ) पाकिस्तान सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). जी नहीं। औपचारिक रूप से कोई विरोध-पत्र नहीं मिला लेकिन भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तानी चुनावों में आल इंडिया रेडियो के तथाकथित हस्तक्षेप के प्रमाण के रूप में आल इंडिया रेडियो के प्रसारणों से कुछ उद्धरण" छोड़ गए थे।

(ग) पाकिस्तान के कार्यकारी हाई कमिश्नर को एक पत्र दिया गया जिसमें आल इंडिया रेडियो के असली प्रसारण का उल्लेख था। इस पत्र में यह बताया गया था कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर द्वारा छोड़े गये तथाकथित उद्धरण या तो प्रसारण के गलत अनुवाद थे अथवा उसे तोड़ा-मरोड़ा गया था। एक 'उद्धरण' तो कतई मनगढ़ंत था।

(घ) पाकिस्तान सरकार इसी प्रकार के निराधार आरोप लगाती रहती है।

राजनयिक पदों पर नियुक्तियां

*325. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यश पाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा ऐसोसियेशन की ओर से हाल ही में उन से एक शिष्टमंडल मिला था और उसने सीनियर राजनयिक पदों पर राजनीतिज्ञों तथा सेवा निवृत

सीनियर सैनिक अधिकारियों को नियुक्ति करने की सरकार की नई नीति के विरुद्ध शिकायत की थी, जो भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों की मिशनों के प्रमुखों के रूप में सामान्य पदोन्नति के रास्ते में बाधक थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) भारतीय विदेश सेवा (इंडियन फारेन सर्विस) एसोसियेशन की ओर से एक शिष्टमंडल विदेश मंत्री से मिला था और उसने दूसरी सेवाओं के सेवा-निवृत्त और सेवारत सदस्यों को–जिनमें सशस्त्र सेना के सदस्य भी शामिल हैं–बड़े-बड़े राजनयिक पदों पर नियुक्त करने की नीति पर आपत्ति प्रकट की थी; परन्तु, जनता के विशिष्ट व्यक्तियों को ऐसे पदों पर नियुक्त करने के सरकार के अधिकार पर एसोसियेशन ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की ।

(ख) इस मामले पर, और एसोसियेशन ने नौकरी की शर्तों के विषय में जो अन्य मामले उठाए थे, उन पर भी विदेश मंत्रालय विचार कर रहा है ।

जम्मू और काश्मीर पर संवैधानिक उपबन्धों का लागू किया जाना

*326. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने जम्मू और काश्मीर पर राष्ट्रपति का शासन लागू करने वाले संवैधानिक उपबन्ध को लागू करने के कारण कोई बदले की भावना से कार्यवाही करने के निणय की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ग) उन के इस रवैये पर सरकार कीं प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) (क) से (ग). इस विषय पर पाकिस्तान सरकार का नोट और हमारा उत्तर सदन की मेज पर रख दिया गया है ।
[पुस्तकालय में रखा गया दखिय संख्या एल० टी० 3938/65]

इन्डोनेशिया-मलयेशिया विवाद

*327. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम सेवक यादव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा डुडी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया और इन्डोनेशिया की सरकारों ने अपने पारस्परिक विवाद में भारत से नैतिक अथवा भौतिक सहानभूति, समर्थन तथा सहायता के लिये निवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) किसी विशेष रूप में नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में भारतीय मिशन

*328. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में भारत के सब से बड़े तथा सब से छोटे राजनयिक मिशन कौन से हैं ;

(ख) प्रत्येक मिशन में कर्मचारियों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उन पर कितने समय के पश्चात पुनर्विचार किया जाता है ; और

(ग) क्या यह अनुभव किया गया है कि हमारे बड़े बड़े राजनयिक मिशन अधिकाधिक बड़े होते जाते हैं और उस वृद्धि के अनुरूप लाभ नहीं होता है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) विदेश-स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों में सबसे बड़ा मिशन लंदन-स्थित भारत का हाई कमीशन है और सबसे छोटा डुबाई-स्थित भारतीय व्यापार एजेंसी ।

(ख) जब कोई नया मिशन खोला जाता है तो उसके कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या स्थिर कर दी जाती है । अस्थायी पदों को अगले वित्तीय वर्ष में बनाए रखने की स्वीकृति देते समय, वर्ष में एक बार, कर्मचारियों की इस स्थिर संख्या की समीक्षा की जाती है ।

यह समीक्षा मिशन विशेष के पिछले वर्ष के वास्तविक काम के बोझ के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। विदेश सेवा इन्स्पेक्टर भी निश्चित अवधि के बाद नियमित रूप से मौक़े पर समीक्षा करते रहते हैं।

(ग) जी नहीं। ऐसा कभी महसूस नहीं किया गया कि हमारे बड़े-बड़े मिशन और बड़े होते जा रहे, हैं और इस वृद्धि के अनुरूप लाभ नहीं हो रहा है। परन्तु, इस मंत्रालय में एक विशेष पुनर्गठन समिति बनाई गई थी जो विदेश-स्थित मिशनों में कर्मचारियों की संख्या में न्यायोचित कमी बेशी करने के उद्देश्य से उनके कर्मचारियों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करती रहती है।

अल्पकालीन सेवा के लिये भर्ती

*329. **श्रीमती शारदा मुखर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात-काल की घोषणा के पश्चात सशस्त्र सेनाओं में अल्पकालीन सेवा के लिए भारी संख्या में भर्ती की गई थी ;

(ख) क्या यह भर्ती मुख्यतया अधिकारी केडर में की गई थी या अन्य केडरों में भी ; और

(ग) अल्पकालीन सेवा तथा स्थायी नियुक्तियों की शर्तों में मुख्य अन्तर क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री श्री (यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। परन्तु यह भर्ती केवल थल-सेना के लिए की गई है।

(ख) अधिकतर आफिसर काडर में ही।

(ग) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 3939/65]**

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना

*330. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 फरवरी से 21 फरवरी, 1965 तक नौशेरा क्षेत्र में भारतीय सीमा पर तैनात भारतीय गश्ती टुकड़ी के साथ हुई विभिन्न मुठभेड़ों में तीन पाकिस्तानी सिपाही मारे गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मीडियम और लाइट मशीन गनों और राकेट-लांचर्स से लगभग 6,000 गोलियां चलाई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). 19 से 21 फरवरी 1965 तक नौशरा क्षेत्र में 12 घटनाएं हुई थी, जिनमें पाकिस्तानियों ने हमारी चौकियां, पिकटों और गश्ती दस्तों पर गोलियां चलाई थीं। इन घटनाओं में उन्होंने मध्यम मशीनगनों, हल्की मशीनगनों, 2 इंच मार्टरों, राइफल से दागे जाने वाले ग्रेनेडों इत्यादि का प्रयोग किया था। पाकिस्तानियों ने कुल कितनी गोलियां चलाई, मालूम नहीं। हम ने उस हद तक, गोली का जवाब गोली से दिया, जहां तक आवश्यक समझा गया। जहां तक, पाकिस्तानी हताहतों का प्रश्न है, सरकार को ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। हमारी ओर कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) युद्ध बदी के उल्लंघनों के संबंध में, उन सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्रों के पर्यवेक्षकों को शिकायतें कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त एहतियाती उपाय भी किए गए हैं।

बर्मा से भारतीयों की वापसी

*331. श्री रामनाथन् चेट्टियार :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 7 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 381 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 नवम्बर, 1964 से अब तक कितने भारतीय बर्मा से वापिस लाये गये हैं ;

(ख) बर्मा से उनकी सम्पत्ति जिसमें नकदी तथा जेवर भी शामिल हैं वापिस लाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) लगभग 11,416.

(ख) बर्मा छोड़कर आने वाले भारतीयों की परिसम्पत्ति लौटाने के प्रश्न पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है ।

EMPLOYEES IN INDIAN HIGH COMMISSION, LONDON

735. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of employees working in the Indian High Commission, London from 1959-60 to 1964-65 (upto 28th February, 1965) ;

(*b*) whether any steps have been or are proposed to be taken to reduce the number of staff ;

(*c*) if so, the details thereof and also the results achieved, and

(*d*) the annual expenditure incurred during this period ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) :

(*a*)

1959-60 :	1316
1960-61 :	1178
1961-62 :	1152
1962-63 :	1048
1963-64 :	959
1964-65 : (upto 28-2-1965).	948

(*b*) Yes ; steps have been and continue to be taken to reduce the strength of the staff.

(*c*) A team of the Special Reorganisation Unit was commissioned in 1958-59 to review the staff-strength in the High Commission. On the Unit's recommendations, the strength of the staff was reduced from 1316 in 1959-60 to 1178 in 1960-61.

(*ii*) In 1961, Shri M. J. Desai then Foreign Secretary undertook a further investigation. On the basis of his survey, the staff-strength was further reduced to 1152 in 1961-62.

(*iii*) Still later, in 1962, Shri T. Sivasankar, Secretary, Ministry of Works Housing and Supply reviewed the staff position in the India Store Department and the number of the staff was reduced to 1048.

(*iv*) On the recommendations of the Special Reorganisation Unit, the High Commission have set up an Economy Board to keep a constant watch or the methods of work and staff requirements with reference to increase or decrease of the work load. Consequently, there has been a further reduction in staff, the present strength being 948.

(*d*)

1959-60 . . .	£ 1,646,574
1960-61 . . .	£ 1,503,273
1961-62 . . .	£ 1,430,799
1962-63 . . .	£ 1,427,984
1963-64 . . .	£ 1,489,035
1964-65 (up to 31-1-65)	£ 1,151,141

रेडियो व्यय को तार व्यय के साथ मिलाना

736. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि रेडियो व्यय को तार अथवा टेलीफोन व्यय के साथ मिलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी हां। डाक-तार विभाग की रेडियो शाखा के लेखों को (देश के भीतर की संचार-व्यवस्था के लिए) तार शाखा के लेखों से मिलाने का प्रश्न विचारधीन है ।

(ख) इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

लोक नर्तकों के लिए पुरस्कार

737. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के गणतन्त्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले लोक नर्तकों को किस आधार पर तथा किस पैमाने पर पुरस्कार दिये गये ; और

(ख) इस समारोह में किस राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) दिल्ली में 1965 के गणतन्त्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले लोक नर्तकों को कोई इनाम नहीं दिए गए थे ; नर्तकदलों के लिए कोई इनामी प्रतियोगिता आयित नहीं की गई थी। गणतन्त्र दिवस परेड की सांस्कृतिक शोभा-यात्रा में भाग लेने वाली झांकियों में से क्रमशः राजस्थान और गोवा, दमन तथा दीव सरकारों की झांकियां सर्वश्रेष्ठ और द्वितीय श्रेष्ठ मानी गई थीं ।

राज्यों से आने वाले सभी दलों के उन सदस्यों को पहले वर्षों के लिए, सामारिकाएं प्रदान की गईं थीं जो लोक नृत्य समारोह में भाग लेने के लिए आए थे, अथवा जिन्होंने झांकियों के प्रदर्शन के लिए उन पर काम किया ।

स्वतन्त्रता दिवस पर व्यय

738. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **1962, 1963 और 1964** में स्वतन्त्रता दिवस समारोह पर केन्द्र ने कितना व्यय किया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : स्वतन्त्रता दिवस पर दिल्ली में मनाये गये उत्सवों पर केन्द्र की तरफ से पिछले तीन साल में जो खर्चा हुआ, वह इस प्रकार था :—

1962	25,400 रुपये ।
1963	26,900 रुपये ।
1964	21,800 रुपये ।

बिना लाइसेंस के रेडियो

739 { **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग ने (राज्यवार) **1964** में कितने बिना लाइसैंस के रेडियो सेटों का पता लगाया ; और

(ख) बिना लाइसैंस के रेडियो सेट रखने के क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) 1964 में समूचे भारत में बिना लाइसैंस के 85985 रेडियो सेटों का पता लगाया गया था । इस संख्या का राज्यवार ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य-संघीय प्रदेश का नाम	1964 के दौरान पकड़े जाने वाले अनधिकृत रेडियो सेटों की कुल संख्या
1. आंध्र . . .	2634
2. आसाम . . .	1472
3. बिहार . . .	5317
4. दिल्ली . . .	5556
5. गोआ . . .	609
6. गुजरात . . .	4283
7. हिमाचल प्रदेश . .	871
8. जम्मू तथा काश्मीर . .	1816
9. केरल . . .	1963
10. मद्रास . . .	12344
11. मध्य प्रदेश . . .	1908
12. महाराष्ट्र . . .	6549
13. मैसूर . . .	2546
14. उड़ीसा . . .	396
15. पंजाब . . .	11933
16. राजस्थान . . .	5979
17. उत्तर प्रदेश .	12458
18. पश्चिम बंगाल . .	7151
कुल योग .	85985

(ख) कारण ये हैं :—

खरीद या स्थानान्तरण के एक सप्ताह के भीतर और सीमाशुल्क कार्यालय से निकासी के 30 दिन के भीतर लाइसैंस अवश्य ही प्राप्त कर लिये जाने चाहिऐ । जो व्यक्ति यह प्रमाण नहीं दे सकते या भूल जाते हैं या लाइसेंस-शुल्क देने से बचना चाहते हैं वे ही आमतौर पर जब तक छापा न मारा जाए लाइसेंस नहीं लेते ।

भारत-अरब सम्बन्धों पर गोष्ठी

740. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब राष्ट्रों तथा भारत सम्बन्धी गोष्ठी की बैठक अब समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अरब देशों के बीच अधिक सहयोग स्थापित करने के बारे में समिति ने क्या सिफारिश की है ; और

(ग) उन सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अरब संसार और भारत विषयक गोष्ठी का समारम्भ 15 फरवरी को हुआ और वह 20 फरवरी, 1965 को समाप्त हुई।

(ख) गोष्ठी में कई सिफारिशें की गई जिनमें एक प्रमुख सिफारिश यह है कि साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि से सम्बद्ध भारतीय अध्ययन केन्द्र अरब संसार में खोले जायें और ऐसे ही अरब अध्ययन केन्द्र भारत में खोले जाएं । गोष्ठी की सिफारिशें प्रकाशित कर दी गई है और वे भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद से प्राप्त की जा सकती है ।

(ग) एक सम्पादकीय समिति स्थापित कर दी गई है जो यह बतायेगी कि विभिन्न सिफारिशों पर अमल करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएं ।

नौ सेना के जहाज का दुर्घटनाग्रस्त होना

741. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जनवरी, 1965 को नौसेना का एक जहाज गोआ के समीप समुद्र में डूब गया था ;

(ख) यदि हां, तो उससे जान व माल की कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या दुर्घटना के कारण की जांच पड़ताल करने के लिए किसी जांच बोर्ड की नियुक्ति की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जान या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विमान पूरी तरह नष्ट हो गया है ।

(ग) तथा (घ). जी हां । बोर्ड आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में गबन

742. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964 में दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के ट्रंक एक्सचैंज में वेतन तथा भत्तों का अधिक भुगतान किया गया ;

(ख) यदि हां, तो ये अधिक भुगतान किस प्रकार किये गये और इनकी अनुमानित राशि कितनी है और ;

(ग) क्या मामले की कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी नहां।

(ख) अधिक भुगतान करने का तरीका यही था कि कुछ कर्मचारियों को ड्यटी वेतन दिया गया हालांकि वे कुछ मौकों पर छुट्टी पर थे। अभी तक पता चली अधिक भुगतान की ,अनुमानित रकम 11,300 रुपये है।

(ग) पहले पहल प्राथमिक विभागीय जांच की गई। अब व्यापक रूप से विभागीय जांच की जा रही है। इस मामले की सूचना विशेष पुलिस सिबन्दी (स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट) को भी दी गई थी और उनके द्वारा की जा रही जांच चल रही है।

उदवभरक प्रणाली

743. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्दरगाहों में उदवभरक प्रणाली समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). अभी तक मामला विचाराधीन है ।

अन्तर्देशीय पत्र और विदेशों के लिये हवाई डाक पत्र

744. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपालसिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग ने अन्तर्देशीय पत्रों और विदेशों के लिये हवाई डाक-पत्रों के नये डिजाइन मंजूर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मूल्य में कोई परिवर्तन होगा ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा । फिर भी, बेहतर किस्म की स्टेशनरी की व्यवस्था के लिए विभाग को कुछ अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा ।

New Aerodrome in New Delhi

745. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) the progress made in the construction of the new aerodrome for I.A.F. in the Capital ;

(*b*) the estimated expenditure involved and the amount spent so far; and

(*c*) when this aerodrome is expected to be ready for operation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju) : (*a*) The work on the construction of the runway and taxi track has been completed. The overall progress regarding the execution of the remaining works services, which were sanctioned in Phase I, is about 75%.

(*b*) The rough cost of the entire project is estimated to be Rs. 5·11 crores. Out of this amount, an expenditure of Rs. 3,14,23,000/- was booked upto the end of January 1965.

(*c*) Efforts are being made to commission the airfield before the onset of the coming monsoon.

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश

746. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले औद्योगिक कमचारियों को उपार्जित अवकाश देने सम्बन्धी वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है । चूंकि यह मामला एक व्यापक किस्म का है, इस पर रक्षा मंत्रालय में कोई इकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता ।

प्रबन्ध में मजदूरों का प्रतिनिधित्व

747. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समवायों में शेयरों के क्रय द्वारा मजदूरों को उद्योगों के प्रबन्ध

में प्रतिनिधित्व देने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है। लेकिन इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठना।

हिन्द महासागर में परमाणु अस्त्रों से लैस जहाज

748 **श्री प्रभातकार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर के शान्त जल-प्राँगण में परमाणु अस्त्रों से सज्जित जहाजों और पोलेरिस पनडुब्डी के प्रवेश के विरूद्ध ऐशियाई और अफ्रीकी देशों द्वारा संयुक्त कार्यवाही आरम्भ करने का प्रश्न उठाने के बारे में विचार किया है ;

(ख) क्या भारत ने ऐशिया और अफ्रीका में सम्बन्धित सरकारों से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उन सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। फिर भी हिन्द महासागर में विदेशी युद्धपोतों के आवागमन की सम्भावना के सामान्य प्रश्न पर सरकार बराबर विचार कर रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर्मी रिजर्विस्ट्स की पेंशन

749. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन, तथा अधिक निर्वाह-व्यय के कारण आर्मी रिजर्विस्ट्स को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी पैंशन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तथा (ख): बढ़े चढ़े निर्वाह खर्च से सभी ग्रस्त हैं, विशेषकर के थोड़ी आय वाले। सैनिक रिजर्विस्ट वह व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी सेना में सक्रिय सेवा समाप्त कर लेने पर, जो आमतौर पर (बढ़ाए न जाने पर) 7, 10 या 12 वर्ष की होती थी, तुलना में छोटी आयु में रिजर्व में अन्तरित कर दिया गया था,और वह ऐसी तबदीली की तिथि से ही कोई अन्य रोज़गार कर सकते थे। अगर किसी सैनिक रिजर्विस्ट ने 15 वर्ष की कम से कम सेवा सम्पूर्णन की हो, जो पेंशन पाने का अधिकारी वर्ग केलिए आवश्यक है, तो नई पेंशन पद्धति के अंतर्गत, निर्धारित सक्रिय तथा रिज़र्व सेवा सम्पूर्ण करने पर वह या तो 10 से 12 रुपये मासिक तक की पेन्शन का अधिकारी है, 5 रूपये मासिक तदर्थ वृद्धिसहित, या उसके बदले उनकी सक्रिय तथा रिज़र्व सेवा में नियुक्ति की शर्तों पर आधारित 750 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के उपदान का। रिजर्विस्टों की पेन्शन दर बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

भारतीय उच्चायोग, पाकिस्तान में द्वितीय सचिव

750. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने, करांची में भारतीय उच्चायोग के द्वितीय सचिव, श्री बी० एन० जोशी पर, जिन्हें पाकिस्तान की मांग पर वापिस बुला लिया गया था, लगाये गए आरोपों का खण्डन करते हुए पाकिस्तान को विरोध-पत्र भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) पाकिस्तान सरकार ने क्या आरोप लगाए थे और भारत ने अपने विरोध-पत्र में उनका किस प्रकासे रखण्डन किया ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह):(क) जी हां । पाकिस्तान सरकार के पास एक विरोध-पत्र भेजा गया था जिसमें उन आरोपों का खंडन किया गया जो उन्होंने हमारे अधिकारी के खिलाफ लगाए थे ।

(ख) पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने हमारे विरोध-पत्र को अस्वीकार कर दिया और यह आरोप लगाया कि भारत को जैसे ही यह मालूम हुआ कि पाकिस्तान सरकार श्री जोशी को वापस बुलाने के लिए कह सकती है वैसे ही उसने पाकिस्तान के द्वितीय सचिव पर "झूठे" आरोप लगा दिए।

(ग) उन्होंने यह आरोप लगाया कि श्री जोशी ने जासूसी और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में हिस्सा लिया है । इस आरोप का खंडन करते हुए, भारतीय हाई कमीशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने बदले की भावना से श्री जोशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है । यह उस घटना-क्रम से बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि पाकिस्तान ने हमसे अपने अधिकारी को वापस बुला लेने के लिए कहा ।

अरब फिल्म समारोह

751. श्री रामेश्वर टांटिया: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में फरवरी, 1965 में अरब फिल्म समारोह हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो समारोह में कितने अरब देशों ने भाग लिया ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य में मार्च से भारतीय फिल्म समारोह भी होने बाला है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :(क) और (ख) जी, नहीं । प्रश्न शायद फ़रवरी में संयुक्त अरब गणराज्य की फिल्मों का समारोह करने की तजवीज़ के बारे में है । यह स्थगित किया जा चका है ।

(ग) संयुक्त राज्य अरब गणराज्य में मार्च, 1965 में होने वाले भारतीय फ़िल्म समारोह को भी स्थगित कर दिया गया है ।

कलकत्ता में इन्दोनेशिया का वाणिज्य दूतावास

752. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विगे :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम पुरे :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दोनेशिया सरकार ने कलक्त्ता में अपना वाणिज्य दूतावास बन्द करने की इच्छा के बारे में भारत सरकार को सूचना दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्दोनेशिया सरकार ने ऐसा निर्णय करने के क्या कारण बताये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। इन्डोनेशिया की सरकार ने किफायत की दृष्टि से कलक्त्ता में अपना कोंसलावास बन्द कर दिया ।

काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक

753. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने के संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के बारे में 23 नवम्बर 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर 1964 के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह): दिसम्बर 1964 के समाप्त होने से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या में चार की वृद्धि कर दी गई है । जम्मू तथा काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की वर्तमान संख्या 43 है जबकि उनकी कुल अधिकृत संख्या 45 है ।

ग्रामीण रोजगार दफ्तर

754. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देहातों में अपूर्ण रोजगार की समस्या को हल करने के लिये चुने हुए कुछ सामुदायिक विकास खण्डों में निकट भविष्य में काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण रोजगार दफ्तर खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रयोजन के लिये सामुदायिक विकास खण्डों को किस आधार पर चुना जाता है ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) अब तक चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में, 190 रोजगार सूचना और सहायता केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकारों की सलाह से इन केन्द्रों के पुनर्गठन और विकास की, जांच की जा रही है ।

Telephones in Delhi

755. Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications pending at present for installation of telephones in Delhi ; and

(b) the time likely to be taken for providing telephones to them ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) 36,648 as on 1-2-1965.

(b) To meet the pending demand and the new demand that is being generated, the capacity of the telephone exchanges and the external Cable Plant in the Delhi Telephone System is being continuously expanded to the maximum extent possible consistant with the available resources. Connections are being provided at a fast rate and this tempo would be gradually increased. It is difficult to indicate the exact time limit by which all the pending applicants are likely to be provided with telephones.

Employment for Retired Soldiers

756. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the number of ex-Servicemen who have been provided with employment by Government during the last four years ;

(b) the number of ex-Servicemen who are employed in the private sector; and

(c) the total number of such ex-Servicemen who are still fit for active service.

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D.S. Raju): (*a*) According to information with Government 34,284, including 194 ex-service officers.

(b) According to information with Government 2,698, including 30 ex-service officers.

(c) The information is not available. The time and labour involved in collecting it will not be commensurate with the result achieved.

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार

*757. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार व्यवस्था की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के बारे में अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था में कौन सी कमियों का पता लगा है ; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार व्यवस्था में वृद्धि करने के बारे में क्या योजना बनाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तफसील में कोई जांच नहीं की गयी है, लेकिन सीमा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार के सभी पहलुओं पर एक प्रशिक्षण और दिग्दर्शन शिवर में विचार किया गया जो विशेषत: इसी काम के लिये अक्तूबर, 1964 में नैनीताल में लगाया गया था ।

(ख) अनुभव किया गया है कि इन क्षेत्रों में प्रचार का काम और तेज़ करने की आवश्यकता है ।

(ग) इन क्षेत्रों में वर्तमान क्षेत्रीय प्रचार संगठन को, काफ़ी बढ़ाने पर विचार हो रहा है । सीमा क्षेत्रों के लिये और बढ़िया और अधिक कार्य-क्रम प्रसारित किये जा रहे हैं और ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि इन क्षेत्रों के श्रोताओं को वे और अच्छी तरह सुनाई दें ।

स्वर्गीय पं० नेहरू के जीवन सम्बन्धी प्रदर्शनी

758. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन सम्बन्धी प्रदर्शनी का न्यूयार्क में हाल ही में उद्घाटन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्घाटन उत्सव पर सूचना और प्रसारण मंत्री भी उपस्थित थीं ; और

(ग) उसमें स्वर्गीय श्री नेहरू के जीवन के किन विशेष पहलुओं का चित्रण किया गया था और क्या इस विषय में सरकार से परामर्श किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) श्री नेहरू के जीवन के निम्नलिखित पहलुओं को दर्शाया गया था :

1. नेहरू, उनका जीवन और उनका भारत ।
2. भारत जिसमें वह जन्मे ।
3 भारत की खोज ।
4. स्वतंत्रता संग्राम की ओर ।
5. वर्षों जेल में ।
6. स्वाधीनता ।
7. एक देश विभाजित हुआ ।
8. स्वतंत्र विदेश नीति ।
9. लोगों के साथ ।
10. बच्चों के साथ ।
11. उपलब्धियां ।
12. अधूरा काम ।
13. वसीयत ।

भस्मि का बखेरना, इतिहास दर्शक भित्ति (1880 से 1964 तक) भारत तथा विश्व की घटनाओं को सचित्र अनुक्रमणिका (इलस्ट्रेटड इन्डेक्स)

14. विश्व की श्रद्धांजलि ।
15. गांधी मंडप ।

भारत सरकार ने नेहरू स्मारक प्रदर्शनी की संगठन समिति की देख-रेख में उपर्युक्त प्रदर्शनी का आयोजन किया है ।

बोनस विधेयक

759. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित बोनस विधेयक के बारे में श्रमिकों और कर्मचारियों के विचार प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जो टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उन पर विचार किया जा रहा है ।

मछेरों के शवों को निकालने के लिये श्री लंका सरकार की प्रार्थना

760. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका सरकार ने भारत सरकार से अपनी नौ-सेना की गश्ती किश्तियों को श्री लंका के उन मछेरों के शवों को निकालने के लिए सुविधा देने की प्रार्थना की थी जो कहा जाता है, कि दिसम्बर, 1964 के चक्रवात के बाद बहकर धनुषकोटि और पंवन के तटों पर आ गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां । श्रीलंका की सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि उनके नौ सेना जहाज़ों को भारतीय प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए जिससे कि वह श्रीलंका के उन मछेरों के शवों को उठा ले जा सकें जो दिसम्बर 1964 के समुद्री तूफान के बाद दक्षिण तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ बहकर चले आये थे । इसके लिए तत्काल अनुमति दे दी गई ।

Sittings of Lok Sabha

761. Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision to reduce the number of sittings of Lok Sabha to be held during a year ;

(b) if so, the basis for this decision and whether some other decisions of a similar nature have also been taken ; and

(c) whether it is a fact that the number of sittings of the current Budget Session is less as compared to all the previous Budget Sessions ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha):

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) The tentative number of sittings of the Lok Sabha during the current session is expected to be 54 as compared to 61 and 66 in the years 1963 and 1964 respectively. The sittings in the previous years included Saturday sittings. Sittings on Saturdays have now been dispensed with in deference to the wishes of the Speaker.

प्रारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा का विलय

762. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेम बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विदेश सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के विलय के प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है जिससे भारतीय विदेश सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी समुचित स्वतंत्रता से अपनी नियुक्तियों को परस्पर बदल सकेंगे ; और

(ग) क्या सरकार ने कदम उठाये हैं कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विदेशों में कूटनीतिक पदों पर जाने से पहले देश में प्रशासन से पूर्ण परिचित हों ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त किये गये अधिकारियों को भर्ती के तुरंत बाद नेशनल अकादमी आफ़ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी के साथ 6 महीने के लिए संबद्ध कर दिया जाता है ताकि वे भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के साथ ही प्रशासन सम्बन्धी बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर लें । इस अवधि के अन्त में उन्हें जिला प्रशासन और विकास कार्य में प्रशिक्षण देने के निमित तीन महीने की अवधि के लिए नियत ज़िलों में भेज दिया जाता है ।

गश्त लगाने वाली अमरीकी परमाणु पनडुब्बियां

763. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० सा० तिवारी :
श्री नरेन्द सिंह महीडा :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री चुनी लाल :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "जेकमसेह" नामक अमरीकी परमाणु पनडुब्बी ने, जो पोलरिस मिसाइलों से लैस है सुदूर-पूर्व समुद्र में गश्त कर रहे अपने साथी "जहाज डैनियल बून" के पास पहुंचने के लिए अपनी समुद्री यात्रा आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या दोनों पनडुब्बियां 28,00 मील तक मार करने वाले आधुनिक ए–3 पोलरिस मिसाइलों से लैस हैं ;

(ग) क्या "डैनियल बून" में लगे ए–3 मिसाइलों को शीघ्र ही अधिक दूर तक मार करने वाले अधिक शक्तिशाली बी-3 मिसाइलों से बदला जायेगा; और

(घ) क्या भारत सरकार ने अमरीका को इन साहसिक कार्यों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बता दी है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). सरकार ने दूर-पूर्व समुद्र में संयुक्त राज्य अमरीका की परमाणु पनडुब्बियां होने की खबरें समाचार-पत्रों में देखी हैं, परन्तु उनकी वास्तविक गतिविधियां अथवा उपकरणों के बारे में उसे कोई सूचना नहीं है और इस समय यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि ये पनडुब्बियां भारत के पास ही ठहराई जा रही हैं। इन परिस्थितियों में इस विषय में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को कोई पत्र भेजने का सवाल ही नहीं उठता।

परमाणु हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी शिखर सम्मेलन

764. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने 28 दिसम्बर, 1964 को चीन को सूचित कर दिया है कि वह परमाणु हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक शिखर सम्मेलन बुलाने के प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई के सुझाव का समर्थन करता है ;

(ख) क्या रूस काहिरा में अफ्रीकी एशियाई तटस्थ राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किये गये संकल्प का समर्थन करता है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि विश्व शांति के हित में एक विश्व-निःशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाया जाये ;

(ग) क्या इस बारे में भारत सरकार ने रूस को अपनी पसन्द की सूचना दे दी है; और

(घ) चीनी प्रस्ताव के रूस द्वारा समर्थन किये जाने के बारे में भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मुख अपने भाषण में सोवियत विदेश मंत्री ने हथियार-परिहार पर बातचीत करने के लिए एक विश्व सम्मेलन आयोजित करने के विचार का समर्थन किया; इसका प्रस्ताव गुटों से अलग राष्ट्रों के सम्मेलन की घोषणा में किया गया था ।

(ग) और (घ). आणविक हथियारों पर रोक लगाने और उन्हें समाप्त करने के विषय पर बातचीत करने के लिए प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई ने 17 अक्तूबर, 1964 के अपने पत्र में विश्व का शिखर सम्मेलन बुलाने का जो प्रस्ताव किया था उसके उत्तर में हमारे प्रधान मंत्री ने लिखा कि जब तक सामान्य और संपूर्ण हथियार–परिहार के विषय पर संधि का मसौदा तैयार करने में काफी प्रगति नहीं हो जाती तब तक इस प्रकार के किसी सम्मेलन का कोई लाभ नहीं हो सकता । यह स्थिति सब को मालूम है, इसलिये यह आवश्यक नहीं समझा गया कि इसे सोवियत संघ (यू. एस. एस. आर.) अथवा किसी अन्य देश की सरकार के ध्यान में लाया जाय ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मसला

765. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत में मानव अधिकारों की पुरःस्थापना का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में उठाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार का क्या रवैया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) फिलीपीन, निकारागुआ और अल-सल्वाडोर की सरकारों ने मिल कर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19 वें सत्र की कार्य सूची में "तिब्बत का प्रश्न" नामक मद शामिल करने का प्रस्ताव किया था । कार्यसूची के कई अन्य मदों की तरह इस मद पर भी महासभा में विचार नहीं किया गया क्योंकि वहां असाधारण स्थिति के कारण उसका सामान्य कार्य रुक गया था । इस बीच महासभा ने 1 सितम्बर, 1965 तक अपना सत्र स्थगित कर दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में चलते-फिरते टेलीविजन एकक

766. श्री हेडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली नगर के लिए चलते-फिरते टैलीविज़न एककों के बारे में कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बात क्या हैं; और

(ग) क्या टेलीविज़न सैटों को खरीदने के लिए स्वयंसेवक संस्थाओं या सामुदायिक केन्द्रों को राज सहायता देने के बारे में कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). दिल्ली के टेली-विज़न केन्द्र के लिए कमरों तथा अन्य यंत्रों से संयुक्त एक टेलीविज़न गाड़ी हासिल करने का विचार है जो स्टूडियो से दूर की जगहों से कार्यक्रम रिले करने के लिए काम आएगी ।

(ग) जी, नहीं । अभी नहीं । समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

विचारधारा डिवीज़न

767. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के मनोवैज्ञानिक गवेषणा निदेशालय के अधीन विचारधारा डिवीजन को किस प्रकार का काम सौंपा गया है; और

(ख) सशस्त्र बल के मनोबल को परखने के लिए कोई कसौटी तैयार करने की दिशा में उपर्युक्त डिवीजन ने क्या प्रगति की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) यह दल सशस्त्र सेनाओं के मनोबल और दूसरे सम्बद्ध मामलों पर अनुसंधान प्रयोजनाओं से संबंधित है ।

(ख) अध्ययन अभी भी जारी है ।

सभा-पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद

768. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभा-पटल पर रखे जाने वाले सभी दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद भी साथ-साथ रखने के लिए आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन दोनों की प्रामाणिकता एक जैसी होगी ?

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) संसद्-कार्य विभाग ने ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

National Defence Fund

769. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri P. H. Bheel :
Shri Bade :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Solanki :
Shri Narasimha Reddy :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Mina :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 337 on the 23rd November, 1964 and state :

(a) the total cash contribution received in the Central Account of the National Defence Fund from the Ist November, 1964 to the 28th February, 1965 ;

(b) the quantum of contribution received in the form of gold and gold ornaments and other precious metals during the above period; and

(c) the fund so far utilised ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) The total cash contribution received in the Central Account of the National Defence Fund during the period Ist November, 1964 to the 28th February, 1965 was Rs. 20,64,329·74.

(b) The quantum of contributions received in the form of gold and gold ornaments and other precious metals during the above period was :—

	Gms.
Gold and gold ornaments	11,929·630
Silver and silver articles	30,933·260

(c) A total expenditure of about Rs. 33·35 crores has so far been authorised but the actual expenditure has been about Rs. 24 crores.

Military Training Centre, Kotah

770. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Stores worth several lakhs of rupees which were ordered in connection with the expansion of the Military Training Centre at Kotah are lying at site unutilized ;

(b) if so, the reasons threfore ; and

(c) whether the Training Centre is being shifted from Kotah to Jaipur ; if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) and (b) : Stores worth Rs. 13·29 lakhs comprising principally A.C. sheets and water supply pipes are lying at the site in question. These stores were ordered for two projects sanctioned for the expansion of the Military Training Centre, Kotah as a result of the Emergency. The work on the two projects has been suspended after part completion pending review of the ultimate strength of the training centre and the location thereof.

(c) The question is under Government consideration.

Radio-Photo Service

771. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that an agreement has been signed by the Governments of Netherland and India in regard to Radio-photo service; and

(b) if so, the broad outline thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

U. S. Military Aid Mission

772. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some officers of the United States Military aid Mission are staying in Delhi since the Chinese attack in October, 1962 ;

(b) if so, the period for which they are likely to stay in India ; and

(c) the manner in which the expenditure involved on their stay is being met ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). A United States Military Supplies Mission has been located in India as part of the U. S. Embassy. This Mission helps in processing our requirements of military supplies which are obtained from the Government of the United States under their Military Assistance programme on a continuing basis. The Mission is also assisting us in the procurement of equipment and stores under the U. S. Military Credit Sales Programme.

Equipment and stores are being received under U. S. Aid and Credit Programmes. In accordance with the Agreement between the two countries, the Government of India is to pay sums of money mutually agreed upon by the two governments to meet the expenditure on the U. S. Military Supplies Mission. The amounts of such payment forms a small percentage of the Aid to be received. As on account payment, a sum of Rs. 50 lakhs was made by the Government of India early, in the 1963 and an additional sum of about Rs. 1 crore has been paid recently to cover expenditure upto the 30th June, 1965.

No period has been fixed for the continuance of the U.S. Military Supply Mission. But as long as India receives material supplies under U. S. Military Aid and Military Credit under Organisation of this nature may be necessary.

परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये शिखर सम्मेलन

773. **श्री स० ब० पाटिल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री के परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक शिखर सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार इस विचार से सहमत है कि व्योरेवार बातचीत करने के लिए शिखर सम्मेलन बुलाना उचित नहीं होगा और आम तथा पूरे निश्स्त्रीकरण करने के सवाल पर समझौता करने के लिए व्योरेवार बातचीत करना आवश्यक है ।

मद्रास में अबाड़ी स्थित कपड़ा बनाने का कारखाना

774. **श्री मनोहरन :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री नरेन्द्र सिंह महोडा :
श्री सोलंकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबाड़ी स्थित कपड़ा बनाने के कारखाने से मशीनों और उत्पादन क्षमता को उत्तरी भारत के कारखानों में स्थानान्तरित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मज़गांव डाक

775. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मज़गांव डाक लिमिटेड बम्बई ने अन्दमान प्रशासन के लिये एक यात्री तथा माल जहाज का निर्माण किया है ;

(ख) क्या इसको औपचारिक रूप से गृह-कार्य मंत्रालय को सौंप दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख को ; और

(घ) इस जहाज़ के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय हुई और विदेशों में इसी प्रकार के जहाज़ के निर्माण पर आने वाली लागत की तुलना में यह कैसी है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). जलयान 12-1-1965 को औपचारिक तौर पर गृह-मंत्रालय को सौंप दिया गया था ।

(घ) इस जलयान के निर्माण पर कुल 67.50 लाख रूपये की लागत उठी है । ऐसे ही जलयान के, विदेशों में निर्माण की लागत मालूम नहीं है, क्योंकि इस जलयान या इस से मिलते-जुलते जलयान के निर्माण के लिए विदेश से कोई टेण्डर नहीं मांगे गए थे ।

पंजाब में रोजगार की स्थिति

776. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलैंडर वर्ष 1964 के दौरान पंजाब में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों द्वारा कुल कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये ;

(ख) इन संस्थानों में इस अवधि के दौरान कितने रिक्त स्थान विभिन्न रोजगार दफ्तरों के माध्यम से भरे गये ; और

(ग) अनुसूचित जाति के कितने आवेदकों को काम पर लगाया गया ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख)

क्षेत्र	रोजगार कार्यालयों को सूचित रिक्त स्थानों की संख्या	भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या
सरकारी	82,008	56,879
निजी	16,754	3,773

(ग) सन् 1964 के दौरान 8,757 उम्मीदवारों को काम दिलाया गया ।

जवानों तथा अधिकारियों के यात्रा भत्ते

777. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवानों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के यात्रा भत्ते की दरों में क्या अनुपात है ;

(ख) यह अनपात उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विदेशों में विद्यमान अनुपात से कम है या अधिक ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस अनुपात को कम करने का है ?

प्रतिरक्ष मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जवानों तथा कमीशन प्राप्त अफसरों के यात्रा भत्ते की दरों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उन की सेवाओं की स्थितियां और शर्तें, तथा यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं, सर्वथा, विभिन्न हैं, । तदपि, होने वाली यात्रा के स्वरूप पर आधारित, अनुपात लगभग 1:4 तथा 1:6 के दर्मियान है ।

(ख) विदेशों में यात्रा भत्ते की देयताएं क्या हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्य नहीं है ।

(ग) इस समय कोई विशेष सुझाव सामने नहीं है । परन्तु परिस्थियोंवश यदि सुधार वांछित होता है, तो जवानों की यात्रा सुविधाओं पर वाजिबी विचार किया जाता है ।

विश्व परमाणु निशस्त्रीकरण सम्मेलन

778. **श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा :**
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाना के राष्ट्रपति एंक्रुमा ने हाल में सुझाव दिया है कि परमाणु निशस्त्रीकरण पर विचार करने के लिए एक विश्व सम्मेलन बुलाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि घाना के राष्ट्रपति ने परमाण निरस्त्रीकरण के सवाल पर विचार करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया है ।

(ख) सरकार सब से अधिक महत्व इस बात को देती है कि आम और पूरे निरस्त्रीकरण के सवाल पर शीघ्र ही समझौता हो जाना चाहिए । सरकार का यह विचार है कि इस बारे में जो भी समझौता होगा वह सिर्फ़ परमाणु निरस्त्रीकरण तक ही सीमित नहीं रह सकता बल्कि परंपरागत हथियारों के निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर भी साथ ही समझौता करना होगा । इस तरह का कोई समझौता तभी हो सकता है जब कि इस विषय पर विस्तार के साथ बातचीत और विचार-विमर्श किया जाए, और, इसलिए, सरकार यह समझती है कि जब तक आम और पूरे निरस्त्रीकरण से संबंद्ध एक सन्धि का मसौदा तैयार न कर लिया जाये तब तक इस सवाल पर विचार करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

टेलीफोन के बिल

779. **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 2–3 वर्षों से दिल्ली में टेलीफोन के बिलों के लगभग तीन करोड़ रुपये बकाया पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) 1 सितम्बर, 1964 को 173.37 लाख रुपये की रकम 29 फरवरी, 1964 तक जारी किये गये बिलों के भुगतान के सिलसिले म बक़ाया थी ।

(ख) निर्धारित नियमों के अन्तर्गत जो क़दम उठाये जाने चाहियें, ख़ास तौर से रक़म जमा न करने वाले व्यक्तियों के टेलीफोन कनेक्शन काट देने के लिए उचित क़दम उठाये जा रहे हैं ।

Rana Pratap Sagar Atomic Plant

780. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. L. M. Singhvi :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Rajasthan Government have submitted a proposal for doubling the capacity of the Rana Pratap Sagar Atomic Power Station for increasing electric power potential ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shashtri) :

(a) Yes.

(b) The proposal is now under the consideration of Government.

"स्टेट्समैन" की सम्पादकीय टिप्पणियां

781. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 जनवरी, 1965 के "स्टेट्समैन" (कलकत्ता) के 3 जनवरी के अंक के सम्पादकीय स्तम्भ में व्यक्त इन विचारों की ओर आकर्षित किया गया है, कि :

"पाकिस्तान में चाहे कोई भी सरकार ही हो, परन्तु वह काश्मीर पर देश का अपना दावा नहीं छोड़ सकती" ; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार से यह प्रत्याशा नहीं की जानी चाहिए कि वह अखबार में छपी हरेक बात पर अपनी प्रतिक्रिया बताए । बहरहाल, कश्मीर के विषय पर सरकार की नीति सदन में और भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा परिषद् में कई बार बताई जा चुकी है ।

अमरीका में प्रचार

783. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के महाराजा ने हाल की अपनी भाषण यात्रा के दौरान यह बताया था कि अमरीका की जनता में यह गलत धारणा फैली हुई है कि भाषा एवं जाति संबंधी मत-भेदों और नेताओं की कमजोरी के कारण बहुत जल्दी भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे, क्या इस धारणा को दूर करने के लिए अमरीका में समुचित प्रचार किया जा रहा है ;

(ख) अब तक क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). वाशिंगटन डी० सी० में हमारा राजदूतावास और न्यूयार्क तथा सानफ्रान्सिसको-स्थित हमारे दो प्रधान कोंसलावास भारत को चित्रित करते समय बराबर इस बात पर जोर देते रहते हैं

कि भारत में जातिभेद धीरे-धीरे मिटता जा रहा है । वे सरकार की नीतियों को भी सही रूप में पेश करते हैं, जो कि भारत में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण कभी-कभी विकृत रूप ग्रहण कर लेती है ।

सभी मिशनों से, जिन में संयुक्त राज्य अमरीका के मिशन भी शामिल हैं, कह दिया गया है कि भाषा के प्रश्न को वे हमारे प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री के वक्तव्यों का हवाला दे-कर - सही रूप में प्रस्तुत करें।

भारत की सही तस्वीर को प्रस्तुत करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदा चलती रहती है और हम समझते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका में भारत को एक संयुक्त राष्ट्र ही समझा जाता है ।

लेखा प्रक्रिया

784. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग की लेखा प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देशपद तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) समिति ने कौन सी मुख्य सिफारिशें कीं तथा उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है । फिर भी डाक-तार विभाग के दूर संचार प्रशासन की लेखा-विधियों पर पुनर्विचार करने के लिए जुलाई, 1964 में ब्रिटिश डाकघर और मैसर्स पीट, मारविक मिट्चेल एण्ड कम्पनी, लंडन को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ख) परामर्शदाताओं के लिए विचारार्थ विषयों की सूची संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी--3940/65]** चूंकि केवल परामर्शदाता ही नियुक्त किए गए थे, अतः सदस्यों के नामों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) परामर्शदाताओं की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं और उन के शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है।

राजस्थान में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था

785. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष राजस्थान में स्वचालित टेलीफोन की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन नगरों में यह सुविधा उपलब्ध करने का विचार है ; और

(ग) किन-किन नगरों में सीधी सम्पर्क सेवा की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) (i) अगले वर्ष जयपुर टेलीफोन केन्द्र का 5000 लाइनों से 6500 लाइनों में विस्तार किया जाएगा ।

(ii) इसके अतिरिक्त अलवर, व्यावर, भीलवाड़ा, पिल्लहगा, कुचामन सिटी, गजसिंह पुर, श्रीविजय नगर, कुम्बेर, ईसपुरा सिटी, पदमपुर, करोली, फतेहपुर, फालना, श्री महावीरजी, खनेला और जैसलमेर में छोटे स्वचल केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव ।

(iii) हनुमानगढ़, नीम का थाना, सवाई माधोपुर और फुलेरा के मौजूदा छोटे स्वचल केन्द्रों का इस प्रकार विस्तार किया जाएगा —

हनुमानगढ़	. 25 से 100 लाइनों में
नीम का थाना .	. 50 से 100 लाइनों में
सवाई माधोपुर . .	. 25 से 50 लाइनों में
फुलेरा .	. 10 से 25 लाइनों में

(ग) जयपुर दिल्ली से सीधे डायल करने की सुविधा द्वारा पहले से ही जुड़ा है । अगले वर्ष राजस्थान के दूसरे नगरों में इस सुविधा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आयुध कारखाने

786. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आयुध कारखानों ने $2\frac{3}{4}$ इंच के क्ले पिजन कारतूस बनाने की दिशा में कुछ प्रगति की है ;

(ख) आयुध कारखानों द्वारा जांच के लिए भेजे गये कुछ कारतूसों के बारे में राष्ट्रीय राइफल संस्था की ओर से श्री कर्णी सिंहजी, संसद सदस्य द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या आयुध कारखानों के लिये भारत में क्ले पिजन ट्रैप और स्कीट मशीनें बनाना संभव है क्योंकि विदेशी मुद्रा प्रतिबन्धों के कारण इनका आयात करना संभव नहीं है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां । $2\frac{3}{4}$ इंच कारतूसों के उत्पादन के लिए, एक प्रायोजना आयुध कारखानों में कार्यान्वित की जा रही है । इस संबंध में कुछ मशीनें आ चुकी हैं, और शेष के शीघ्र आने की आशा है ।

(ख) माननीय सदस्य के सुझाव/कमेण्ट्स नोट कर लिए गए हैं ।

(ग) जब इसके लिए आयुध कारखानों में क्षमता प्राप्य होगी, इन मशीनों के निर्माण के लिए, संभावनाओं की जांच पड़ताल की जाएगी ।

फ़िल्म समारोह से जर्मनी की फिल्म को वापिस लेना

787. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की आपत्ति पर जर्मनी की "वरस्पाटुंग इन मरीन बोर्न" (मरीन बोर्न में विलम्ब) को अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह से हटा लिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में आपत्ति क्या थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली स्थित सोवियत संघ के दूतावास के विचार में उक्त फ़िल्म में सोवियत विरोधी सामग्री थी ।

चिकित्सकों के लिये पारपत्र

788. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री चाण्डक :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने और आगे अध्ययन तथा नौकरी के लिये विदेशों में जाने वाले डाक्टरों को पारपत्र देने के लिये और अधिक प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नए प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सदन की मेज़ पर एक वक्तव्य रख दिया गया है जिसमें इस बारे में सूचना दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी--3941/65]**

Telegraph Office, Panjim

789. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattanayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officer-in-charge of the Telegraph Office, Panjim refused to forward a telegram of Shri Diwekar Kakedkoar addressed to Dr. Ram Manohar Lohia on the 17th September, 1964 on the plea of its being objectionable ;

(b) whether any list of objectionable material has been supplied to the Telegraph Offices and, if so, whether a copy thereof will be laid on the Table; and

(c) whether the contents of the above telegram are considered objectionable according to this list ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) (a) The transmission of the telegram was refused under the provisions of the Indian Telegraph Act, 1885.

(b) The Act and the rules governing the general principles in regard to refusal to transmit telegrams are emboided in the P &T Manuals which are supplied to all telegraph offices. Relevant extracts of the Indian Telegrph Act and the Indian Telegraph Rules and Explanatory paragraph of the Manuals thereto are laid on the Table of the Sabha [Placed in the Library. *See* No. LT 3942/65]

(c) The contens were considered objectionable by the concerned authorities in the local context.

Prime Minister's Constitutional Right

790. **Shri Madhu Limaye :** Will the **Prime Minister** be pleased to state whether it is a fact that he had stated in his Press Conference at Delhi on the 20th January, 1965 that he had the constitutional right to advise a Chief Minister, whichever party he may belong to, to resign, if his conduct is found to suffer from impropriety ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : No. Sir.

Visit of U. S. Industrialists

791. **Shri D. N. Tiwari** : Will the Minister of **External Affairs b** : pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a group of twenty-six industrialists of United States of America visited India for a journalistic enquiry under the aegis of " Time " News Magazine:

(b) if so, the subjects which they enquired into ;

(c) the number of places visited by them ; and

(d) whether a copy of its report would be submitted to Government ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) and **(b)** Twenty-six leading Corporation Presidents from the United States of America and 22 others, whose work is connected with the publication of 'LIFE' and 'FORTUNE' magazines, visited India under the aegis of " Time " Inc. their visit to India was part of their Asian tour to acquaint themselves, at first-hand, with this area. As such, they did not come to look into any specific subjects.

(c) New Delhi and a village near Delhi.

(d) Does not arise.

हावड़ा स्टेशन पर मारपीट

792. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 8 जनवरी, 1965 को हावड़ा स्टेशन पर हुई मारपीट के बारे में, जिसमें छुट्टी पर अपने घरों को जा रहे 200 जवान शामिल थे, जिनमें से कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों से आ रहे थे, कोई जांच करने का आदेश दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि घर को छुट्टी पर जाने वाले जवानों को स्थान दिये जाने के मामले में लगातार कुप्रबन्ध के कारण इस प्रकार की घटनायें होती हैं और इस प्रकार जवानों को बड़ी असुविधा होती है और उनकी छुट्टियां बेकार हो जाती हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) घटना की जांच के लिए सैनिक अधिकरणों ने एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी को आदेश दे दिया है ।

(ख) तथा (ग) : जैसे कि यशपाल सिंह तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या 605 दिनांक 16-3-64 के उत्तर में मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसी हिदायतें हैं कि जिनके अन्तर्गत संचलन नियंत्रण अधिकरणों द्वारा पहले ही व्यवस्था किए जाने के बगैर, सेवाओं के 10 से अधिक सैविवर्ग के दल भेजना, मना है और भेजने वाली यूनिटों को ऐसा निश्चित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है कि उनके सैविवर्ग उन अधिकरणों द्वारा किए प्रबन्धों का सख्ती से पालन करें, और वह केवल उन्हीं गाड़ियों द्वारा यात्रा करें, जो उनके लिए उन द्वारा निर्धारित की जाएं । सभी गाड़ियों में जनता के लिए प्राप्य स्थानों के अनुरूप सेवाओं के सैविवर्ग बाकोटा नियत होता है । इसके अतिरिक्त तदर्थ आधार पर रेल अधिकारियों से, जभी आवश्यक हो अतिरिक्त स्थान प्राप्त कर लिए जाते हैं । ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये, यह सुनिश्चित करने के लिए, कि वर्तमान हिदायतों पर सख्ती से पालन हो, कार्यवाही की जा रही है ।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में प्रचार

793. **श्री उ० म० त्रिवेदी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तटस्थता तथा शांति पूर्वक सह-अस्तित्व के बारे में भारत के दृष्टिकोण के उद्देश्यों का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : हमारी सूचना सेवाओं द्वारा रोज़मर्रा की बुलेटिनें मासिक पत्रिकाएं जारी करने, श्रव्य-दृश्य साधनों द्वारा प्रचार, अनौपचारिक वार्ता और व्याख्यान जैसे प्रचार के सामान्य तरीके अपनाने के अलावा, गुट सहित देशों के हाल के सम्मेलन और उसमें भारत द्वारा किए गए कार्य का प्रचार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए । गुटों से अलगाव और शांतिपूर्ण सहजीवन में भारत की निष्ठा को बराबर प्रस्तुत किया जाता है ।

ईसाई और हिन्दू नागा

794. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) ईसाई नागाओं तथा (दो) हिन्दू नागाओं की संख्या कितनी है ; और

(ख) नागालैंड के प्रशासन के बारे में हिन्दू नागाओं की इच्छा जानने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नागाओं की लगभग 3·5 लाख की कुल जन संख्या में से 60 प्रतिशत से ऊपर ईसाई हैं जबकि शेष नागा लोग अपने पुराने विश्वासों का अनुसरण करते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीन जाने की अनुमति

795. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अधिकारियों को छोड़कर उन लोगों का विवरण क्या है जिन्हें 1 जनवरी, 1964 से 1 जनवरी, 1965 तक की अवधि में चीन जाने की अनुमति दी गई थी ; और

(ख) इन में से प्रत्येक व्यक्ति का वहां जाने का उद्देश्य क्या था ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1964 से 1 जनवरी 1965 तक सरकारी अधिकारियों को छोड़कर भारत से कोई व्यक्ति चीन नहीं गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण

796. **श्री अब्दुल गनी गोनी** :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री वारियर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1964 से 1 जनवरी, 1965 तक की अवधि के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से कितने शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान वापस चले गये हैं ; और

(ख) 1 जनवरी, 1964 से 1 जनवरी, 1965 तक की अवधि के दौरान भारत से पूर्वी पाकिस्तान को जाने वाले प्रव्रजकों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से कितने व्यक्ति भारत वापस आ गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) 1 जनवरी 1964 से 1 जनवरी 1965 तक की अवधि में पूर्व पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों की कुल संख्या 8,55,996 थी । इनमें से 9176 पूर्व पाकिस्तान लौट गए ।

(ख) प्रवासियों की, अर्थात् उन लोगों की कुल संख्या 2,683 थी जिन्होंने 1 जनवरी 1964 से 1 जनवरी 1965 तक पाकिस्तानी प्रवास प्रलेखों अथवा प्रमाण-पत्रों के आधार पर भारत से पूर्व

पाकिस्तान की यात्रा की ; यह संख्या जांच चौकियों द्वारा भेजे गए विवरण से संकलित की गई है। इनमें से 797 भारत वासप आ गए ।

सर्वे आफ इण्डिया

797. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों और भूगोल, भूतत्व शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने वाले लोगों को सर्वे आफ इंडिया के एक इंच तथा चौथाई इंच की स्थलाकृतिक (टोपोग्रेफिक) शीटें नहीं मिलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : (क) स्थल–रूपरेखीय यह पत्र प्रतिबंधित है, और विश्वविद्यालयों के छात्रों और अनसंधान कार्य करने वालों द्वारा, उन के प्रयोग के लिए, रक्षा मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है । शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं को, इन नक्शों का वितरण सुलभ्य बनाने की प्रक्रिया के, सरलीकरण का, सरकार विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला खान प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें

798. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962, 1963 और 1964 में ए० आई० टी० यू० सी०, आई० एन० टी० यू० सी०, एच० एम० एस० तथा यू० टी० यू० सी० ने अनुशासन संहिता के अन्तर्गत विभिन्न कोयला खानों के प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार को कितनी शिकायतें भेजीं और वे शिकायतें किस प्रकार की थीं ; और

(ख) ऐसी कोयला खानों तथा समवायों के नाम क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है । इसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

खानों के मजदूर संघ के अधिकार

799. **श्री प्रभातकार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० उ० मिश्र :
डाक्ट रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को भारतीय खानों में मजदूरों संघ अधिकारों पर आघात के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय खनिक कार्मिक संघ, (डेब्लू० एफ० टी० यू०), प्रेस से दिनांक 1 सितम्बर, 1964 का कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संस्था को कोई उत्तर भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) संक्षेप में ये इस प्रकार हैं :—

ये आरोप कि अनुशासन संहिता और शांति संकल्प के उल्लंघनों के लिए केवल यूनियनों के ही विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और औद्योगिक मामलों के संबंध में भारत रक्षा नियम मज़दूर संघ कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, सही नहीं है । अदजय 2 कालियरी में 6 कामगरों , जिन्हें राष्ट्र विरोधी कार्यवाइयों के लिए भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत पकड़ा गया था, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर हुए और उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने दोष सिद्धियों की पुष्टि की ।

जब मैनेजमेंट ने संबंधित 28 कामगरों में से 22 को बकाया राशि की अदायगी करदी और संबंधित पक्षों में समझौत हो गया कि शेष कामगरों को उनकी बाकाया राशि मैनेजमेंट से मांगने पर मिल जायगी, खास बल्लभपुर कालियरी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी गयी ।

सेलेक्टेड सामना एन्ड न्यू ड्रामागोरिया कालियरीज़ में हमले की तथाकथित घटनाएं आदि न्यायाधीन हैं ।

Television Sets from Yugoslavia

800. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Surya Prasad :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government of Yugoslavia have offered to supply television sets to the Government of India ;

(b) if so, whether Government have accepted the offer ;

(c) whether it is a fact that a commercial firm in Belgrade has informed the Government of India that it is ready to supply television sets at Rs. 1,000 per set; and

(d) if so, the reply given by Government in this behalf ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) and (c) No. Sir.

(b) and (d). Do not arise.

श्रम डिपो गोरखपुर

801. **डा० उ० मिश्र :**
डा० रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी कोयला खानों में श्रम डिपो, गोरखदुर द्वारा दिये गये मजदूर काम करते हैं ;

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं और वर्ष 1964 में प्रत्येक खान में कितने मजदूर काम करते थे ; और

(ग) उन में से कितने मजदूर स्थायी किये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख): साथ नत्थी विवरण में जानकारी दी गई है । **[[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी--3943/65]**।

(ग) जानकारी प्राप्त की है ।

संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के विश्व संघ का सम्मेलन

802. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में जनवरी, 1965 में संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के विश्व संघ का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है, कि भारत ने सुझाव दिया था कि इन्डोनेशिया से संयुक्त राष्ट्र संघ छोड़ने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो कितने देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और कितने देशों ने इसका विरोध किया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र एसोसियेशन भारत संघ की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने एक प्रस्ताव रखा है जिस में "इन्डोनेशिया सरकार के संयुक्त

संयुक्त राष्ट्र से हट जाने के निर्णय पर चिंता व्यक्त की गई है, और इन्डोनेशिया सरकार से अपील की गई है कि वह अपने निर्णय पर फिर से विचार करे और संयुक्त राष्ट्र में पूरी तरह से फिर से भाग लेने लगे ।"

(ग) बताया जाता है कि 22 प्रतिनिधि मंडलों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और विपक्ष में किसी ने नहीं ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के संबन्ध में उच्च न्यायालयों के निर्णय

803. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्य श्रमिक कानूनों के लागू होने के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने परस्पर विरोधी निर्णय दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सभी राज्यों में सहकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में श्रमिक कानूनों के लागू करने में एकरूपता लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). कलकत्ता और केरल के उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सहकारी समितियों के कामगरों पर लागू होता है । मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सहकारी समिति के कर्मचारी, जो समिति के हिस्सेदार भी हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के लिये कामगर नहीं हैं। समिति के हिस्सेदार होने के नाते उन्हें अपने दावों में केवल मद्रास सहकारी समिति अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत न्यायनिर्णय कराना पड़ता है । ये निर्णय परस्पर विरोधी नहीं समझे जाते, क्योंकि इन मामलों के तथ्य समान नहीं हैं ।

जहां तक अन्य श्रमिक कानूनों का संबंध है, सरकार के ध्यान में कोई परस्पर विरोधी निर्णय नहीं आए हैं।

(ग) सरकार के ध्यान में कोई कठिनाई नहीं आई है । अतः इस संबंध में कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी उद्योग में लाभांश

804. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रत्येक राज्य में चीनी उद्योग में लाभांश का भुगतान कर दिया है ;

(ख) किन किन राज्यों में चीनी उद्योग में 1962-63 और 1963-64 का लाभांश दे दिया गया है ;

(ग) क्या किसी राज्य में चीनी उद्योग में लाभांश आयोग की सिफारिशों के आधार पर लाभांश दिया गया है ; और

(घ) क्या नियोजकों और कर्मचारियों ने सरकार द्वारा परिवर्तित रूप में लाभांश आयोग की सिफारिशों को मान लिया है ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सरकार द्वारा यथा संशोधित बोनस आयोग की सिफारिशों के बारे में नियोजकों और कामगरों से प्राप्त हुई टिप्पणियों पर विचार किया जा रहा है । इन टिप्पणियों के प्रकाश में सरकार द्वारा स्वीकार की गई आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक बिल का मसौदा तैयार किया जा रहा है ।

क्योंझर में लौह अयस्क की खानें

805. **डा० उ० मिश्र :**
डा० रानेन सेन :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्योन्झर जिले में लौह अयस्क की खानों में नियोजकों के लोह अयस्क खनन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की अंतरिम सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) क्योन्झर ज़िले की कच्चे लोहे की खानों में कुछ नियोजकों ने अभी तक इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है ।

(ख) इन्हें क्रियान्वित न करने के बारे में जो कारण पेश किए गए हैं उन पर विचार किया जा रहा है ।

चीनी उद्योग के लिए दूसरा मजूरी बोर्ड

806. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के लिए दूसरा मजूरी बोर्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में मजदूर संघों से सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

कागज उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

807. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग के लिए एक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आवश्यकताओं के आधार पर मजूरी

808. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के निदेश के अनुसार क्या सरकार ने आवश्यकता के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कैलोरी की आवश्यकता के मानकों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यकताओं के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियत मानकों को ध्यान में रख कर मजदूरी निर्धारित करने वाले प्राधिकारियों को क्या निदेश देने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई सिफारिशों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति से प्रार्थना की गई थी कि वह आवश्यकता के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने के लिए श्रमिक वर्गों के परिवारों के लिए पर्याप्त पोषणिक आहार की सिफारिश करे । राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति ने इस प्रयोजन के लिए एक उप-समिति नियुक्त की थी । इस उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और उस पर राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की पोषण सलाहकार समिति का परामर्श लेकर विचार किया जा रहा है । समिति की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा है ।

गुजरात में अणु शक्ति केन्द्र

809. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में सौराष्ट्र में एक अणु शक्ति केन्द्र स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या किसी स्थान का चुनाव कर लिया गया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सौराष्ट्र में अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रायगड़ा और जयोर के बीच सीधा टेलीफोन सम्बन्ध

810. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरापुट जिले (उड़ीसा) में रायगड़ और जयोर के बीच सीधा टेलीफोन सर्कट स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : रायगड़ा और जयोर के बीच एक सीधे टेलीफोन परिपथ की व्यवस्था 23 नवम्बर, 1964 को कर दी गई है ।

भुवनेश्वर में डाक और तार विभाग के क्वार्टर

811. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में डाक और तार विभाग के क्वार्टरों के निर्माण करने में अब तक क्या नवीनतम प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय किया गया है ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) 63 क्वार्टर बनाने का काम अभी शुरू हुआ है ।

(ख) कुछ नहीं ।

उड़ीसा के ग्राम क्षेत्रों में रेडियो सेट

812. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ग्राम क्षेत्रों को भेजने के लिए 1964-65 में कितने रेडियो सेटों का आवंटन किया गया है ; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1964 तक इस राज्य को कितने रेडियो सेट दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 1,100.

(ख) 9,120.

आकाशवाणी के सम्बलपुर केन्द्र के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी

813. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1964 को आकाशवाणी के सम्बलपुर केन्द्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी, कलाकारों और अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

	आकाशवाणी सम्बलपुर में स्टाफ आर्टिस्टों/ कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या
स्टाफ आर्टिस्ट .	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य कर्मचारी .	39	12	1

उड़ीसा में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

814. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1964-65 में राष्ट्रीय नमूना सवक्षण द्वारा कुल कितने सर्वेक्षण किये गये ; और

(ख) उन पर क्या व्यय हुआ है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :

(क) उड़ीसा में अप्रैल, 1964 से अब तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा किये

गये सर्वेक्षण

एक . सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण :

(क) अप्रैल—जून 1964 में किए गए सर्वेक्षणों के विषय

1. उपभोगता व्यय

2. घर की वस्तुओं की एकीकृत सूची जिसमें अन्य बातों के साथ साथ घर की आय तथा व्यय पर जानकारी, टिकाऊ तथा अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की तालिका [illegible] किया गया है।
आदि को [illegible]

(परीक्षण के लिये अध्ययन)

3. ग्राम सांख्यकी

4. गांतों में वस्तुओं के खुदरा मूल्य

5. चुनी हुई वस्तुओं के साप्ताहिक खुदरा मूल्य

6. भमि उपयोग तथा फसल काटने सम्बन्धी तजर्बे।

(ख) जिन विषयों को सर्वेक्षण के 19वें राउंड में शामिल किया जा रहा है (जुलाई, 1964 से जून, 1965 तक)

1. ग्रामों में वस्तुओं के खुदरा मूल्य

2. भूमि उपयोग तथा फसल काटने सम्बन्धी तजर्बे

3. शहरी श्रम बल

4. ग्रामीण श्रमिकों का रोजगार, बेरोजगारी और ऋण ग्रस्तता

5. जन संख्या, पैदाइशें और मौतें

6. उपभोक्ता व्यय, घरों की हालतें, जन संख्या, पैदाइश और मौत और घरेलू क्षेत्र के उपक्रमों का उत्पादन, आदि ।

दो. विशेष और तदर्थ सर्वेक्षण :

1. मध्यवर्गी मूल्य समाहरण और घर का किराया सर्वेक्षण (मासिक)

2. वर्किंग क्लास के घरों का किराया सम्बन्धी सर्वेक्षण (मासिक)

3. कारखाना केन्द्रों में मज़दूरों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों/सहकारी भंडारों आदि से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की बिक्री (मई, 1964 से)।
तीन उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण :

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों का व्यय (1) नमूनों, अनुसूचियों, अनुदेशों आदि सहित तकनीकी डिजाइन, (2) आंकड़े इकट्ठे करने और (3) सारणीकरण के लिये व्यय किया जाता है। आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, उड़ीसा में क्षेत्र कार्य राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। डिज़ाइन और सारणीकरण सम्बन्धी अधिकांश कार्य भारतीय सांख्यिकीय संस्था द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों की अवधि वित्तीय वर्षों के साथ साथ नहीं चलती हैं। और इसलिये, संलग्न विवरण में दिये गये कुछ सर्वेक्षण इस अवधि के बाहर हैं। डिज़ाइन और सारणीकरण का कार्य अखिल भारत के आधार पर किया जाता है। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन मदों पर राज्यवार और सर्वेक्षणवार कितनी कितनी राशि व्यय की गई। इन बातों के कारण इस अवधि में सर्वेक्षणों पर किया गया कुल व्यय विशिष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। 1964–65 में उड़ीसा में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा क्षेत्र कार्य पर किये गये व्यय के बारे में भी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के कुछ समय बाद ही बताया जा सकता है। तथापि, जनवरी 1965 तक क्षेत्रीय कार्य पर लगभग 2.11 लाख रु० व्यय किये गये हैं।

पंचायत समितियों के कार्यालयों में टेलीफोन

815. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा में पंचायत समितियों के कितने कार्यालयों में टेलीफोन लगे हुये थे; और

(ख) 1965–66 में पंचायत समितियों के कितने कार्यालयों में टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 126.

(ख) 11.

Delhi Mail Motor Service

816. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) whether Government have received any complaint against the Delhi Mail Motor Service of the Postal Department regarding the wastage of petrol

by plying vehicles unnecessarily ; irregularities committed in the building of chassis for their vans ; pilferage of spare parts of the Departmental vans by the officers and of high rate of accidents caused by technical defects ;

(b) whether Government have inquired into these complaints ; and

(c) if so, the outcome thereof and the action taken in this matter ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati.) : (a) Yes. An anonymous complaint was received.

(b) Yes.

(c) The allegations could not be established and hence no action was taken.

राष्ट्रीय छात्र सेना दल के लिए लाईटमशीन गनें

817. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय छात्रसेना दल की यूनिटों को हल्की फौजी मशीन गनें (सर्विस एल० एम० जी०) नहीं दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगितायें रुक गई हैं ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो राष्ट्रीय छात्रसेना दल की यूनिटों को हल्की फौजी मशीन गनें उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : (क) एन० सी० सी० यूनिटों को जितनी संख्या में वास्तव में सैनिक एल० एम० जी० मिलनी चाहिएं, उससे बहुत कम दी गई है। परिणामस्वरूप पश्चिमी कमान की निशाना-बाजी ट्राफी प्रतियोगिता, जिसमें सैनिक एल० एम० जी० का प्रयोग आवश्यक था, 1962 से नहीं हो पाई ।

(ख) पहली प्राथमिकता स्थल-सेना की आवश्यकताओं को देनी पड़ती है। ज्यों ही एल० एम० जी० की प्राप्यता स्थिति सुधरेगी, और स्थल सेना की बढ़ती आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, एन० सी० सी० सहित अन्य मांगें भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी की जाएंगी ।

राज्यों के सूचना मन्त्रियों का सम्मेलन

818. **श्री कोया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तृत प्रचार नीति बनाने के लिए राज्यों के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के कब होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। सामान्य विषयों, विशेषकर प्रचार कार्य और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यकलापों में मेल रखने के प्रश्नों पर विचार के लिये राज्य के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन करने का प्रस्ताव है ।

(ख) गालिबन अप्रैल 1965 के आखीर में ।

नई दिल्ली के दुकान कर्मचारी

819. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के दुकान कर्मचारियों ने 31 जनवरी, 1965 को मुख्य आयुक्त के निवास स्थान के सामने प्रदर्शन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, अन्तरिम सहायता, वेतन-वृद्धि, सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्यूटी मुआवजा और निर्वाह निधि लाभ ।

Wireless Between Varanasi and Gorakhpur

820. **Shri Vishva Nath Pande :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Posts and Telegraphs Department have decided to introduce the micro-wave wireless communication system between Varanasi and Gorakhpur ; and

(b) if so, when it would be introduced and the amount of expenditure to be incurred on this scheme ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) No, but a multi-channel VHF system is being introduced.

(b) The VHF system will be ready by the end of 1966 and will cost approximately Rs. 7 lakhs.

संसदीय शिष्टमण्डल का नागालैण्ड का दौरा

821. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री पु० र० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में एक सप्ताह की अध्ययन यात्रा के लिए कोई संसदीय शिष्टमंडल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में अपने विचार रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किये हैं ?

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) हां,

(ख) 1. श्री एच० एन० मुखर्जी
2. श्री हेम बरुआ
3. प्रो० एन० जी० रंगा
4. श्री आर० जी० दुबे
5. श्री अन्सार हरवानी
6. श्री आर० बरुआ
7. श्री ए० पी० जैन
8. श्री एम० आर० मसानी

} सदस्य लोक सभा

9. डा० एम० एम० एस० सिधु
10. श्री चन्द्र शेखर
11. श्री आर० एस० खण्डेकर
12. श्री आई० के० गुजराल
13. श्री एम० पी० भार्गव
14. श्री आर० एस० पंजहजारी

} सदस्य राज्य-सभा

(ग) इस शिष्टमंडल द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

योजना का प्रचार

822. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वर्तमान योजना प्रचार व्यवस्थाओं को शक्तिशाली बनाने की विभिन्न योजनायें विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). योजना के प्रचार की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा हाल में योजना आयोग में हुई एक बैठक में की गई थी और यह फसला किया गया कि उक्त उद्देश्य के लिये आयोग में एक समिति बनाई जाए । यह समिति (क) प्रचार के विषय निर्धारित करेगी, (ख) योजना आयोग के विभिन्न विभागों की आधार सामग्री तैयार करने के लिये हिदायत देगी, और (ग) योजना प्रचार सम्बन्धी सुझावों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योजना प्रचार निदेशन और समन्वय समिति के सामने पेश करने के लिए तैयार करने में, सचिव की सहायता करेगी ।

दिल्ली में बेकार लोग

823. श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को दिल्ली के दोनों नौकरी दिलाऊ कार्यालयों में दर्ज बेकार लोगों की संख्या क्या थी ; और

(ख) 1962 और 1963 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख).

तारीख	चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या
1	2
31-12-1962	84,752
31-12-1963	86,872
31-12-1964	1,06,206

बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम

824. श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 1965 को बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम की व्यवस्था नेशनल स्टेडियम में की गयी थी ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम की व्यवस्था वाणिज्य मंत्रालय की प्रार्थना पर की गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) टिकटों से प्राप्त हुई राशि कितनी है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : (क) सशस्त्र सेनाओं के बैंडों द्वारा, अभिनव बीटिंग रिट्रीट समारोह में संगीत सहित एक बैण्ड समारोह कार्यक्रम का, नेशनल स्टेडियम में 7 फरवरी, 1965 को प्रबंध किया गया था ।

(ख) तथा (ग). यह उत्सव वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा, अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल के बीसवें अधिवेशन के लिए आए प्रतिनिधियों के मनोरंजन के लिए आयोजित किया गया था । बैंडों पर उठा खर्च आयोजकों से वसूल किया जाएगा ।

(घ) प्रतिनिधियों तथा अन्य निमंत्रित किए गए लोगों, फालतू स्थानों के लिए 2587 रुपये 50 पैसे के टिकट बेचे गए थे । प्राप्त राशि को सैनिकों के कल्याण-कार्य लिये प्रयुक्त किया जायेगा ।

ब्रिटिश नौसेना अध्यक्ष का आगमन

825. श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश नौसेना अध्यक्ष एक सप्ताह के लिए फरवरी 1965 के प्रथम सप्ताह में भारत आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके आने का प्रयोजन क्या था ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तथा (ख). एडमिरल सर डेविड लस, फर्स्ट सी लार्ड ने, परस्पर मामलों पर बातचीत करने के लिए 2 फरवरी से 7 फरवरी 1965 तक भारत की यात्रा की ।

कानपुर के निकट डाकघर पर डाका

826. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि 20 जनवरी, 1965 के आसपास कुछ सशस्त्र लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर जिले के जिनौरा गांव में एक डाकघर पर डाका डाला और डाक-टिकटें तथा नकदी लकर भाग गये ;

(ख) क्या इस विषय में कोई जांच अथवा गिरफ्तारी की गई है ;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी गत दो मास में इस तरह की घटनायें हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो (राज्यवार) उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) यह ठीक नहीं है । वास्तव में घटना यह हुई थी कि 15/16 जनवरी, 1965 को का पुर डिवीज़न के अधीन जिन्दौरा (जिनौरा नहीं) के शाखा डाकपाल ने गजनेर पुलिस थाने में डाकघर के रिकार्ड, नक़दी और दूसरी कीमती वस्तुओं की चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी ।

(ख) पुलिस की जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप उक्त डाक घर के निकट के एक बगीचे से रिकार्ड, डाकघर की मोहरें और डाक-टिकटें बरामद हुई थीं । 16 जनवरी, 1965 को पुलिस द्वारा शाखा डाकपाल के घर की तलाशी लेने पर 598 रुपये बरामद हुए, जो कि डाकघर की शेष नक़दी में कम थे । पुलिस ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है कि शाखा डाकपाल द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई थी वह ग़लत थी और वे भारतीय दण्ड विधान की धारा 182 के अन्तर्गत शाखा डाकपाल के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की जांच कर रहे हैं ।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागाओं के लिये पाकिस्तानी हथियार

827. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने नागाओं को भारी संख्या में पाकिस्तानी हथियार दिये हैं; और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में हुए युद्ध-विराम समझौते के पश्चात् 1,700 नागा विद्रोही सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये सीमा पार करके पाकिस्तान चले गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) मई, 1962 और जून, 1964 के बीच उपद्रवी नागाओं के तीन दल पूर्व पाकिस्तान गए और लौटे । सुलभ सूचना के अनुसार इन दलों ने पाकिस्तान में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया और वे अपने साथ हथियार और गोला-बारूद लाए । उपद्रवी नागाओं को कोई अन्य हथियार दिए जाने की सूचना नहीं है ।

(ख) अक्तूबर–नवम्बर 1964 में, लगभग 1500, उपद्रवी नागाओं का एक दल बर्मा होकर पाकिस्तान गया था। उन्हें भी शायद वैसी ही सुविधाएं मिलेंगी जैसी कि पूर्व दलों को मिली थीं ।

(ग) उपद्रवी नागाओं के इस दल का जाना युद्ध-विराम के क़रार की भावना का उल्लंघन है । यह बात शांति मिशन के ध्यान में लाई गई थी । शांति मिशन ने छिपे नेताओं को यह सूचना दी कि वह इस मामले को गंभीर समझते हैं । तब से लेकर अब तक उपद्रवी नागाओं के पूर्व पाकिस्तान जाने की कोई और रिपोर्ट नहीं आई है ।

कैंटीन स्टोर्स विभाग

828. **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैंटीन स्टोर्स विभाग (भारत) का संचालन वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विभाग के कर्मचारियों का पद-स्तर निर्धारित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) एक सरकारी उपकरण है और सेवाओं के सेविवर्ग के लिए, बिना किसी लाभ के उद्देश्य के इस वाणिज्यिक ढंग से चलाया जाता है । (सी० एस० डी० आई) चलाने का उद्देश्य है सेवाओं के सेविवर्ग को उनकी यूनिट लाइन के पास किराना तथा अच्छी किस्म की अन्य चीजें वाजिबी तथा एकसी लागत पर प्राप्त करना, जो भारत में किसी भी स्थान पर बाजार के मूल्यों से अधिक न हों । प्रासंगिक लाभ सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को सुख सुविधाएं प्राप्य करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए, इस विभाग के केवल मात्र ग्राहक हैं ।

(ख) सी० एस० डी० (आई) के कर्मचारी इसी की निधियों में से वेतन पाते हैं, न कि रक्षा सेवाओं के अनुमानों से, और इस कारण उन्हें सरकारी सेवक नहीं माना जाता । कर्मचारी-संघ के सदस्यों की कई बैठकों में अक्तूबर, 1965 में यह परस्पर तय पाया, कि इन कर्मचारियों की सेवा की स्थितिएं और शर्तें, तुल्य परिस्थितियों में, सेना के आयुध कारखानों में नियुक्त रक्षा के असैनिकों की तुल्य श्रेणियों के समतुल्य हों, इस समता की सिफारिश, संघ की मांगों पर विचार करने के लिए सितम्बर, 1964 में स्थापित की गई, तदर्थ समिति ने भी की थी और इस सिफारिश को दिसम्बर, 1964 में नियन्त्रक बोर्ड ने मान लिया था ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को सामने रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट

829. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
डा० रानेन सेन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (1) के कर्मचारियों के संघ ने एक मांग पत्र पेश किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी मांगों पर अंतिम रूप से विचार कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या 1964 में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल हुई थी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मांगों पर यूनियन के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श हो रहा है ।

(घ) जी, हां ।

कैंटीन स्टोर्स विभाग

830. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स विभाग (1) को 1963-64 में मुनाफा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विभाग के प्रबन्धकों का विचार इस मुनाफे में से अपने कर्मचारियों को बोनस देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) किसी लाभ के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा और इसलिए बोनस घोषित करना संभव नहीं है । विभाग, अग्रिम क्षेत्रों के सेवि-वर्ग सहित, जहां बाजार सुविधाएं प्राप्य नहीं हैं, सेवाओं के सेविवर्ग को किराना, की तथा अन्य चीजें, उचित तथा सामान्य दरों पर प्राप्य करने के लिए, संस्थापित किया गया है । विभाग को परिवहन में, रेल के सैनिक भाड़ादरों, आयकर, चुंगी महसूल से विमुक्ति इत्यादि सुविधायें प्राप्त हैं। रिज़र्वों के लिए व्यवस्था करने के पश्चात्, अधिक आय-लाभ, सेवाओ के सेविवर्ग के कल्याण कार्य में लगा दिया जाता है। लाभ का कुछ अंश हर वर्ष, कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) के कर्मचारियों को हितकारी निधि के रूप में प्राप्य किया जाता है ।

नया प्रसारण कार्यक्रम चालू करना

831. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० ब० राघवन् :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री यशपालसिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार प्रमुख केन्द्रों से 18 घन्टों का निरन्तर रेडियो प्रसारण कायक्रम चालू करने के बारे में सरकार अभी हाल में विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का निर्णय क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारी, खर्च और टेकनीकी पहलुओं पर विचार के बाद इस विषय में फ़ैसला किया जायेगा ।

Radlo Licences

832. **Shri Gulshan :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to issue Radio licences for a period of three years or more ;

(b) if so, the broad outlines of the scheme ; and

(c) when this scheme will be enforced ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati): (a) Yes, Sir.

(b) It has been decided to issue Broadcast Receiver Licences in book form in which there will be provision for renewals for 6 years in addition to the year of issue of the book. The question as to what concession in rate should be allowed in case of renewal for 3 years or more is still under consideration.

(c) the scheme is likely to come into force by September, 1965.

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री नेहरू के जीवन पर फिल्म

833. **श्रीमती लक्ष्मीबाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 23 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 338 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर पूरी फिल्म निर्माण करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : फिल्म विभाग विभिन्न सूत्रों से सामग्री एकत्रित कर रहा है ।

राष्ट्रीय मण्डलीय समुद्री केबल

834. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० ब० राघवन् :

क्या **संचार** मंत्री 16 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर से भारत तक राष्ट्रमण्डलीय समुद्री केबल की व्यवस्था करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). जी नहीं । प्रश्न अभी विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय होने में अभी कुछ समय लगेगा ।

Tarapore Atomic Power Station

835. Shri Baswant : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the acreage of land acquired for the Tarapore Atomic Power Station; and

(b) whether any land for land acquired for this station has been allotted to those whose lands were acquired ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) 1127 acres of land, including 701 acres of Maharashtra Government land, have been acquired for the Tarapore Atomic Power Station.

(b) No, Sir.

कलकत्ता में स्टेडियम के लिये भूमि

836. **डा० सारदीश राय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 1 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में स्टेडियम बनाने के लिये भूमि देने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की प्रार्थना पर अब तक अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) यह निर्णय किया गया है कि कलकत्ता मैदान में से 22.772 एकड़ भूमि एक फुटबाल स्टेडियम बनाने के लिये, पश्चिमी बंगाल सरकार को पट्टे पर दे दी जाय । यह निर्णय पट्टे की शर्तों पर समझौता होने पर निर्भर है, जिन पर आजकल राज्य सरकार से बातचीत हो रही है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

MURDER OF SARDAR PRATAP SINGH KAIRON AND THREE OTHER'S

सरदार प्रताप सिंह कैरों तथा तीन व्यक्तियों की हत्या

श्री बाल्मीकि (खुर्जा) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "6 फरवरी, 1965 को सरदार प्रताप सिंह कैरों तथा तीन अन्य व्यक्तियों की हत्या ।"

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : सदन के सदस्य मोटे तौर पर यह जानते हैं कि 6 फरवरी, 1965 को सरदार प्रताप सिंह कैरों तथा उनके साथियों

[श्री हाथी]

की हत्या किस प्रकार हुई । इस आंतकपूर्ण घटना से सारा देश स्तब्ध रह गया । पंजाब सरकार का शासन तंत्र, भारत सरकार से उपलब्ध सभी आवश्यक सहायता तथा साधनों के साथ, इस अपराध की खोज में लगा हुआ है । इस खोज की प्रगति के बारे में सदस्यों की चिंता उचित ही है । पंजाब के अधिकारियों ने समय-समय पर कुछ विवरण समाचार-पत्रों के जरिये तथा राज्य विधान सभा में दिये गए वक्तव्यों द्वारा दिये हैं । अस्तु, मैं नीचे घटनाओं तथा अब तक किये गये प्रयत्नों का एक संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं ।

6-2-1965 को दोपहर के 12.15 बजे चार आदमियों के आदेश पर वह कार रोक दी गई जिसमें सरदार प्रताप सिंह कैरों, श्री बल्देव कपूर, भूतपूर्व संयुक्त उद्योग निदेशक, पंजाब और सरदार प्रताप सिंह कैरों के निजी सहायक श्री अजीत सिंह सफ़र कर रहे थे । यह घटना जिला रोहतक के राई थाने में रसोई गांव के पास मील के पत्थर 18/4 के निकट घटित हुई । चारों आक्रमणकारियों ने कार को घेर लिया और सरदार प्रताप सिंह कैरों, उनके दोनों साथियों और ड्राइवर दलीप सिंह की अपने हथियारों से गोली मार कर हत्या कर दी । हत्यारों के पास एक राइफ़ल, एक शौट गन तथा दो रिवाल्वर थे ।

श्री नाथ पाई (राजपुर) : हत्या के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में पहिले ही प्रकाशित हो चुका है । हम केवल यह जानना चाहते हैं कि सरकार अपराधियों को पकड़ने में कहां तक सफल हुई है । **अन्बांधायें**) ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्य गण यह चाहते हैं कि विवरण पढ़ा जाये . . .

Shri Madhu Limaye (Monghyr). We want the Home Minister to be present in the House.

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मंत्री महोदय केवल घटना का विवरण पढ़ रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : We want a statement to be made by Shri Nanda himself.

Mr. Speaker : The Home Minister has gone somewhere else. The Minister of State is present in the House and I cannot compel them in this regard.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, is there any matter of more urgent importance other than this ?

Mr. Speaker : The hon. Member should not go on speaking like this.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि गृह मंत्री महोदय दिल्ली में हैं, तो उन्हें ही विवरण पढ़ना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि सदस्य गण क्यों यह शिकायत कर रहे हैं कि विवरण गृह-कार्य मंत्री द्वारा ही पढ़ा जाये जब कि राज्य मंत्री प्रश्न का उत्तर देने तथा विवरण पढ़ने के योग्य हैं ।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में गृह-कार्य मंत्री को सदन के समक्ष उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : वह राज्य-सभा में हैं । (**अन्तर्बाधायें**) ।

श्री रंगा (चित्तूर) : इस सदन की यह प्रथा है कि केबिनट मंत्री की अनुपस्थिति मैं कोई भी अन्य मंत्री अथवा उस मंत्रालय से सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति, किसी भी सन्देश को दे सकता है, प्रतिवेदन पढ़ सकता है और उस मंत्रालय की ओर से उत्तर दे सकता है ।

पुनर्वास मन्त्री (श्री त्यागी) : इस संसद की यह पुरानी प्रथा है कि मंत्री की अनुपस्थिति में, राज्य मंत्री अथवा उपमंत्री, यहां तक कि अन्य किसी विभाग का मंत्री, उत्तर दे सकते हैं। यह संयुक्त उत्तरायित्व का प्रश्न है और इस पर मैं आप का विनिर्णय चाहता हूं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I now whether the Minister is speaking on behalf of the Government or expressing his personal opinion ?

श्री त्यागी : किसी विशेष मंत्री को तब तक उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस पर व्यक्तिगत अभियोग न हो ।

अध्यक्ष महोदय खड़े हुये—

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : अध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, जब आप खड़े होते हैं, तो क्या तब भी कोई सदस्य "व्यवस्था का प्रश्न" कह कर आपका ध्यान आकृष्ट कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने "व्यवस्था के प्रश्न" के बारे में विरोधी दलों के नेताओं तथा कुछ विरोधी सदस्यों की एक बैठक बुलायी थी; उसमें हमने जो निर्णय लिए थे उन्हें मैं अब पढ़ूंगा । इस विशेष मामले में मैं उनका 'व्यवस्था का प्रश्न' सुनने के लिए बैठ गया था । माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : No point of order should be raised while the Speaker is on his legs.

Shri Nath Pai : This is an old and regular practice of this House.

अध्यक्ष महोदय : हमारा बर्ताव शिष्ट होना चाहिए । अब मैं उन लिये गये निर्णयों अथवा दिये गये सुझावों की ओर निर्देश करूंगा :

(एक) किसी सदस्य जिसे व्यवस्था का प्रश्न उठाना हो, खड़ा होना चाहिए और "व्यवस्था का प्रश्न" कहना चाहिए । जब तक कि अध्यक्ष अथवा पीठासीन व्यक्ति उसे पहिचान न लें, सदस्य महोदय को उसके बारे में आगे नहीं बोलना चाहिए । जब सदस्य को पहिचान लिया जाये, सिर्फ तब ही उसे अपने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में आगे बोलना चाहिए ।

[अध्यक्ष महोदय]

(दो) व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय सदस्य को, सदन की जिस प्रक्रिया की उपेक्षा अथवा उल्लंघन किया गया हो, उससे सम्बन्धित संविधान का प्रबन्ध अथवा विशिष्ट नियम बताना चाहिए ।

(तीन) जब अध्यक्ष बोल रहे हों, तो किसी भी सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिए अथवा न ही खड़े होकर या बैठकर बोलना चाहिये ।

इसके बाद यह निश्चय किया गया :—

"अध्यक्ष की बात शान्ति से सुननी चाहिए और जो सदस्य बोलना चाहते हों, उन्हें अध्यक्ष के बैठ जाने के बाद और अध्यक्ष द्वारा उन्हें बोलने के लिए कहे जाने के बाद ही खड़ा होना चाहिए ।

(चार) जिन विषयों के सम्बन्ध में अध्यक्ष कोई सहायता न दे पाया हो, ऐसे विषय "व्यवस्था का प्रश्न" नहीं होने चाहिए । यदि कोई सदस्य मंत्री से अथवा मंत्री के वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हो, तो उसे अध्यक्ष की अनुमति से सदन में इस प्रकार कहना चाहिए और व्यवस्था प्रश्न के रूप में उसे नहीं उठाना चाहिए ।

मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इन सुझावों को ध्यान में रखें जिससे कि सभा का कार्य सुचारू रूप से चल सके, जैसा कि श्री रंगा ने इस सदन में चली आ रही प्रथा के विषय में कहा कि सम्बन्धित मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रालय का कोई भी अन्य मंत्री प्रश्नों, ध्यान दिलाने वाले सूचनाओं, यहां तक कि स्थगन प्रस्तावों आदि, जो भी हो, के उत्तर दे सकते हैं । सम्बन्धित विवरण चार पृष्ठ का है । सदस्यों का आग्रह है कि गृह मंत्री ही इसे पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें, अतः मैं राज्य मंत्री जी से इस विवरण को सभा पटल पर रखने और उसे सदस्यगणों में परिचालित करने के लिए कहता हूं और गृह-कार्य मंत्री से अपराह्न 4.45 पर इस सदन में उपस्थित होने के लिए कहता हूं ताकि उनसे सम्बन्धित मामले में प्रश्न पूछे जा सकें ।

कई सदस्य गण : जी, नहीं, जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा ने इसका निर्णय करना है ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यह बिलकुल उचित है ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की अन्तर्बाधायें नहीं होनी चाहिएं । मैं केवल सभा की राय जानना चाहता हूं ।

कई सदस्यगण : जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : तब माननीय मंत्री महोदय विवरण पढ़ सकते हैं ।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : मंत्री महोदय को पूछे गये प्रश्न से सम्बन्धित भागों को पढ़ने दिया जाये ।

श्री हाथी : रसोई थाने में इस घटना की सूचना रसोई गांव के सरपंच ने दोपहर के लगभग 12.45 पर दी थी। थानेदार मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, अपने साथ एक हैड कान्स्टेबिल तथा तीन कान्स्टेबिलों को ले कर जो उस समय उपलब्ध थे एकदम एक कार में घटनास्थल की ओर रवाना हो गया और लगभग 1.05 बजे मौके पर पहुंच गया। इतने में थाने के क्लर्क ने पुलिस सुपरिटेंडेंट, रोहतक, पुलिस थाना समालखा (जिला करनाल), पुलिस थाना सोनीपत (जिला रोहतक), पुलिस थाना नरेला (दिल्ली) और चंडीगढ़ को टेलीफोन द्वारा सूचना भेज दी। उस ने घटनास्थल से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित केन्द्रीय सरकार के पुलिस केन्द्र के कमांडेंट से भी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस बात का प्रबन्ध करने के बाद कि घटनास्थल पर किसी चीज के साथ कोई छेड़-छाड़ न की जाये, स्थानीय पुलिस ने भागते हुए अपराधियों का रास्ता रोकने के लिये नाकाबन्दी कर दी। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की मदद से संगठित खोजी दस्ते अपराधियों की तलाश में निकल पड़े। भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की गतिविधि की भी एकदम दिल्ली में पड़ताल की गई। गुप्तवार्ता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पुलिस के अधिकारीगण जिन में दिल्ली पुलिस के दो उप-महानिदेशक भी शामिल थे (महानिरीक्षक की अनुपस्थिति में जो कि दौरे पर थे), दिल्ली अपराध अनुसंधान विभाग का खोजी दस्ता, फोटो यूनिटें और पीछा करने वाले घटनास्थल पर मध्याह्न में लगभग 3.15 बजे पहुंच गए। केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अपराध अनुसन्धान विज्ञान की प्रयोगशाला, कलकत्ता के विशेषज्ञ उसी रात को वायुयान द्वारा घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और अगले दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ही घटनास्थल पर पहुंच गए। इस के अलावा चंडीगढ़ की अपराध अनुसन्धान प्रयोगशाला का चलता फिरता दस्ता भी पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने अन्य पुलिस संगठनों से एकदम सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक वायरलैस सैट भी वहां लगा दिया।

लाशों को सोनीपत हस्पातल में ले जाया गया जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 7 फरवरी, के प्रातःकाल उन की शव-परीक्षा की। सरदार प्रताप सिंह कैरों के शरीर पर .32 बोर के रिवाल्वर से चलाई गई गोलियों के 2 जख्म थे, एक बांई आंख के नीचे और दूसरा बांयें कान के नीचे। गोलियों के बाहर निकलने के कोई जख्म नहीं थे।

अंगुलि-चिह्न विशेषज्ञ कार के शीशे के बाहर की तरफ उंगलियों के कुछ दाग ढूंढ़ने में सफल हो गए। उन के फोटो ले लिये गए। घटनास्थल पर तथा अपराधियों द्वारा पकड़े गए रास्ते पर मिलने वाले पदचिह्नों को भी ढूंढ़ कर उन के फोटो लिये गए और प्लास्टर के सांचों में उतार लिया गया।

दिल्ली, पंजाब तथा सारे पड़ौसी क्षेत्रों में विस्तृत जांच-पड़ताल करने के लिये तुरन्त ही उपयुक्त जांच दल बनाए गए। मामले के विभिन्न पहलुओं और प्राप्त विभिन्न सूत्रों की जांच करने के लिये अलग अलग दल नियुक्त किए गए। होटलों, सरायों, गैरेजों तथा मोटर ट्रांस्पोर्ट कपनियों में तुरन्त जांच की गई।

इस खोज के लिये पंजाब पुलिस का एक विशेष दल नियुक्त किया गया है जिस में दो उप-महानिरीक्षक पुलिस, 5 पुलिस अधीक्षक, 10 उप-प्रधीक्षक पुलिस, 40 अराजपत्रित अधिकारी और लगभग 100 कांस्टेबिल हैं। इस के अलावा दिल्ली पुलिस से खास तौर पर इस खोज के लिये 1 पुलिस अधीक्षक, 2 उप-अधीक्षकों और 3 निरीक्षकों की सेवायें उपलब्ध हुई हैं। गुप्तवार्ता विभाग के कुछ चुने हुए कर्मचारी भी गुप्त सूचनायें एकत्रित करने और पंजाब पुलिस की सहायता करने के लिये नियुक्त किए गए हैं। पंजाब के एक पुलिस अधीक्षक के अधीन एक विशेष दल, सभी सम्भव सन्देहास्पद व्यक्तियों की पड़ताल करने के लिये, दिल्ली में काम कर रहा है। जांच करने वाले इन सभी दलों में बहुत निकट का

[श्री हाथी]

सम्पर्क रखा जा रहा है। दिल्ली तथा पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी अपने प्रयत्नों में तालमेल रख रहे हैं। पंजाब के मुख्य मंत्री के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार ने गुप्त वार्ता विभाग के निदेशक को हिदायतें दी हैं कि वे लगातार इन खोजों को देखते रहें, आवश्यक मार्ग दर्शन देते रहें और यह बात भी देखते रहें कि दिल्ली तथा पंजाब के खोज करने वाले अधिकारियों के प्रयत्नों में तालमेल बना रहे। उन्हें इस बात का ध्यान रखने का भी आदेश है कि जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों की पुलिस का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। इस अपराध के लिये किसी भी सम्भव उद्देश्य को असंगत मान कर छोड़ा नहीं गया है। अनुसन्धान करने वाले अधिकारी अपने मस्तिष्क को खुला रख कर चल रहे हैं और सूत्रों के सभी प्रकारों और सम्भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। गुप्त वार्ता विभाग के निदेशक के निकट सहयोग तथा सक्रिय सम्पर्क से और इस तथ्य से कि गुप्त वार्ता विभाग के अधिकारी इस काम पर लगाए गए हैं, विश्वास किया जा सकता है कि व्यक्तिगत बदले जैसे उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों पर भी कम ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अब तक 7,000 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की गई है और हजारों बदचलन व्यक्तियों कि गतिविधियों तथा लगभग 4,600 गाड़ियों की जांच की गई है। इस मामले की खोज में सहायता दे सकने वाली प्रत्येक सूचना तथा सूत्र की जोरशोर से पड़ताल की गई है और उस की पूरी जांच की गई है। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कुछ सूत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर गम्भीरता से अध्ययन और काम किया जा रहा है।

इह तरह के मामले की खोज की प्रक्रिया अक्सर लम्बी होती है। बहुत सी ऐसी जानकारी के ढेर को छांटना पड़ता है जिस में अधिकतर अविश्वसनीय होती है और जो काम की होती है उस के अनुसार काम करना होता है। विभिन्न सूत्रों की बार-बार ठोक बजा कर जांच करनी पड़ती है। इस सब में समय लगता है। पुलिस को उपलब्ध जानकारी में से अधिकतर अभी प्रगट नहीं की जा सकती क्योंकि इस से खोज के काम पर उल्टा असर पड़ सकता है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय सारे विवरण को प्रगट करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को समझेंगे। मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी गहराई से सम्भव हो सकता है इस मामले की खोज की जा रही है, राज्य सरकार को ज्यादा-से ज्यादा मदद दी जा रही है और किसी भी अवस्था पर इस मामले में ऐसी देरी नहीं लगी जिस से बचा जा सकता हो और किसी भी सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा रही है।

Shri Balmiki : In our democracy it is really very painful and unfortunate that a prominent figure like Sardar Pratap Singh Kairon was murdered. At the same time it is more shameful and condamnatory that a crime of this nature has not so far been investigated and the culprits are at large. In view of the fact that more than one month has elapsed since the crime was committed, may I know the reasons for the delay to this extent and whether the case would now be referred to the C. B. I. for investigation ?

Shri Hathi : The investigaton that has been made till now.....

Mr. Speaker : Only the latter part of the question may be answered.

Shri Hathi : For this purpose, the Panjab Government will be given the fullest assistance.

Shri Prakash Vir Shastri : The panicky news relating to the day light murder of Shri Kairon committed on the Delhi-Ambala Road. . .

Mr. Speaker : The hon. Member need not repeat what has already appeared in the newspapers.

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that almost thirty Members of the Panjab Legislative Assembly have written to the Prime Minister and the Government of India that they suspected the possibility of a political motive behind this murder. I, therefore, want to know whether the Prime Minister has given any instructions to the Investigation Committee or the Home Ministry to ensure that the possibility of a political motive behind the murder could also be explored.

Shri Hathi : As I said in the statement :

"किसी भी सम्भव उद्देश्य को असंगत मान कर छोड़ा नहीं गया है और अधिकारियों से विस्तृत जांच करने के लिए कहा गया है . . . . . मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर" ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, my question is very clear and. . .

Mr. Speaker : The hon. Minister said in his statement that no possible motive other than these of personal revenge for the crime is ruled out, and investigation is being made.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : May I know whether it is a fact that a blue colour car in which a Minister, named Shri Dange, of the Rajasthan Legislative Assembly was seated passed through the scene of the incidence which was stopped and he was requested to give a ring and he did not comply with the request ?

Shri Hathi : The investigation will cover all these things.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The Post-mortem Examination Report says that Sardar Pratap Singh Kairon was fired from a ·32 revolver. In view of the fact that no license is issued for the said revolver to any of the citizens of Panjab, and it is in the custody of officers only ; may I know whether there can be a possibility of officers having a hand in the murder ?

Shri Hathi : Not only bad characters, but all have been interrogated, and enquiry about the arms is also in progress.

Shri Buta Singh (Monga) : In view of the fact that a big police-personnel including high ranking officials have not succeeded in bringing the culprits to book, may I know whether the Home Minister contemplates to assign the responsibility to the local Sub-Inspector of Police for its investigation.

Shri Hathi : It is quite a different thing to assign this responsibility to a particular person, but we have to keep in mind all the aspects while issuing directions.

Shri Gulshan (Bhatinda) : The former Home Minister of the Panjab Legislative Assembly in a Statement made by him accused some of the Cabinet Ministrers of Panjab of this crime leading to the murder of Shri Kairon. In view of this, may I know whether the Central Government are prepared to investigate this matter themselves ?

Shri Hathi : At this stage, everything what is said, is not a fact. So far as the Central Government is concerned, as I said, the fullest assistance would be given to the Panjab Government on demand.

Shri Naval Prabhakar (Delhi—Karol Bagh) : May I know whether it is a fact that the man who lodged the report with the Police also died ?

Shri Hathi : Yes, it is a fact.

Shri Naval Prabhakar : What was the cause ?

Shri Hathi : : Heart failure.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : पंजाब और दूसरे स्थानों में यह धारणा बनती जा रही है कि सरकार जांच करने की बजाय दिखावा कर रही है। क्या सरकार ऐसी धारणा को खंडन करने को तैयार है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा है कि यहां के निदेशक तथा अन्य अधिकारी उचित निदेश दे रहे हैं ताकि जांच ठीक ढंग से चलती रहे।

Shri Bagri (Hissar) : The people in Punjab and at other places think that the politicians are behind this murder. Is Central Government prepared to arrogate to itself full responsibility of this work ?

Shri Hathi : The Central Government is prepared to afford all co-operation in this matter. But under our constitution the prime responsibility for law and order is of the State Governments.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Since Pratap Singh Kairon was not an ordinary man and was a controversial figure when alive, is the Central Government to alley the doubts of the people about the sincerity of Panjab Ministers about it, prepared to take this enquiry into its own hands ?

Shri Hathi : The Government of India will not enquire into it directly but will give all possible help to the State Government who are already looking into it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Will Government hold an enquiry about the conduct of a Deputy Minister of Rajasthan who passed that way when Sardar Pratap Singh Kairon was murdered but did not inform police about it but made a wrong statement in the State Legislature that when he passed that way, the police was already present there.

Mr. Speaker : The Minister is not present here to defend himself and as such this question cannot be put in this House.

श्री हाथी : बहुत सी बातें इस जांच के दौरान सरकार की निगाह में आई हैं उन में एक यह भी है जो माननीय सदस्य ने कही। परन्तु जब तक पूरी जांच न हो जावे यह नहीं कहा जा सकता कि इस घटना का उस अपराध से कितना सम्बंध है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : The atmosphere in Punjab for the last some years has become very poisionous and so in such circumstances does not the Central Government think that to leave this matter to the State Government is not proper ?

Mr. Speaker : This question has been raised frequently.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या सरकार यह जांच करवाने को तैयार है जिस की मांग श्री हुकम चन्द कछवाय ने किया है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, उन्होंने कह दिया है ।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : इस घटना का कत्ल से कोई सम्बन्ध न हो ? परन्तु एक भले व्यक्ति के नाते क्या यह उन का कर्तव्य नहीं था कि यदि कोई कत्ल हुआ हो तो वह वहां रुक तो जावें ?

अध्यक्ष महोदय : हम यहां यह निर्णय करने नहीं बैठे हैं कि उस ने अपना कर्तव्य किया या नहीं ।

Shri Mauriya (Aligarh) : When Sardar Pratap Singh Kairon was removed from his office, it was evident that he had many enemies, both in politics as well as in administration. In view of this fact were some arrangements made for his protection ?

श्री हाथी : जब सरदार कैरों अपने पद से हटें तो उन्हें संरक्षक दिया गया था । परन्तु उनके अपने ही अनुरोध पर वह हटा लिया गया ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अपने बध होने से पहले सरदार प्रताप सिंह कैरों दिल्ली आये और वे यहां प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री से मिले और उस में उन्होंने यह भी कहा बताया जाता है कि अपने पुत्रों आदि के बारे में भी कहा कि वे किस प्रकार कर से बच रहे हैं, आदि आदि । इस बात का ध्यान रखते हुए क्या उन्हें अपने पुत्रों से बचने के लिये कुछ किया गया ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं स्वर्गीय सरदार कैरों से काफी दिन से नहीं मिला था । वह मेरे पास नहीं आये ।

श्री स० मो० बनर्जी : समाचारपत्रों में छपा था कि वे प्रधान मंत्री से मिले । क्या यह सच है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : वह मुझ से मिले थे । परन्तु मुझ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा ।

Shri Prakash Vir Shastri : On a point of order Sir, I want to know why the Government is avoiding the reply to the question which is being asked again and again ?

Mr. Speaker : Under our constitution Law and Order is a State subject and so the State Government is making investigation into it.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या सरकार को पता है कि पंजाब में यह अफवाहें चल रही हैं कि इस कत्ल में भारत सरकार के कुछ नेताओं का भी हाथ है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : जी नहीं, ऐसा तो विचार करना भी व्यर्थ है।

Shri Priya Gupta (Katihar) : In view of the fact that some high officials of Punjab were against Sardar Kairon, why should the Central Government put up the plea of the subject being in State list ? In view of the importance of the case, why does the Central Government take it into its own hands ?

श्री नन्दा : केन्द्रीय गुप्त वार्ता (इंटैलीजेंस) ब्यूरो के निदेशक ने इस कार्य का सारा समन्वय अपने हाथ में ले लिया है और इसलिये हम अपनी शक्ति के अनुसार वह कर रहे हैं जो आवश्यक है।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : In view of the fact that Sardar Kairon's dead body was removed eight hours after his murder, the difficulties experienced by the State Government and Central Government's full cooperation with the Punjab Government and even then that Government has failed, does not the Central Government think it necessary to take this work in its hands or give such assistance as the Punjab Government may be successful in its work ?

Shri Hathi : We will give to the State Government whatever experts they want from us or officers or special instruments, whenever they require.

श्री नारायण डांडेकर (गोंडा) : आपने कहा है कि जांच करना संविधान के अनुसार राज्य सरकार का कार्य है और मंत्री ने यह भी कहा कि वह हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। साथ ही यह भी कहा है कि किसी भी उद्देश्य को, चाहे वह राजनीतिक ही क्यों न हो, की उपेक्षा नहीं की जावेगी। जब आप ने यह कार्य राज्य सरकार पर छोड़ रखा है तो आप कैसे इस सदन को विश्वास दिला सकते हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों की उपेक्षा नहीं की जावेगी ?

श्री हाथी : क्योंकि समन्वय का कार्य निदेशक ने अपने हाथ में लिया हुआ है इसलिये वह निदेश देते हैं और देखते रहते हैं कि किन तरीकों से जांच हो रही है।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : There was a press report that the culprits of this case had fled to Pakistan, may I know whether this is correct ?

Shri Hathi : The Government has no information about it.

Shri Daljit Singh (Una) In view of such delay in the matter, why the Central Government has not taken this matter into its own hands ?

श्री नन्दा : हम जो समन्वय कर रहे हैं तथा जो सहायता दे रहे हैं उस का कुछ महत्व है।

श्री इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : कत्ल के एक दिन पश्चात् पंजाब सरकार के गृह-कार्य सचिव ने यह वक्तव्य दिया जो "ट्रिब्यून" नामक समाचारपत्र में छपा था कि यह कोई राजनीतिक कत्ल नहीं है। इसी प्रकार के वक्तव्य पंजाब के अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों ने दिये और इसलिये इस सारे मामले को एक नये ढंग से ऐंठ दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री आदि इस ओर क्या कार्य कर रहे हैं ?

श्री नन्दा : मैंने अधिकारियों से बातचीत की है और उन्हें यह विश्वास दिला दिया है कि वे अपनी जांच करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान न करें कि किस व्यक्ति ने क्या कहा है।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I want to know whether any arrests have been made so far in this connection?

Shri Hathi : Some persons were arrested only for interrogation. No other arrests have been made.

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : यह काफी जोर से कहा गया है कि हत्या के बारे में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस के पीछे कौन सा उद्देश्य था। एक पुलिस अधिकारी श्री माथुर ने कई बार वक्तव्य दिया है कि अपराध के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। दोनों में से कौन सी बात सच हैं ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने बताया मुझे किसी वक्तव्य का पता नहीं है . . . . (**अंतर्बाधाएं**)

एक माननीय सदस्य : जांच के संबंध में इनकी इतनी जानकारी है।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : An army officers has been entrusted the work of investigation, but the man who lodged the first information report has died and no post mortem has been carried out on his body. The Medical Officer of Sonepat was informed very late. Are there any constitutional difficulties which hinder Government taking this case in its own hands ?

श्री नन्दा : इसका उत्तर दिया जा चका है।

Shri Hari Vishnu Kamat : Is it enquiry or investigation ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विधान आदि के संशोधन के बारे में विवरण

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संविधान, 1964 में संशोधन करने सम्बन्धी लिखतों (संख्या 1–3) के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3933/65]

(दो) कहवा बागान उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू०बी—3(26)/64, दिनांक 3 मार्च, 1965।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3934/65]

(तीन) रबड़ बागान उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी—3(3)/65, दिनांक 4 मार्च, 1965।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3935/65]

मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : मैं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पंचवर्षीय योजना प्रसार सम्बन्धी मूल्याकंन समिति के एक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—3936/65]

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITEE

राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकर समिति

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) (एक) के अनुसरण में, लोकसभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधि– नियम के अन्य उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन 1 जून, 1965 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय सेनाछात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) (एक) के अनुसरण में, लोकसभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधि- नियम के अन्य उपबन्धों तथा उन के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन 1 जून, 1965 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय सेनाछात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

केरल आय व्ययक 1965-66

KERALA BUDGET, 1965-66

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं वर्ष 1965–66 के लिये केरल राज्य की अनुमित आय तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

रेलवे आय व्ययक सामान्य चर्चा––जारी

RAILWAY BUDGET GENERAL DISCUSSION--*contd.*

श्री नेसामनी (नागर कोइल) : जिस शीघ्रता से पाम्बन पुल का पुनः निर्माण किया गया है मैं उसके लिये रेलवे मंत्री का आभारी हूं । रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में नई रेलवे लाइनों का जिक्र किया, जिन्हें कि चतुर्थ योजना में रखा गया है । उनमें से एक लाइन टिन्नेवेली से कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम तक बनाई जायेगी । इस लाइन के निर्माण के लिये यह शर्त रखी गई है कि चूंकि उन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास नहीं है इसलिये चौथी योजना में उपलब्ध संसाधन और निष्पादन की प्राथमिकता के आधार पर इस लाइन को लिया जायेगा । केरल सरकार ने बार बार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस रेलवे लाइन के न होने से वहां पर उद्योगों के विकास में देर लग रही है । वहां पर मोनाजाईट के दो कारखाने हैं । उनका उत्पादन अमरीका को भेजा जा सकता है और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है । परन्तु जब तक इसके लिये उचित यातायात की व्यवस्था नहीं होगी

हम विदेशी मंडी में इसको सस्ते दामों पर नहीं बेच सकते और अपनी आय नहीं बढ़ा सकते। कारखाने का विस्तार किया जा रहा है और इसके उत्पादन के सुविधाजनक निर्यात के लिये इस लाइन का निर्माण करना अत्यवाश्यक है ।

इस क्षेत्र में रबड़ और चाय का भी उत्पादन होता है जिसे पहले कोचीन भेजा जाता है और फिर विदेशों को निर्यात किया जाता है । इन वस्तुओं को भेजने में संचार साधनों की कठिनाइयां रास्ते में आती हैं और व्यापार को हानि होती है । इसलिये हमारा निवेदन है कि इस लाइन को कम से कम चतुर्थ योजना में ले लिया जाये । लाइन के मार्ग के लिये एक तो सुझाव यह है कि लाइन को बलीपूर से नगेर कोइल तक बरास्ता कन्याकुमारी ले जाया जाये और दूसरा यह कि इसको वली-पूर से आरामबोली तक सीधे ही बरास्ता पानागुड़ी ले जाया जाये । दूसरा सुझाव अधिक अच्छा है क्योंकि सड़क और रेल की प्रतिस्पर्धा कम हो जायेगी और यह रास्ता भी छोटा है ।

टिकटें रिजर्व कराने के लिये केवल एक ही आउट एजेंसी है जो कि नगेर कोइल में है और रेलवे स्टेशन से 50 मील दूर है। वहां पर बड़ी भीड़ होती है और लोगों को टिकट रिजर्व कराने के लिये प्रायः तिरुनलवेली में जाना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि नगेर कोइल रेलवे स्टेशन पर अधिक टिकटें रिजर्व कराने की व्यवस्था की जाये ताकि यात्रियों को अधिक कष्ट न हो।

आउड एजेंसियों पर ही नहीं अपितु शहरों और जंकशनों पर भी टिकटें रिज़र्व कराने में दिक्कत होती है। कहा जाता है कि यात्रि अभिकरण पहले बहुत सारी टिकटें रिज़र्व कर लेते हैं और फिर बाद में उन्हें रद्द कर देते हैं इस प्रकार लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। रेलवे को इस बात की जांच करनी चाहिये। ताकि एक साधारण यात्री को कोई कठिनाई न हो।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : On a point of order. Sir, There is no quorum in the House.

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है ।

श्री नेसामनि : यह खुशी की बात है कि रेलवे पर भोजन व्यवस्था में सामान्य रूप से सुधार हुआ है। परन्तु मेरा अनुरोध है कि रेलवे को भीजन आदि को देखना चाहिये और उसकी किस्म में सुधार करना चाहिये ताकि उन लोगों की संतुष्टि हो जाये जो रेस्टोरेन्ट कारों और रिफ्रेशमैंट रूमों में खाना खाते हैं ।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : In the budget there are proposals for taxation, but will the hon. Railway Minister give assurance that more trains will be run and facilities will be provided and passengers relieved of great rush on Railways. The passenger travelling by night trains are very much inconvienced in the absence of enough sleeping coaches. Now that Government is proposing taxes. I hope enough 2 tier and 3 tier sleeping coaches will be provided for the passengers travelling by third Class. The fans in the third class coaches and even in first class coaches are not in good conditions. They should be properly checked and looked into.

I have appealed to the Government several times to provide fast trains between Vijayanagaram and Delhi *via* Raipur, Bilaspur, Katni and Veena. Now the run between these two places is 36 hours. This will cover parts of Orissa, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Government may kindly give consideration to this proposal as the people will very much benefit by it.

[Shri A. . aigal]

The policy of Railway Ministry is not to give concession to any religious organisations for its annual conference. But I do not understand why special concession were given to one association who held its Conference in Bombay. But there is an organisation which does not prefers any religion and which is headed by Avtar Mehar Bawa. After two years this organisation is having its Darshan Programme. I had requested the Ministry on their behalf but that was turned down. I think that a Committee should be appointed to look into such requests.

The coolers have been put up at various places but they were not in working order and require to be regularly checked.

The genuine grievance of the class II, III and IV employees are not being redressed. The officers of the Ministry and Members of Parliament should get togteher to consider their demands on price index basis.

The train running from Ahmedabad to Bhopal should be extended upto Allahabad.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : रेलवे बजट में किराये और भाड़े में वृद्धि करने का जो सुझाव है मैं उसको नहीं समझ सकता हूं । किसी भी सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया है । आजकल जब कि महंगाई इतनी बढ़ गई है और लोगों का गुज़ारा नहीं चलता है ऐसा करना उचित न होगा ।

सीजन टिकट के किराये में वृद्धि का सुझाव है । मेरा निवेदन है कि सीज़न टिकटों का प्रयोग मुख्यतः कारखानों में काम करने वाले मज़दूर करते हैं न कि अमीर लोग और इस 50 पैसे की वृद्धि भी उनके लिये बोझ बन जायेगी । सरकार इस घाटे को और तरीकों से पूरा कर सकती है । रेलवे समय समय पर किसी न किसी बहाने किराये में वृद्धि करती रही है । यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोगों में असंतोष फैल जायगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
The Deputy Speaker *in the Chair*]

कहा जाता है कि वैज्ञानिक व्यवस्था के कारण मरम्मत के कामों में काम करने वाले श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है । ऐसा करना बिलकुल उचित नहीं है और इसके विपरीत बड़े अफसरों की संख्या बढ़ाई जा रही है । सरकार के किराये भाड़े में वृद्धि करने के स्थान पर उच्चपदाधिकारियों की संख्या को कम करना चाहिये और इस प्रकार किराये के घाटे को पूरा करना चाहिये ।

प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिये भी पैसा खर्च नहीं किया जाता है और इसके विपरीत फालतू चीजों पर फिजूल खर्ची की जाती है जिससे कोई फायदा नहीं होता है ।

जब भी किसी स्टेशन बनाने के लिये उचित मांग रखी जाती है तो सरकार बहाना लगा देती है कि पैसा नहीं है । परन्तु दुर्गापुर में बिधानराय स्टेशन की कोई जरूरत

नहीं थी मगर कांग्रेस का अधिवेशन होने के कारण वहां स्टेशन बनाया गया । इस पर 6 लाख रु० खर्च आया है । और बना कर फिर इसे गिरा दिया गया है क्योंकि वहां पर यात्री नहीं थे ।

बैल्ली मेन लाइन और हावड़ा बर्दवान मोड़ लाइन के मिलने के स्थान पर लोग कब से स्टेशन बनाने की मांग कर रहे हैं। परन्तु रेलवे कहती है कि पैसा नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय उपमंत्री वहां जायें और स्थिति को देखें ।

जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो आप एक विशेष स्टेशन मंजूर कर देते हैं लेकिन जब कोई धार्मिक मेला होता है जिसमें 10 अथवा 14 लाख व्यक्ति जाते हैं तो और स्टेशन की मांग की जाती है तो आप कहते हैं कि हमारे पास डिब्बे नहीं हैं।

स्टेशन के प्लेटफार्मों को नियमित रूप से साफ नहीं किया जाता है । हावड़ा बर्दवान सेक्शन पर बिजली से चलने वाली गाड़ियों में कोई शौचालय अथवा पेशाबघर नहीं है । सेरामसुर के स्टेशन पर जब मैं ने पेशाबघरों को न साफ करने का कारण पूछा तो बताया गया कि पानी उपलब्ध नहीं है । माननीय मंत्री कृपया इन बातों की ओर ध्यान दें ।

पिछले सत्र के दौरान एक मंत्रणा बैठक में माननीय रेलवे मंत्री ने कहा था कि कलकत्ता में एक सरकुलर रेलवे होनी चाहिये। इस पर वह वास्तव में सहमत हैं, परन्तु एक अकेले शहर के लिये 5 करोड़ रु० का खर्च कौन बर्दाश्त करेगा । इस तर्क में कोई औचित्य नहीं है । पश्चिम बंगाल सरकार सर्वेक्षण आदि के लिये 10 लाख रु० देने के लिये तैयार हैं। वहां पर यातायात की हालत बहुत अधिक बिगड़ गई है और वहां के लोग यह आशा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार वहां पर यह रेलवे बनाने पर सहानुभूति-पूर्ण विचार करे ।

हावड़ा स्टेशन की हालत इतनी खराब है कि गाड़ी से प्लेटफार्म पर उतरने को जी नहीं करता । स्टेशन पर से हावड़ा पुल तक भूमि के नीचे रास्ता बनाने का ज़िक्र चला था । यदि इसे बना दिया गया तो लोगों को काफी राहत मिलेगी । इसकी भी जांच होनी चाहिये ।

पश्चिम बंगाल में बहुत सी छोटी रेलें हैं जो गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जाती हैं। वे लोग अपनी मनमानी करते हैं और समय पर गाड़ियां नहीं चलाते हैं। और न ही आस पास बसों को चलने देते हैं जिससे जनता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है । सरकार को चाहिये कि इन रेलों को अपने हाथ में ले ले।

लिलुआ वर्कशाप में चीनी आक्रमण से पहले काम के $42\frac{1}{2}$ घंटे थे। आपात की घोषणा पर वहां के मजदूर अधिक घंटों के लिये काम करने के लिये स्वेच्छा से राज़ी हो गये। परन्तु सरकार ने यह देख कर काम के 48 घण्टे लागू कर दिये। ऐसा उचित नहीं है । अधिक समय तक काम करने के लिये उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है । फिर, तालाबंदी के पश्चात् उन्हें रेलवे पास नहीं दिये जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये उनके साथ भी अन्य कर्मचारियों जैसा ही सलूक किया जाना चाहिये ।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

उप रेलवे मंत्री ने कई बार कहा है कि रेलवे कर्मचरियों की सभी श्रेणियों के लिये मजूरी बोर्ड बिठाया जायेगा । अब उनको इस वायदे से पीछे नहीं हटना चाहिये और शीघ्र ही ऐसा एक बोर्ड स्थापित करना चाहिये ।

खड़गपुर में एक स्कूल जिसे रेलवे के कर्मचारी चला रहे हैं, न कि रेलवे विभाग उसमें लग भग 400–500 विद्यार्थी हैं। उनकी मांग यह है कि या तो सरकार उस स्कूल को पूर्णरूप से अपने हाथ में ले ले या फिर उनको भूमि दे दे ताकि वे लोग स्कूल की इमारत बना सकें और इसके लिये बंगाल सरकार से विकास शुल्क ले सकें । रेलवे के लिये इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है ।

उत्तरी बंगाल के लोगों के लिये दार्जिलिंग डाक के अतिरिक्त एक और एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जानी बड़ी जरूरी है । अब जो डाक गाड़ी चल रही है उसमें बहुत भीड़ जाती है और उसमें बैठने की जगह नहीं मिलती । एक और गाड़ी पुरुलिया और हावड़ा के बीच चलाने की आवश्यकता है । इस समय केवल एक गाड़ी रात के समय चलती है और उसमें पूर्व रिज़र्वेशन के बिना स्थान नहीं मिलता । हाल ही में मैं इस गाड़ी पर गया तो मुझे प्रथम श्रेणी में भी स्थान नहीं मिला । फिर रेलवे कर्मचारियों में कुछ मित्रों की सहायता से दो टायर वाले डिब्बे में मुझे स्थान मिल सका । यदि आपके लिये इस समय हावड़ा से बन्देल और तार्केश्वर के लिये अधिक उपनगरीय गाड़ियां चलाना संभव नहीं है तो प्रत्येक गाड़ी में एक एक डिब्बा जोड़ दीजिये ।

हावड़ा–बन्देले और हावड़ा–बर्दवान कोर्ड लाइन पर स्थिति काफी खराब है । पिछले 3–4 महीनों में कई बार गाड़ियां नहीं चली हैं। कभी बिजली का तार चोरी हो जाता है, कभी रेल की पटरी सही हालत में नहीं होती और कभी रेल की ब्रेकें काम नहीं करतीं । सरकार को इन की जांच करनी चाहिये । यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है । उपनगरीय गाड़ियों का समय पर चलना बहुत जरूरी है । क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने काम पर देर से पहुंचेगा तो उसकी नौकरी छूट सकती है । सरकार को सब अड़चनों को दूर करना चाहिये ।

Shri Sheo Narain (Bandi) : In view of the insufficient means of communication in Kashmir it is suggested that a railway line from Madhopur to Vanihal *via* Udhampur should be constructed. More railway lines are necessiated in Tripura and Nagaland as there is the pressure of China in NEFA the present narrow gauge line between Lucknow and Siliguri should be replaced by a double Broad gauge line as the present line is not sufficient to meet the pressing need of the traffic. Something should be done to provide facilities to the passengers of third class. It is difficult to get seating accommodation even in first class. For travelling by Air conditioned first class Members of Parliament have to bear one third fare. Members of Parliament should be given free Air-conditioned first class passes. Officers are allowed to travel by Air-conditioned first class whereas we are not. This differenciation should not be there. After all the dignity of a Member of Parliament is higher than that of any other citizen.

There should be network of Railway in Ghasighat, Manipur and Nagaland. This is the demand of the nation.

A broad-gauge line should be laid in Goa so that wheat can be transported there easily. If considered desirable the inter class should again be introduced for the benefit of the middle income group.

The incidence of chain pulling by students has increased because previously they were given some concessions which have now been stopped. All those concessions should be restored to the students without hitch. Weekly tickets should be issued to them, then there will be no chain pulling.

Khalilabad town in my constituency is developing into a big industrial area. The businessmen coming from distant places have to face a lot of difficulty because the mail and express trains do not shop at these stations. These trains should be made to stop there. There was a first class waiting room at Basti Station. After Independence that was converted into Inspector's quarter. Now there is no first class waiting room. This should be there.

A Harijan boy Shri Ram Lakhan working as a clerk was not considered for promoton to the post of Vigilance Inspector because he was not working in the scale of Rs. 130—300. This is not the sound criterion that you do not trust your own man and take person from outside.

One train coming from Gorakhpur stayes for about half an hour at Magadh. It will be better if it is made to stay for some time at Khalilabad by reducing its stay at Magadh slightly.

Some hon. Members have criticised the rail-road competition. I am in favour of the competition because it will go a long way in eradicating corruptions from the Railway.

Catering conditions are not satisfactory. The food served is not of good quality. Government should see that good stuff is provided for the price charged. If it is not possible contracts should be given to private parties. Arrangement of Mrs. Ishwar Das Ballabh Das was quite satisfactory.

Some 1400 workers of Lucknow have been posted to Gujarat Zone. They are demanding their transfer under the Lucknow Zone. Their case should be given sympathetic consideration.

In the time of Shri Jagjiwan Ram 2-3 officers were dismissed during the strike. Justice has not been done to those officers. They should be reinstated. Their cases should be again looked into.

Shri Baswant (Thana) : The railways were started in this country in the year 1953 and its budget then used to be only of the order Rs. 90 lakh. Now we have railway track of 57,000 Kilometres and the budget gone up to Rs. 660 crores.

It is said that there is a shortage of Rs. 25 crores in the transportation account of the railways. The reason for decline in this income appears to be the rise in transport fares of railways which was done two years back.

The pliferage in the railway departments should be checked and unnecessary expenditure avoided. The reason of theft is the auction of old iron and wooden articles of railways. The contractors who get these articles in auction get permit to remove them outside the railway premises and since they have valid

[Shri Baswant]

permits to remove articles they take away that iron also which is new and received fresh by the railways. The fine imposed by the authorities for delay in removing of auctioned articles is only to the tune of Rs. 50 to Rs. 200. Hence I suggest that old iron should be melted by the railway authorities themselves and may not be auctioned.

I want to make a mention about the condition and overcrowding in the sub-urban railway in Bombay. In August, 1964 the number of monthly passes issued was 2,78,028 whereas for the same month during the year 1962 their number was 2,24,970. In one day about 70,59,946 people travel in this railway. The population of Bombay previously was 43 lakhs whereas now it has increased to 50 lakhs and there are many municipalities in the adjacent colonies. All big factories seen in Maharashtra have generally their head offices in Bombay. The land is very costly in that city and when Government sold some plots it fetched at the rate of Rs. 8000 per square yard. My whole point is that railway is made much use of that. Therefore the only solution is provision of underground railway and this may be done during the Fourth Plan period.

There is need for checking of passengers who travel without tickets as their number is rising day by day.

I may also mention here something about expansion of Bombay city. Mr. S. K. Patil once said that if new colonies are to be built in Bombay they can be done at a distance of 50 miles from the city.

During the Fourth Plan period there is need for provision of electrified train between Berar and Ahmedabad.

The concession of railway travel given to Kisans previously, which has now been withdrawn may be revived. The guides on the railway station should be conversant with the local language.

Now there is a talk of the reorganisation of railway zones. I request that while so doing due consideration should be given to the language of the people I do not want Sholapur to be separated from Maharashtra.

OnWestern Railway there are no stations even as far as 16 miles. This may be looked into and stations should be at nearer distance.

In the end I request that one more express train should be introduced between Bhusawal and Bombay as the passengers are put to much inconvenience due to its absence.

श्री मि० सू० मूर्ति (अनकापल्लि) : मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं कि रेलवे विभाग में सुधार हुआ है। उन्होंने जो क्षेत्रों की योजना बनाई है उससे भी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस क्षेत्र के निर्माण के बारे में इस वर्ष के अप्रैल से लागू करने का निर्णय करदें क्योंकि 1-4-66 से तो चौथी पंचवर्षीय योजना ही आरम्भ हो जावेगी।

जहां तक कार्य का संबंध है, रेलवे मंत्रालय ने प्रशंसनीय कार्य किया है। इन से आय भी बढ़ती जा रही है। एक परामर्श मैं देना चाहता हूं कि आगे से वार्षिक रिपोर्ट में यह भी बता दिया जाये कि भिन्न-भिन्न रेलों में कितने व्यक्तियों ने यात्रा की ताकि प्रत्येक रेलवे की प्रगति का पता चल सके ।

जहां तक अंकापल्ले से ताड़ गुड़ के यातायात का सम्बन्ध है उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। इसके बारे में मुझे कुछ डाक तार भी प्राप्त हुए हैं। व्यापारी लोग रेलवे अधिकारियों को इस सम्बन्ध में पहले से बता भी देते हैं। परन्तु उन्हें रेल के खाली डिब्बे नहीं मिलते हैं। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्य करना चाहिये।

यात्रियों पर किराया बढ़ा दिया गया है परन्तु उन्हें तो उसकी सुविधायें नहीं मिली हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगले वर्ष जब वह किराया बढ़ावें वस इस बात का भी ध्यान रखें।

मैं हर वर्ष थोड़ी दूर पर चलने वाली गाड़ियों के बारे में कह रहा हूं । ऐसी एक गाड़ी तो तुनी से वाल्टेयर के लिये चलायी जावे क्योंकि विशाखापतनम का शहर महत्वपूर्ण होता जा रहा है ।

और सुविधा तो अलग रही कम से कम पीने के पानी की सुविधा तो तीसरे दर्जे के यात्रियों को मिलनी ही चाहियें । नरसा पटनमरोड तथा येलामनचिली स्ट्रेशन बहुत पहले बने थे परन्तु वहां यात्रिमों को धूप से बचने के लिये कोई कुछ भी इन्तजाम नहीं है । मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र को स्वयं दौरा कर के देखें ।

अब मैं दो, तीन और बात कहूंगा कासीमकोटा और कासीन कोटा हाल्ट नाम के दो स्टेशन आनाकापाल्ले के पास हैं। यह एक झंडा स्टेशन है। अब सुनने में आया है कि इसे समाप्त किया जा रहा है। वहां के लोग इस हाल्ट स्टेशन का झंडा स्टेशन में परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं और कहते हैं कि डिविज़नल सुपरनटेंडेंट से इसकी सिफारिश भी कर दी है । यह मामला अब रेलवे बोर्ड या सम्बन्धित रेलवे के जनरल मैनेजर के पास होगा। मैं मंत्री महोदय से इस कार्य को करने की प्रार्थना करूंगा ।

रेल दुर्घटनायें अब कम होती जा रही हैं । परन्तु एक बात अवश्य है कि इन दुर्घटनायें में से दो तिहाई के लिये रेलवे कर्मचारी उत्तरदायी हैं। मुझे पता नहीं है कि यह अधिक भीड़ होने के कारण है या लापरवाही के कारण । इस पर भी ध्यान देना चाहिये ।

गोदावरी पर पुल बनाने के हक में सारा आंध्र प्रदेश है । प्रारम्भ में तो वहां रेल तथा सड़क का पुल बनाने का सुझाव था । परन्तु अब सुनने में आया कि केवल रेल का पुल बनाने के लिये टेंडर लिये गये हैं। आंध्र सरकार ने तो इसके लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था अपने बजट में कर भी है । इसका कुल व्यय 2 करोड़ रूपया आवेगा। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे वित्त मंत्रालय से इसके लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था करावें और वहां रेल तथा सड़क का पुल बन जावे । यह पुल सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है ।]

दांतेवारा–भद्राचलम रोड के बारे में कुछ सर्वेक्षण का आदेश दे दिया है । यह दण्डकारण्य परियोजना के खनिज पदार्थो के पता लगाने के लिये बहुत आवश्यक है । मैं कई बार वाल्टेयर से भद्राचलम होते हुए खजीपेटा तक के सर्वेक्षण के बारे में कह चुका हूं ताकि वहां के खनिज पदार्थो का पता लग सके । मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि यह दोनों क्षेत्र साथ-साथ स्थित हैं। रेलवे मंत्रालय से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान दें ।

[श्री मि० सू० मूर्ति]

येलामनचिली स्टेशन पर पहले डाक लेने आदि का प्रबंध था परन्तु 1960 से यह काय समाप्त कर दिया । वहां के लोगों ने इस रोक के विरुद्ध बहुत बार प्रतिवेदन भेजे हैं और हाल ही में दो दक्षिण रेलवे के जनरल मैनेजर से भी मिले हैं और उसने कुछ वचन भी दिया था परन्तु उसे निभा नहीं पाया । अब लोग इस बारे में सत्याग्रह करना चाहते हैं । परन्तु मैं ने उन्हें कहा कि जब तक मैं रेलवे मंत्री से न मिल लूं वे ऐसा न करें । मैंने मंत्री महोदय को अपनी बात मनवाने का प्रयास भी किया परन्तु सफल न हो सका । मैं डा० राम सुभग सिंह से जो कि उस ओर जा रहे हैं कहुंगा कि वहां जाकर वे या तो वहां के लोगों को अपनी बात से मनालें या उनकी बात मान जावें । मैं फिर मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस ओर ध्यान दें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr] : Mr. Deputy Speaker, I have read the Railway Budget papers minutely. I find a sense of satisfaction also in this. This is the greatest state undertaking and its effect is bound to be felt by other state enterprises. If the Railway Ministry cannot do its work properly, other state undertakings will also fail to do thier work.

We have invested a sum of Rs. 3000 crores and about 13 lakh workers are employed in them. But I am sorry to say that these employees have been deprived of thier fundamental political rights. In all other undertakings which are run on commerical lines the employees are permitted to become members of political parties. Why then there is exception in thier case?

The Railway employees have demanded the formation of a wage board as is the case with other industries. This is a reasonable demand and should be acceded to.

I want to point out another thing which relates to the non-acceptance by the Ministry of Railways to apply the industrial Disputes Act. A discipline code has been framed to keep peace in the industry. The employees want its application to them but the Ministry of Railways has not agreed to it. Whenever there is a dispute the Government wants it to be referred to an arbitrator. Now I want the government to take initiative.

I want that a comprehensive scheme of 25 years for conversion of all small metre gauge railways into broad gauge ones may be formulated by the Railway Ministry and the present Railway Minister may take initiative in it. This scheme should also cover electrification and dieselisation of all railways. This will help the working of our steel plants.

Some concrete step should be taken to increase efficiency in Railways and Railway workshops. There should be an end to the feeling of self-complacency from which the railways now suffer.

About railway passengers I must say that the greatest income which accrues to the railways comes from the passengers who travel in IIIrd class but Government ignores them and always raises thier fares. If you want to create an atmosphere of development in the country, you do away with Ist and 2nd class compartments. Long journey passengers should be given proper amenities. These things will create a sence of sacrifice and equality in the country.

Corruption in the goods department of railways is well known. I want the Minister of Railways to think over this matter.

I want you to have a look at the railway map and you will find that there is no railway line from Bombay to Mangalore. I am not saying it from the point of view of advancing the cause on regional or provincial grounds. Since the present railway minister belongs to that area, I want him to give it more importance. You know there is a railway line from Cochin to Trivandrum which is a small gauge one but there is no line from Trivandrum to Kanya Kumari. I, therefore, request that laying of a railway line on Western Coast should at once be taken in hand. This is important from the point of view of security & industrial development of the nation. In the same manner I want that the small metre gauge lines in Assam in Bihar be converted into broad metre gauge.

The self complacency which appears to be with the government with regard to the question of accidents and irregularities in the department is also desticable. I want the railway minister that if he wants to decrease accidents in railways, he should bring punctuality in their running. I think the money he has spent on the construction of more buildings for railway platforms etc. would have better been used on laying new lines and converting small metre gauge lines into broad metre gauge ones.

There should be a survey for railway line from Sultanpur to Devgarh. There is great inconvenience in railway transport between Kyool and Jamalpur. These trains do not stop at various stations between these two places and they should be made to stop at them. The train which runs from Sahabganj to Jamalpur should be extended upto Kyool.

Regarding suburban railway in Bombay, I would say the two ministers of railways would better realise the difficulties of passengers there if they see for themselves how difficult and rather impossible it is for passengers to board train there. This creates much hardship for the office workers. The only son of one of my friends died in an accident on such a train. Two or three persons daily die like this.

There is a necessity for change in the attitude of the Railway ministry towards its 13 lakh employees. If it is done in a bureaucratic manner, it will bring disgrace to all the public undertakings in India and it will belie those who now say that enterprises in public sector bring social good and efficiency. I therefore want the railway minister to accede to the reasonable and just demands of the employees. In case of divergence of opinion on any dispute between the employees and the administration, the same should be given to an arbitrator.

श्री वीरन्ना गोड़ (बंगलौर) : रेलवे मंत्री महोदय ने जो आशा जनक रेलवे आय-व्ययक प्रस्तुत किया है उसके लिये उन्हें मैं बधाई देता हूं । इससे मूलरूप से रेलवे की आय में 11½करोड़ रूपये की वृद्धि होने की आशा है । अच्छा काम हो, इसके लिये कर्मचारियों को सन्तोषजनक वेतन मिलना चाहिये । । कमचारियों के वेतन इस वर्ष में दो बार बढ़े हैं । बच्चों की स्कूल फीस इत्यादि के रूप में भी उन्हें कुछ रियायतें दी गयी हैं । नयी लाईनें चालू की गयीं, कई लाईनों का विद्युतीकरण किया गया है और लाईनों को दोहरा बनाया गया है ।

मैं मैसूर का प्रतिनिधि हूं । उस क्षेत्र में मेरी रूचि होना स्वाभाविक है । मेरा निवेदन यह है है कि बगलौर–गंटाकल लाईन को तुरन्त बड़ी लाईन में बदल दिया जाना चाहिये । इसके बिना

[श्री वीरन्ना गौड़]

मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है । माल यातायात में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । बंगलौर सालम लाईन के निर्माण में भी शीघ्रता की जानी चाहिये । चामराज-नगर–सादामंगलम लाईन को शीघ्र बनाना चाहिए । इसकी ओर मंत्री महोदय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

रेलभाड़ा और माल भाड़ा बढ़ाने का जहां तक सम्बन्ध है मेरा निवेदन यह है रेलवे मंत्री इस दिशा में यह निणय करने में ठीक ही हैं । यह गलत है कि वह अफसरों के हाथों में खेल रहे हैं । मैं रेलवे बजट का स्वगत करता हूं ।

Shri Lahtan Chaudhri : There is a general satisfaction regarding this Railway Budget which is before the House. There is also a sense of satisfaction regarding the work done by the Railway Ministry in the past and its plans for the future. It is felt that the budget, indicative of improvement and a plan for further improvement and increase in revenue is satisfactory. But I feel that there is still some scope for greater progress and in this connection I put forward a few suggestions.

There is a general complaint that goods arrive very late through the railway. Sometimes it takes 145 days for the goods to reach Bombay from Calcutta a d 115 from Calcutta to Sasram, 93 days from Sasram to New Delhi. This has shaken the confidence of the people in the efficiency of the Railway. My Submission is that the speed of goods train should be improved and people should be ensured of the timely delivery of their goods. Much time is taken by the railways even for the transportation of goods including the essential commodities and even the parcels. I think if the speed of goods trains is improved, their utilisation and income can be sufficiently increased.

Similarly the complaint is that the speed of the passenger train is very slow. There is complete lack of facilities which are necessary for the passengers in the trains. I am also of the opinion that the fare for a distance of twenty five Kilo meters should not be increased. If we need money the ticketless travelling should be properly checked. Railway employees have a great hand in this crime. It is generally seem that even in the magistrial checking only the poor people are caught, literate people some how manage to come out of this trap. Railway Ministry should look into this evil seriously.

Now I come to the problem of my constituency. There is only fifty-two miles of railway line in the sahars district with a population of twenty lakhs with the construction of Kosi barrage, there is a great scope of development. The area is producing 1/12th of the total production of Jute in the country, a part of which is also exported. The farmers in this area are experiencing great difficulties and hardships in getting the transport for their produce. I therefore urge that the railway lines should be extended in the area. The line between Supol and Partapgarh via Bhavatiyahi, should be laid again. Bhavatiyahi should be linked with Nirmali and connected with the lateral road, which is now under construction. This will save much time of the passengers.

Shrimati Jamuna Devi (Jhabua): The Railway Budget of this year of 1965-66 has been presented before the House with great care. The speech of Railway Minister is also very encouraging. I may hope that the Construction

of the railway lines mentioned in the Budget Speech of the honourable Minister will be completed during the course of the year. I would like to urge that every effort should be made by the Railways to improve the goods Transport. This is very essential, if you want to win the confidence of the people.

Railway Administration is in the hands of big officers. There are certain loopholes and short comings in the administration which must be looked into. The defects should be removed and effective Steps should be taken to strengthen the administration. At the Same time Railways should pay special attention to the Construction of railway lines in the backward areas. If we desire to develop these areas we will have to attend to it. As the development of these areas is not possible unless railway lines are laid there.

The areas like Mhow, Indore and Ujjain should not be ignored. There should be a net work of railway lines in those areas. I also want to stress that a broad-gauge line linking Delhi with Mhow, Indore, Ujjain and Nagda etc should be immediately constructed. The railway line linking Indore and Dohad should be constructed at the earliest possible, so that the industrial area may be developed.

Also the efforts should be made to find out the reasons for the non-cooperative attitude of the low-paid railway employees towards the working of the railways. A feeling should be created amongst the railway employees that the service of the railway is the service of the nation as well as of themselves.

The ladies compartments should be made more spacious. There should be separate two-tier coaches for the ladies. It should be tried to provide the increased facilities to them. We should get good food while travelling. Government should look to this aspect of the thing. I hope the suggestions I have placed before the Honourable Minister will be sympathetically looked into.

Shri Maurya (Aligarh) : It has been stated that the Railway income is 660 crores of Rupees. The deficiency is of about 8 crores of rupees which is calculated to be 1·25 percent. In goods traffic the deficiency is of 25 crores of rupees. The railway passenger fares have been increased to the extent of 16 crores of rupees. There has been a fall in the goods traffic. I am of the opinion that it is due to the failure of our plans and the competition between the rail and road trasnport. It has been observed that the Railways are not able to transport goods as efficiently as the road transport has done during past few years. I feel very sorry to state that the low-rated traffic is on the increase and the high rated traffic is on the decrease.

Similarly the increase in the passanger fare is highly distressing in the days of rising prices. Facilities which have been given to the third class passengers are not sufficient. There is a lot of over-crowding in the third class compartments. I shall strongly urge that efforts should be made to remedy the situation. It has been stated in the Audit Report that the amount allocated for providing facilities to the passengers have not been fully untilised. I think it should be clarified on what items the balance have been spent.

There is a lot of corruption now-a-days in the Railways. People get jobs in the Railways by giving illegal gratifiction. There are complaints regarding the late-running of trains. It is a fact that late running of trains for the last sometimes is on the increase. Catering arrangements at the Railway Stations and in the trains is very defective. Number of accidents have also gone very high.

[Shri Maurya]

I feel it is due to longer hours of duty of the drivers. The drivers should be made to work only for the normal hours of duty. It is also bad to exploit the casual labourers. Their condition is very deplorable.

I may submit that it is regretted that although the constitution has provided for collective responsibility of the Ministry, but we see that the policy of Railway Ministry change with the change of the Minister. There is also a complaint that the Scheduled castes and the Scheduled Tribes are not getting their due in the services of the railways.

The employees of the railways who help the big contractors to get big contracts should be seriously dealt with. I also feel that this Budget will not give any relief to the poor.

[श्री सोनावने पीठासीन हुये
Shri Sonavane in the Chair]

श्री वासप्पा (तिपतूर) : मैं हसन–मंगलूर रेलवे का उल्लेख कर रहा था । मेरा निवेदन यह है कि हसन–मंगलूर रेलवे लाईन का निर्माण तेजी से किया जाना चाहिये । रेलवे मंत्री महोदय को इस दिशा में किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए । इसी तरह मंगलूर–पत्तन तक 20 लाख टन लौह इस्पात पहुंचाना सम्भव हो सके, उस दृष्टि से इस लाईन का बहुत ही महत्व है इसके अतिरिक्त और लौह अयस्क निकालने का भी प्रश्न है । अधिक लौह अयस्क निकालने तथा अधिक विदेशी विनिमय करने के लिए हमें किसी न किसी समय हास्पेट क्षेत्र से मंगलूर तक बड़ी लाईन बनानी ही होगी और बनानी चाहिए भी । मेरा निवेदन यह है कि यह बड़ी लाईन केवल हसन–मंगलूर के बीच ही नहीं होनी चाहिए बल्कि करवार पत्तन के विकास के लिये भी इसे करवार से भी मिलाया जाना चाहिए ।

अब मैं मैसूर तथा हुबली खंडों का उल्लेख करना चाहता हूं । मेरा निवेदन यह है कि इन खंडों में अधिक सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । उस हालत में जब कि उस क्षेत्र में एक नया खंड–दक्षिण केन्द्रीय खंड बनाने का भी प्रस्ताव है । इन दोनों खण्डों को बनाये रखना चाहिए विशेष रूप से जब लोग चाहते हैं कि इसका मुख्य कार्यालय हुबली में हो । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि मंगलौर और पूना के बीच तिपतूर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी बनाने की बहुत आवश्यकता है । इसके निर्माण के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए गाड़ियों के पटरियों से उतर जाने का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिए यह जरूरी है कि हुबली–मंगलौर रेलवे लाईन को सुदृढ़ बनाया जाये ।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि चालू वर्ष में वस्तु भाड़े से आय 25 करोड़ रुपये कम क्यों है । यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाड़े में बुद्धि से वस्तुओं के मूल्य में भी बृद्धि हो सकती है और इससे मुद्रास्फीति की पूरी संभावना हो सकती है । मेरा अनुरोध है कि रेलवे मंत्री को दुर्घटनाओं, भीड़–भाड़, गाड़ियों के देर से चलने और टिकटों के संरक्षण में चोर बाजारी की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए । लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर भी ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए । इससे रेलवे मंत्री के हाथ मजबूत होंगे और रेलवे के कार्य में सुधार होगा ।

Shrimati Shakuntala Devi (Banka) : I support the Budget presented by the Railway Minister, but I am not in favour of increase in Railway fares and freight. In these days of high prices it will not yield good results. The railway authorities should curtail their unnecessary expenditure.

Lady passengers should be provided more facilities. There is no first class ladies compartment for them. It causes great inconvenience. Some times they are given upper births. which are not convenient for them. The lady passengers has increased considerably. I suggest that a first class general compartment should be provided in all the trains.

The catering arrangements on trains is not adequate and suffers from many shortcomings. No attention is paid to cleanliness. I suggest that proper attention may be paid to these essential things.

Bhagalpur-Mandar line should be extended upto Madhupur. It will help the peopleof the area a great deal and will add to the revenues of Railways. The building of Bhagalpur station has recently been constructed but the sanitation arrangement is not adequate. Bakhatiarpur is an important reailway station. I request that all mail trains should stop there.

As has been said by other hon. members from Bihar, I also request that a division of Railway Service Commission may be opened in Bihar. It will help people in getting employment.

श्री शिंकरे (मारमागोंआ) : सभापति महोदय, मैं श्री संथानम के एक लेख की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह उन्होंने 24 फरवरी के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में लिखा है । इसमें उन्होंने रेलवे के वस्तु भाड़े तथा किराये में बृद्धि की आलोचना की है । इस बृद्धि से अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । ऐसा उन का विचार है । यह बात सच भी जान पड़ती है । कांग्रेस पार्टी में ऐसे आदमी भी हैं जो वास्तविक स्थिति को जानते हैं । जब सरकार पहले ही दास आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 600 रूपये तक वेतन पाने वालों को महगाई भत्ता दे रही है तो किराये के बढाने से इसी वर्ग वालों को कठिनाई होगी । यही लोग तीसरे दर्जे में यात्रा करते हैं । मेरा रेलवे मंत्री से निवेदन है कि तीसरे दर्जे का किराया बढ़ाया नहीं जाये ।

1955 में भारत सरकार ने गोआ पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये थे परन्तु सरकार को क्या मालूम नहीं था कि गोआ एक बन्दरगाह है । गोआ समुद्र द्वारा व्यापार आदि विदेशों से कर सकता है । अत: वह आर्थिक प्रतिबन्ध असफल रहे ।

उन दिनों गोआ रेलवे के बहुत से राष्ट्रवादी कर्मचारी भारत में दक्षिण रेलवे में सेवा के लिये आ गये थे परन्तु अब गोआ स्वतंत्र होने के पश्चात जब वह लोग वापिस गोआ में गये हैं तो उनकी वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है । उनको रहने के लिये क्वाटर भी नहीं दिये गये । गोआ में ही रहने वाले कर्मचारियों को गोआ भत्ता भी मिलता है । उन लोगों ने रेलवे बोर्ड तथा जनरल मैनेजर को कई अभ्यावेदन दिये हैं माननीय मंत्री को भी उनकी प्रतिलिपिया मिली होंगी । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में पुछताछ करें और आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : इस बार रेलवे के भोजन व्यवस्था विभाग को प्रथम बार लाभ हुआ है । यद्यपि लाभ अधिक नहीं फिर भी लाभ हुआ है ? गर सरकारी क्षेत्र के केदार बहुत अधिक लाभ उठाते हैं । उनको अधिक लाभ होने का कारण यह है कि वे लोग बहुत अच्छी

[श्री सुबोध हंसदा]

प्रकार की खाने की चीजें यात्रियों को देते हैं । परन्तु यदि आप रेलवे के इस विभाग द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं को देखें तो आप देखेंगे कि ये खाने की वस्तुएं बढ़िया किस्म की नहीं होती । रेलवे प्रशासन को भोजन व्यवस्था में सुधार करना चाहिये ।

रेलवे मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वह रेल किराये तथा वस्तु भाड़े में वृद्धि करके 36.5 करोड़ रूपये का राजस्व कमाना चाहते है । मैं इस के विरूद्ध हूं । पिछले वर्षों में यात्रियों के भाड़े से आमदानी में क्रमश: प्रति वर्ष वृद्धि होती रही है । यह वृद्धि इस कारण हुई है कि यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होती रही है । रेलवे मंत्री राजस्व को 221 करोड़ रूपया तक बढ़ाना चाहते हैं जबकि इस समय यह 219 करोड़ रूपये है । अन्तर केवल 3 करोड़ रूपये का है । इस अन्तर को आप बिना टिकट चलने वाले यात्रियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करके पूरा कर सकते हैं । रेलवे स्टेशनों के निकट कि भूमि को लोग बिना किसी किराया दिये निजी प्रयोग में लाते हैं । इस पर रेलवे प्रशासन वाले किराया ले सकते हैं और अपने राजस्व को बढ़ा सकते हैं । अत: यात्रियों को किराये बढ़ाये जाने में कोई, यक्तिसंगत बात मालूम नहीं होती है ।

रेल गाड़ियों में भीड़ की भी वही दशा है । यह कहा जाता है कि यह कम हो रही है परन्तु बास्तव में ऐसी बात नहीं । रेल गाड़ियों की संख्या में बहुत कम बढ़ौतरी हुइ है। मैं ने लोगों को रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते देखा है । यह इसलिये कि रेल गाड़ियों में स्थान नहीं होता । मैंने यह बात क्षिदणपूर्व रेलवे में विशेष रूप से देखी है । इस रेलवे (जोन) में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये । मेरा सुझाव है कि गोमो से खड़गपूर होते हुए हावड़ा तक एक रेलगाड़ी चलायी जाये । एक जनता रेलगाड़ी हावड़ा से नागपुर तथा एक रेलगाड़ी हावड़ा से वाल्टेयर तक चलायी जाये ।

हल्दिया लाइन बहुत समय से रुकी हुई है । रेलवे प्रशासन का ख्याल है कि हल्दिया बन्दारगाह अभी नहीं बन रहा है परन्तु अब विश्व बैंक ने इस पत्तन के बनाने की स्वीकृति दे दी है अत: मेरा निवेदन है कि इस लाइन का निर्माण शीघ्र किया जाये ।

रेलवे प्रशासन में अन्य सब विभागों से अधिक कर्मचारी काम करते हैं । इस में लगभग 13 लाख लोग काम करते हैं । सरकार अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से बहुत अधिक सहानभूति का व्यवहार करती हैं रेलवे प्रशासन में इस को संख्या निर्धारित प्रतिशत के अनुसार नहीं । इस ओर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*)

चतुर्थ श्रेणी में इन जातियों के लोगों की संख्या अधिक है । इस का कारण यह है कि इस श्रेणी का काम करने के लिये अन्य वर्गों के लोग तैयार नहीं होते । यह बात ठीक है कि विभिन्न पदों के लिये उचित लोग उपलब्ध नहीं हैं यह सच है कि उच्च अधिकारियों के पदों तथा तकनीकी पदों के लिये अनुसूचित जातियों के लोग नहीं मिलते । परन्तु इन के लिये प्रशिक्षण केन्द्र भी तो नहीं खोले गये हैं । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये । द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पदों के लिये भर्ती के समय ही इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

कुछ समय पहले संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य अनुसूचित जाति के थे। उस समय इस जाति के बहुत लोगों को लिया जाता था परन्तु अब फिर उन की संख्या में कमी हो गई है। जहां विभिन्न विभागों में इन लोगों की पदोन्नति का प्रश्न है उस में भी इन से अच्छा बरताव नहीं किया जा रहा। सरकार को एक जांच समिति नियुक्त करनी चाहिये जो इस बात का पता चलाये कि कि वास्तविक स्थिति क्या है?

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन 731 शिक्षा संस्थाओं को चला रहा है। इन की संख्या में वृद्धि होनी चाहिये। रेलवे प्रशासन को यह अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये। खड़गपुर के बारे में मझे जानकारी है। वहां एक लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी रहते हैं। वहां पर एक स्कूल चल रहा है। रेलवे प्रशासनों ने स्कूलों को चलाने के लिये अपने मालगोदामों के इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। हम रेलवे प्रशासन से अपील करते हैं कि स्कूल के लिये उचित स्थान दें।

Shri Jag Dev Singh Sidhanti (Jhaggar) : Sir there are only two trains available between Delhi and Jind. This number is very inadequate keeping in view the traffic on this line. This should be looked into and the number of trains should be increased. This area is famous for providing soldiers for army. A good number of army men travel in this area. A deputation from this area has recently met Shri Sham Nath, Deputy Minister in the Ministry of Railways. He has promised a sympathetic consideration of our demands.

On Mathura line there is a railway station called Asawti. It is near Palwal. There is not adequate arrangement for drinking water on this station. It causes great inconvenience to passengers there. The condition is worse during the summer season. I request that necessary arrangements may be made on this station.

Proper attention to Hindi is not being paid by the railway authorities. Corruption is rampant in railways. You go tc Delhi Railway station and see for yourself. The staff pays a lukewarm attention. Officers at the lower level do not care for the general public. Parcels addressed in Hindi are not accepted. A man who speaks Hindi is not attended to properly. Students, who travel by trains should be provided more facilities. I congratulate the Railway administration on the decision to expend the Railway service from Morvi to Tankara.

I request that a railway line may be laid from Panipat to Rewari. This link will help in many ways. It wil be beneficial to Railway administration also. But I am told that it is feared it would have adverse effect on road transport. We should keep in view the interests of general public instead of only a few transport owners. Panipat should be linked with Gohana and from that place to Rohtak there is already railway line. From Rohtak to Rewari a line may be laid. I suggest that railway track should be doubled, where it is possible. Effort should be made to see that passenger trains are not unduly delayed. As the hon. lady member has said more facilities should be provided to lady passengers. I find that class of a compartment is shown in English language. I suggest that it should be indicated in Hindi. You have provided waiting rooms for first class and second class passengers. Similarly there should be arrangements for passengers of third class, also.

Necessary arrangements for catering and drinking water may be made at big stations like Rewari.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : में रेलवे मंत्री को रेलव की क्षमता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिये बधाई देता हूं। में रेलवे मंत्री का विशेष रूप से कृतज्ञ हूं कि उन्होंने सिलिगुड़ी से जोगीघोपा तक बड़ी लाइन की रेल के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है और रोंगिया–रोनगपाड़ा से मारकांगस्लेक तक छोटी लाइन का विस्तार कर दिया है। सिलीगुड़ी–जोगीघोपा रेल का अन्त नदी के किनारे पर होता है। हम नहीं चाहते कि राज्य की पहली बड़ी लाइन की रेल का अन्त एक अन्ध बिन्दु पर है। इस का विस्तार गोहाटी तक होना चाहिये जोकि राज्य का महत्वपूर्ण केन्द्र है। जब रेलवे मंत्री उस राज्य में गये थे तो इस प्रस्ताव से सहमत थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस को करवा देंगे। और मुझे आशा है कि वह अपना वचन निभायेंगे और इस रेल का विस्तार गोहाटी तक कर देंगे।

जहां तक मारकागस्लेक का सम्बन्ध है यह भी लोहित नदी के किनारे पर अन्ध बिन्दु है। हम चाहते हैं कि इस रेल-पर्यन्त का दक्षिण किनारे की रेल से सम्बन्ध स्थापित किया जाय। यदि यह हो जाय तो मार्ग पूर्ण हो जायेगा और आपात स्थिति में यातायात में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उत्तर किनारे की और दक्षिण किनारे की दोनों रेलें ऐसे क्षेत्र से गुजरती हैं जहां नागाओं ने बहुत उत्पात मचा रखा है। यदि दोनों किनारों में सम्बन्ध स्थापित हो गया तो यातायात को हर समय चालू रखना सम्भव हो जायेगा। यदि उत्तरी किनारे की लाइन टूट जाये तो यातायात को दक्षिण किनारे को ओर मोड़ दिया जा सकता है। और उसी प्रकार यदि दक्षिण किनारे की लाइन टूट जाये तो यातायात को उत्तरी किनारे की ओर मोड़ा जा सकता है।

यह आम शिकायत है कि लोहे, इस्पात, सीमेंट और कभी कभी खाद्य वस्तुओं, जैसे नमक जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों के संचलन के लिए भी माल डिब्बे नहीं मिलते हैं। माल डिब्बों के अभाव के कारण आसाम में चाय के बागानों के लिये उर्वरक सिन्दरी और अन्य उत्पादन केन्द्रों में रुके हुए हैं। चाय बागानों के मालिक बहुत चिन्तित हैं क्योंकि उर्वरकों को डालने का समय समाप्त हो रहा है। मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह आसाम को शीघ्र उर्वरक पहुंचाने के लिये माल डिब्बों का प्रबन्ध करें।

जहां तक गाड़ियों में अधिक भीड़ होने का सम्बन्ध है, देश के जिस भाग से मैं आ रहा हूं वहां लोगों को खड़ होने का स्थान भी नहीं मिलता। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उत्तरी और दक्षिण किनारे के लिये एक एक और गाड़ी चलाई जाए। और दूर के यात्रियों के लिए एक द्रुत गति वाली गाड़ी चलाई जाये।

रेल के भाड़ में जो बढ़ोतरी की गई है उससे औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन परिव्यय में और वृद्धि हो जायेगी और इसके फलस्वरूप इन के मूल्यों में भी वृद्धि हो जायेगी। इससे मुद्रा स्फीति भी बढ़गी और उन वस्तुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन को विश्व की निर्यात मण्डियों में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। यह बहुत विचित्र बात है कि यद्यपि उत्तर-पश्चिमी रेल चाय उत्पादक क्षेत्रों में से गुजरती है फिर भी बहुत कम चाय रेल द्वारा भेजी जाती है। परन्तु अब आसाम से कलकत्ता तक चाय के लिये साप्ताहिक विशेष गाड़ी चलाने के कारण अब चाय काफी मात्रा में रेल द्वारा भेजी जाने लगी है। और मैं रेलवे मंत्री से यह भी प्रार्थना करूंगा कि चाय के वहन भाड़े में कुछ रियायत करें ; और इससे न केवल रेलवे की आय में वृद्धि होगी बल्कि अधिक विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी।

जो हर वर्ष किराये में थोड़ी सी वृद्धि की जाती है, पिछले दस वर्षों में कुल मिला कर 30 प्रतिशत हो गई है । इस से कम आय के लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा है जिन को अपने काम के लिये थोड़े थोड़े फासले पर रोज़ जाना पड़ता है । मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि कम से कम मानवता के नाते, 50 किलो मीटर के फासले के लिये किराये में वृद्धि न करें ।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र में रेलों के चलने का सम्बन्ध है, वह लोग रेल के पुराने इंजन प्रयोग कर रहे हैं और यात्रियों की सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते । मुझे आशा है कि सरकार यथासंभव शीघ्र उन रेलों को अपने हाथ में ले लेगी ।

वर्ष 1963-64 के लेखा प्रतिवेदन में 1.58 करोड़ रुपये के निष्फल व्यय का उल्लेख है । यदि माननीय मंत्री बिना टिकट के यात्रा, रेलवे सम्पत्ति की चोरी और ठेके में भ्रष्टाचार से होने वाली हानि को रोकने का प्रयत्न करें, तो मुझे विश्वास है कि वह किराये और भाड़े में कुछ रियायत दे सकेंगे ।

रेलों में स्थान की कमी के कारण लोगों को तेज़पुर से गोहाटी तक आने के लिये बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । हमारी यह प्रार्थना है कि बरौनी, लखनऊ और कलकत्ता के लिये गाड़ियों में विशेष डिब्बों का प्रबन्ध होना चाहिये । जब रेलवे मंत्री आसाम के दौरे पर गये थे तो सिबसागर के लोगों ने उनको एक अभ्यावेदन दिया था । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर शीघ्र ध्यान देंगे ।

श्री मुहम्मद इलयास (हावड़ा) : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि रेलवे से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये रेलवे सतर्कता विभाग और रेलवे प्रशासन सक्रिय कार्यवाही कर रहा है । परन्तु रेलवे में भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaya : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री मुहम्मद इलियास : मेरा घर शालीमार गोदाम के बहुत निकट है । और मैं बचपन से देख रहा हूं कि दिन दहाड़े वहां से ट्रकों में सामान भर कर ले जाया जाता है । यह सब कर्मचारियों की सांठ गांठ से होता है । हमने इस सम्बन्ध में रेलवे संरक्षण दल को शिकायत भी की थी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

जो कोई भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता है उसको रेलवे प्रशासन द्वारा बहुत परेशान किया जाता है । मैं इस सम्बन्ध मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । लिलुआ वर्कशाप, जो रेलवे की बहुत बड़ी वर्कशाप है, वहां दिन दहाड़े गांजा, अफीम और शराब जैसी निषिद्ध वस्तुयें बेची जाती हैं । रेलवे के ईमानदार कर्मचारी श्री आशुतोष बनर्जी ने राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री और रेलवे प्रबन्धक को इन समाज विरोधी तत्वों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लिखा है और यह भी लिखा है कि कई उच्चाधिकारी भी इसमें शामिल हैं । उसकी इस कार्यवाही के कारण बिना जांच किये उस के विरुद्ध आरोप-पत्र बनाया गया और उसे एक दम सेवा से हटा दिया गया । उस ने यह भी लिखा

[श्री मुहम्मद इलियास]

है कि यदि वह अपना आरोप सिद्ध न कर सका तो उस को सेवा से हटा दिया जाय, उस की सारी सम्पत्ति छीन ली जाय और उसे 12 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाय । मैं इस का एक भाग पढ़ना चाहता हूं :

> "मैंने 10/19-11-60 को रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर करके रेलवे अधिकारियों को यह चुनौती दी थी कि जो मेंने आरोप लगाये हैं यदि में उनको सिद्ध न कर सकूं तो मुझे सेवा से हटा दिया जाय, में एक हज़ार रुपये का जुर्माना दूंगा और 12 वर्ष का कठोर कारावास भुगतूंगा । 23-10-61 को मेंने फिर लिखा कि यदि में अपने आरोपों को सिद्ध न कर सका तो मेरी सारी पैतृक सम्पत्ति छीन ली जाय और 10 हजार रुपये का जुर्माना देने को तैयार हूं । परन्तु मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की गई ।"

रेलवे अधिकारियों ने उसकी चुनौती स्वीकार करने के बजाये उसे सेवा-च्युत कर दिया गया । में उसे सभा-पटल पर रख रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । आप इसे मंत्री महोदय को दे दें ।

श्री मुहम्मद इलियास : में इसे मंत्री महोदय को दे रहा हूं ।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में रेलवे द्वारा नियोजित 30 लाख कर्मचारियों के कल्याण के सम्बन्ध में कहा था । परन्तु उन्हों ने 50 लाख आकस्मिक श्रमिकों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा । यह श्रमिक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ? । यदि यह लोग उचित ढंग से कार्य न करें तो शायद रेलवे विभाग का कार्य इतनी अच्छी प्रकार न हो । परन्तु इन से दासों की तरह काम लिया जाता है । इन को 27 से 50 रुपये के वेतनक्रम में वेतन दिया जाता है जिसमें निर्वाह करना बहुत कठिन है । यह लोग प्राय: अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से आते हैं । अत: उन को संगठित रूप से इन चीजों का विरोध करना नहीं आता । हाल ही में रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र में यह आदेश जारी किये थे कि 90 दिन से अधिक सेवा काल वाले व्यक्तियों को अस्थायी घोषित किया जाय । परन्तु विभिन्न स्थानों पर रेलवे अधिकारी 90 दिन का सेवा काल पूरा नहीं होने देते । उन को 2 महीने और 29 दिन काम करने दिया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है । इस प्रकार उनको अस्थायी कर्मचारी नहीं बनने दिया जाता । परन्तु यदि कर्मचारी कुछ घूस दे सके तो उसे तुरन्त अस्थायी कर्मचारी के रूप में ले लिया जाता है । इस प्रकार रेलवे बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है । यदि आकस्मिक श्रमिकों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान न दिया गया तो शायद एक दिन वह विद्रोह कर बैठें ।

मैं रेलवे प्रशासन में बिजली लगाने के काम में लगे कर्मचारियों की कठिनाइयां बताना चाहता हूं । जैसे ही एक परियोजना पूरी हो जाती है तो उन को निकाल दिया जाता है । जब कोई नई परियोजना चालू होती है तो फिर से नई भरती शुरू की जाती है और पहली परियोजना से निकले हुए कर्मचारियों को नहीं लिया जाता । मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह आकस्मिक कर्मचारियों की समस्या की ओर अधिक ध्यान दें ।

मैं छोटी रेलों की समस्या की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह गाड़ियां 90 वर्ष पुरानी हो गई हैं । बंगाल की छोटी गाड़ियों के मालिक मेसर्ज़ मार्टिन बर्न बहुत लाभ उठा रहे हैं फिर

भी सरकार उनको लाखों रुपया अर्थ सहायता दे रही है । सरकार को इन को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । पिछले रेलवे मंत्री श्री जगजीवन राम ने इस सभा में आश्वासन दिया था कि इन छोटी रेलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी । परन्तु हमें पता नहीं कि उस समिति का क्या हुआ । यदि इनको सरकार अपने हाथ में ले ले तो सरकार को बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हुगली और हावड़ा जिलों में संचार का और कोई साधन नहीं है । इस युग में भी यह रेलें दस मील प्रति घंटा की गति से चलती हैं जिससे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । कलकत्ता की यातायात समस्या को वृत्ताकार रेल द्वारा ही सुलझाया जा सकता है । रूरकेला और भिलाई में इस्पात के कारखानों के निर्माण के कारण हावड़ा और बम्बई के बीच यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है ; इसलिये तीन वर्तमान गाड़ियों के अतिरिक्त दो और गाड़ियां चलाई जानी चाहिएं । जब से सरकार ने खान पान को विभागीय बना दिया है उसमें बहुत सुधार हो गया है । जबकि इसमें रेलवे को अभी तक हानि हो रही थी, इस वर्ष कुछ लाभ हुआ है । यदि प्रबंध में और सुधार हो सके तो विभागीय खान पान से यात्रियों को अधिक सुविधा होगी और सरकार को भी लाभ होगा । खान पान विभाग के कर्मचारियों को ठेके के बजाय वेतन के आधार पर रखना चाहिये । और इन को बोनस भी मिलना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि गाड़ियों की गति बढ़ाई जा रही है परन्तु यह सब का अनुभव है कि गाड़ियां समय पर नहीं चलतीं । यह एक बहुत अच्छा सुझाव है कि सरकार गाड़ियों की गति 70 मील प्रति घंटा तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है । परन्तु जिस प्रकार रेलवे प्रशासन यह कार्य कर रहा है मुझे आशा भी नहीं कि यह कमी पूरी होगा । तीसरी श्रेणी के यात्रियों के किराये बढ़ाने के निश्चय का विरोध करता हूं । मैं श्री त्रिदिब कुमार चौधरी के सुझाव का समर्थन करता हूं कि रेलवे बोर्ड को समाप्त कर दिया जाव । रेलवे बोर्ड रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । रेलवे मंत्रालय, विभागों की सहायता से इस बड़े संगठन को बड़ी सुविधापूर्वक चला सकता है ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 9 मार्च, 1965/18 फाल्गुन, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 9, 1965[Phalguna 18, 1886 (Saka)

GMGIPND—LSIII—220(Ai)LS—3-7-65—600.